यूनियन धारा
Union Dhara

जिल्द. 48, सं. 3 VOL.XXXXVIII NO. 3, मुंबई जुलाई-सितंबर, 2023

एम.एस.एम.ई. विशेषांक
SPECIAL ISSUE ON M.S.M.E.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

गृह पत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

यूनियन धारा
Union Dhara

प्रकाशन तिथि : 14.11.2023

संरक्षक Patron

ए. मणिमेखलै A Manimekhalai
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

प्रधान संपादक Chief Editor

अरुण कुमार Arun Kumar
महाप्रबंधक (मा.सं.) General Manager (HR)

संपादकीय सलाहकार Editorial Advisors

ए. के. विनोद A. K. Vinod
मुख्य महाप्रबंधक CGM

शैलेश कुमार सिंह Shailesh Kumar Singh
मुख्य महाप्रबंधक CGM

योगेंद्र सिंह Yogendra Singh
मुख्य महाप्रबंधक CGM

रामजीत सिंह Ramjeet Singh
सहा. महाप्रबंधक (रा.भा.) AGM (OL)

संपादक Editor

गायत्री रवि किरण Gayathri Ravi Kiran
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.) Chief Manager (OL)

संपादन सहयोग Editorial Support

नितिन वासनिक Nitin Wasnik
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Asst. Manager (OL)

जागृति उपाध्याय Jagriti Upadhyay
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Asst. Manager (OL)

गृह पत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

अनुक्रमणिका Contents

- परिदृश्य 1
- संपादकीय 2
- हार्दिक शुभकामनाएं 3
- भारतीय अर्थव्यवस्था और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र 4-5
- एम.एस.एम.ई. भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी 6-7
- एम.एस.एम.ई.: चुनौतियां और समाधान 8-9
- शिखर की ओर / शुभमस्तु 10
- एम.एस.एम.ई.: विकास का प्रमुख कारक 11-12
- एम.एस.एम.ई. : नवीनतम रुझान एवं भविष्य 12-13
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. : एम.एस.ई. क्षेत्र की वृद्धि और विकास का इंजन .. 14-15
- आयात पर निर्भरता कम करने में एम.एस.एम.ई. की भूमिका 16-17
- स्वतंत्रता दिवस समारोह 18-19
- पारंपरिक उद्योगों का महत्व 20-21
- एम.एस.एम.ई.: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण का उपाय ... 22-23
- एम.एस.एम.ई. : भारतीय दृष्टिकोण 24
- M.S.M.E. : An Indian Perspective 25-27
- सीएसआर गतिविधियां 28-29
- MSMEs : Challenges and Solutions 30-31
- M.S.M.E. : A Major Driver of Growth 32-34
- M.S.M.E. AND STARTUPS 35
- सेंटर स्प्रेड 36-37
- Role of MSMEs in Indian Economy 38-40
- Continued Digital adoption under M.S.M.E. 41-42
- M.S.M.E. : Latest Trends and Road Ahead 43-44
- M.S.M.E.: Way Towards Industrialization of Rural and Backward Areas 45-46
- प्रतियोगिता/परिणाम 47
- काव्यधारा 48-49
- यू-जीनियस 50-51
- Face In UBI Crowd 52-53
- First Loss Default Guarantee 54-55
- Know Your Coin 56-57
- Udupi Sri Krishna Temple 58-59
- सेवानिवृत्त जीवन से 60
- हमें गर्व है / व्यंजन 61
- समाचार 62-71
- आपकी पाती 72

ई-मेल E-mail: uniondhara@unionbankofindia.bank
gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank
Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

यूनियन धारा में प्रकाशित लेख आदि में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

The views expressed in the articles published in Union Dhara are solely that of the author and do not necessarily reflect the views of the management.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित.
Published by Union Bank of India for internal circulation

परिदृश्य
PERSPECTIVE

प्रिय यूनियनाइट्स,

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 'यूनियन धारा' का वर्तमान संस्करण भारत में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को कवर कर रहा है. मुझे उम्मीद है कि यह अंक जानकारी से भरपूर होगा तथा एम.एस.एम.ई. और भारत के विकास को आगे बढ़ाने में इसके महत्व पर अच्छी संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा. प्रत्येक अंक में ऐसे जीवंत मुद्दों के संकलन के लिए मैं टीम 'यूनियन धारा' की सराहना करती हूँ.

हमारे देश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, एम.एस.एम.ई. उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में लगभग 63 मिलियन उद्यम शामिल हैं, जो भारत की जीडीपी में 30%, विनिर्माण में 45%, निर्यात में 40% योगदान देते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और बाजार संपर्क तक पहुंच सहित एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है. सरकारी नीतियां और वित्तीय संस्थानों का समर्थन एम.एस.एम.ई. के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं, जो अंततः एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देता है.

देश की प्रगति के साथ, एक सुव्यवस्थित वित्तीय क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि एम.एस.एम.ई. सहित समाज के सभी क्षेत्रों तक व्यापक आर्थिक विकास के लाभ पहुंचें. यह समग्र दृष्टिकोण एक गतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करता है, जो निरंतर प्रगति और समृद्धि की नींव रखता है.

हमारा बैंक एम.एस.एम.ई. के विकास को सुविधाजनक बनाने के अनुरूप वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ और डिजिटल समाधान प्रदान करने में सबसे आगे रहा है. हम एम.एस.एम.ई. के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझते हैं और उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कई वित्तीय उत्पादों को डिजाइन किया है. सरकार की पहल और नियामक ढांचे के अनुरूप, हमारा बैंक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है.

'यूनियन धारा' का यह अंक एम.एस.एम.ई. ऋण देने में हमारे अनुभवों, अंतर्दृष्टि और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में उपलब्ध है. हमें उम्मीद है कि यहां प्रस्तुत जानकारी यूनियनाइट्स को भारत में एक मजबूत और लचीले एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी.

शुभकामनाओं सहित,

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Dear Unionites,

I am happy to note that the present edition of 'Union Dhara' is covering M.S.M.E. Sector in India. I hope that it is going to be informative and provide good reference material on MSMEs and its importance in driving India's growth. I commend the team 'Union Dhara' for bringing such vibrant issues every time.

In the current economic landscape of our country, MSMEs play a crucial role in fostering entrepreneurship, creating employment opportunities, and contributing significantly to GDP. As per government data, the M.S.M.E. sector comprises nearly 63 million enterprises, which contribute 30% to India's GDP, 45% to manufacturing, 40% to exports, and provides employment to over 11 crore people. To harness the full potential of the M.S.M.E. sector, it is essential to focus on providing a conducive environment, including access to finance, technology, skill development, and market linkages. Government policies and support from financial institutions are critical in fostering the growth and sustainability of MSMEs, ultimately contributing to the building of a strong and prosperous India.

As a country progresses, a well-functioning financial sector ensures that the benefits of economic growth are widespread, reaching all sectors of society, including MSMEs. This holistic approach supports the development of a dynamic and inclusive economy, laying the foundation for sustained progress and prosperity.

Our Bank has been at the forefront of facilitating the growth of MSMEs by providing tailored financial products & services, and digital solutions. We understand the unique challenges faced by MSMEs and have designed a comprehensive suite of financial products to address their diverse needs. In alignment with the government's initiatives and regulatory frameworks, our Bank remains dedicated to fostering financial inclusion and sustainable development across the M.S.M.E. sector.

This issue of 'Union Dhara' serves as a platform to share our experiences, insights, and success stories in M.S.M.E. lending. We hope that the information presented here inspires Unionites to collaborate towards building a robust and resilient M.S.M.E. ecosystem in India.

With best regards,

(A. Manimekhalai)
Managing Director & CEO

संपादकीय
EDITORIAL

प्रिय पाठकगण,

हम 'यूनियन धारा' का 'एम.एस.एम.ई. विशेषांक' आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं. इस अंक में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की विशेषताएं और अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है. इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमिता और स्वयं नियोजन को बढ़ावा दिया गया है और प्रत्येक नागरिक को स्वयं आगे बढ़ने और अपने साथ-साथ समाज को भी विकास की दिशा में अग्रसर करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया है. व्यष्टि और समष्टि के उद्धार से देश के विकास का सुनहरा मार्ग प्रशस्त किया गया है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस संवर्ग के अंतर्गत कारोबार विकास हेतु कई पहल की गई हैं. सरकारी नीतियों के अनुरूप कई उत्पाद विकसित किए गए हैं जो छोटे से छोटे व्यापारों से लेकर बड़े उद्योगों के वित्तपोषण हेतु सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराते हैं. साथ ही व्यावसायिकों, यथा डॉक्टर, आर्किटेक्ट आदि, के लिए भी अनुकूलित उत्पाद उपलब्ध हैं. एम.एस.एम.ई. ऋण संवर्ग के अंतर्गत कारोबार वृद्धि हेतु समय-समय पर कई अभियान भी चलाए जाते हैं और जागरूकता मुहिम किए जाते हैं.

हमारे लेखकों ने एम.एस.एम.ई. के संबंध में सर्वतोमुखी जानकारी युक्त इस विशेष अंक के प्रकाशन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस अंक के लिए अपने लेख के रूप में आशीर्वाद देने हेतु हम आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री निधु सक्सेना जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं. गृह पत्रिका को मूर्त रूप देने हेतु संपादकीय सलाहकारों के अमूल्य सुझाव से प्राप्त मार्गदर्शन हेतु हम कृतज्ञ हैं.

आशा है कि 'यूनियन धारा' का 'एम.एस.एम.ई. विशेषांक' आपको रुचिकर लगेगा. हम इस अंक के बारे में आपकी राय तथा मूल्यवर्धन हेतु आपके सुझाव का लाभ पाने की इच्छा रखते हैं, अत: हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें.

आपकी,

(गायत्री रवि किरण)

Dear Readers,

We are happy to present the 'M.S.M.E. special issue' of 'Union Dhara'. In this issue have endeavored to present the features and latest developments in the M.S.M.E. sector

M.S.M.E. sector is considered to be an important part of the economy. This sector promotes entrepreneurship and self-employment beside providing ample opportunities to every citizen to strive for individual growth as well as becoming a driving factor for the advancement of the society. A glorious path is paved for development of the country by facilitating micro and macro development.

Public sector banks have launched many initiatives for business growth under this sector. Many products have been developed in tune with government policies, which provide convenient options for providing finance as per the requirements of small traders as well as big industries. Further, customised products are also available for professionals like Doctors, Architects, etc. Many campaigns and awareness initiatives are also taken up from time to time for promoting business growth under M.S.M.E. portfolio.

Our writers have made significant contribution for publication of this holistic special issue on M.S.M.E.. We express our special thanks to respected Executive Director Shri Nidhu Saxena ji for his blessings in the form of the lead article. We are grateful to the editorial advisors for their invaluable inputs in bringing forth this issue.

Hope this M.S.M.E. special issue of 'Union Dhara' makes for an interesting read. We wish to benefit from your opinion regarding this issue and suggestions for further improvement, so kindly do send us your response.

Yours sincerely,

(Gayathri Ravi Kiran)

हार्दिक शुभकामनाएं

श्री संजय रुद्र ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी रह चुके हैं.

आपके पास बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे क्रेडिट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, एम.एस.एम.ई. और एकीकृत जोखिम विभाग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप एल एंड डी वर्टिकल के प्रभारी भी रह चुके हैं और आपके पास डिजिटल लेंडिंग के विकास परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है.

आपने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा हासिल की है. आप आई.आई.बी.एफ़. के एसोसिएट सदस्य हैं. आपने आई.आई.एम. बेंगलूरु से एफ.एस.आई.बी. द्वारा संचालित, नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सहयोग से आई.एस.बी., हैदराबाद द्वारा आयोजित ग्लोबल एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है.

श्री रुद्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कायापलट की अगुवाई करनेवाले वरिष्ठ नेतृत्व प्रबंधन में एक सक्रिय सहयोगी थे. उन्होंने महाराष्ट्र एक्ज़ीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

श्री लाल सिंह ने 1990 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया. आपको वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न आयामों, विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. क्रेडिट, उभरते कॉर्पोरेट वित्त, कृषि कारोबार, ज्ञानार्जन एवं विकास सहित मानव संसाधन प्रबंधन में 33 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न अंचल कार्यालय, वाराणसी, लखनऊ और चेन्नई के क्षेत्र महाप्रबंधक, क्षेत्र प्रमुख उदयपुर और मुंबई पश्चिम क्षेत्र के साथ-साथ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बैंक की ग्रामीण, शहरी, मेट्रो, फ़ॉरेक्स शाखाओं के शाखा प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण पदों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है. आपने कॉर्पोरेट ऑफिस में कृषि कारोबार वर्टिकल हेड, महा प्रबंधक एम.एस.एम.ई. तथा मानव संसाधन के पद पर कार्य किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ दो बैंकों के समामेलन के बाद आपने कृषि कारोबार वर्टिकल और एम. एस.एम.ई. वर्टिकल में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

आप विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सी.ए.आई.आई.बी.) के प्रमाणित एसोसिएट हैं तथा आपको ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डी.आई.टी.आई.आर.एम.) में डिप्लोमा और माइक्रो फाइनेंस में प्रमाणन भी प्राप्त हैं. आपने यूवीए डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस - वर्जीनिया यूएसए और आईएसबी, हैदराबाद में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया है. आप आई.आई.एम.बी., बी.बी.बी. (अब एफ.एस.आई.बी.) द्वारा विशेष रूप से आई.बी.ए. और डी.एफ.एस. के सहयोग से आई.आई.एम. बेंगलूरु से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यपालक के लिए उच्च नेतृत्व कार्यक्रम प्रबंधन, व्यवहारिक विज्ञान पाठ्यक्रम पूरा किया है.

आप ऋण जमा अनुपात एवं बी.जी.आर.ई.आई. पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश की उप समिति के अध्यक्ष थे. आप यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यू.पी.आई.सी.ओ.), मेसर्स नैबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (नाबार्ड की सहायक कंपनी), पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड सिडबी का पर्यवेक्षी बोर्ड के बोर्ड में नामित निदेशक थे. भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आई.आई.बी.एम.), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के ट्रस्टी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यू.बी.एस.एफ.टी.), के साथ-साथ पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए यूनियन बैंक कर्मचारी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे हैं.

आपने दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र

निधु सक्सेना
कार्यपालक निदेशक

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र : एम.एस.एम.ई. यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र है. एम.एस.एम.ई. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग 6-7 करोड़ एम.एस.एम.ई. हैं. इनमें से लगभग 99% एम.एस.एम.ई. इकाइयां सूक्ष्म उद्यम हैं तथा 50% से अधिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं. अधिकांश एम.एस.एम.ई. इकाइयां एकल स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं. एम.एस.एम.ई. न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और राष्ट्रीय आय और धन-संपदा का अधिकतम न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है.

अर्थव्यवस्था में एम.एस.एम.ई. का महत्व : भारत की जीडीपी में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का लगभग 30% योगदान है. निर्यात अर्जन में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की 40% हिस्सेदारी है. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है. विनिर्माण उत्पादन में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की 45% हिस्सेदारी है. नवाचार, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, संतुलित/ समावेशी आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का अहम योगदान है.

वित्तीय समावेशन और चुनौतियां

भारत में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का औपचारिक ऋण लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का है और 10 वर्षों में इसमें कम्पाउंडेड वार्षिक वृद्धि दर (सीजीएआर) से लगभग 13% की वृद्धि हुई है. तथापि इस क्षेत्र में अब भी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए ऋण की आवश्यकता बनी हुई है, जिसे अनौपचारिक क्षेत्र से पूरा किया जाता है. एम.एस.एम.ई. इकाइयों द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने हेतु विवश होने का एक मुख्य कारण उचित दस्तावेजों की कमी है. बैंकों को वैध दस्तावेज उपलब्ध न करवा पाने के कारण एम.एस.एम.ई. इकाइयों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है. अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने का एक कारण यह भी है कि एम.एस.एम.ई. इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित गति से ऋण उपलब्ध हो जाता है और ऋण स्वीकृति तुरंत हो जाती है. एम.एस.एम.ई. इकाइयों के समक्ष एक और चुनौती है संपार्श्विक (कलैटरल) की अनुपलब्धता भी है, जिसके कारण औपचारिक रूप से ऋण लेने में एम.एस.एम.ई. इकाइयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

कोविड-19 की चुनौतियां और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र : कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने वसूली में देरी और आर्थिक मांग में कमी के कारण एम.एस.एम.ई. कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला. चूँकि ये इकाइयाँ किसी भी कारोबारिक अत्यावश्यकताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, इसलिए कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व घटना ने भी इस क्षेत्र पर भारी असर डाला है. यही कारण है कि अनौपचारिक क्षेत्र से फाइनेन्स प्राप्त एम.एस.एम.ई. इकाइयाँ अधिक प्रभावित हुईं.

भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. इकाइयों और अन्य कारोबार में नकदी

प्रवाह असंतुलन की स्थिति से राहत प्रदान करने के लिए जीईसीएल सुविधा के रूप में चलनिधि सहायता प्रदान करते हुए कारोबार की सहायता के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शुरू किया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने इन इकाइयों से आउटफ्लो को आसान बनाने के लिए ऋण किस्तों की चुकौती हेतु ऋणस्थगन (मॉरटोरीअम) सुविधा भी प्रदान की है.

सरकार, बैंकों और नियामक निकाय के संयुक्त प्रयासों ने एम.एस.एम.ई. को कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने और महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि में भाग लेने में सहायता प्रदान की है.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास हेतु बैंक की पहल: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी जैसे प्रतिकूल समय में भी कारोबारिक मांग को पूरा करने के लिए समय पर ऋण सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एम.एस.एम.ई. को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं. एम.एस.एम.ई. की सहायता हेतु बैंक द्वारा किए गए कुछ प्रयास एवं पहल निम्नलिखित हैं :-

• बैंक ने एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न एम.एस.एम.ई. उत्पाद लॉन्च किए हैं. ये ऋण रियायती शर्तों पर प्रदान किये जाते हैं. महिला/ एससी/ एसटी उधारकर्ताओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं.

• बैंक ने यूनियन जीएसटी गेन नाम से नकदी प्रवाह उत्पाद शुरू किया है, जिसके अंतर्गत एम.एस.एम.ई. इकाइयों को परंपरागत तुलन पत्र आधारित फाइनेन्स के स्थान पर जीएसटी रिटर्न के आधार पर 5.00 करोड़ रुपए तक का फाइनेन्स किया जा सकता है.

• कलैटरल रहित ऋण के संदर्भ में, बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फाइनेन्स प्रदान किया है तथा कलैटरल प्रदान करने में असमर्थ एम.एस.ई. को वित्तीय सहायता देने के लिए सी.जी.टी.एम.एस.ई./सीजीएफएमयू जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं का उपयोग किया है.

• इस संवर्ग को ऋण के तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 135 केंद्रों पर एम.एस.एम.ई. ऋण प्वाइंट स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही बैंक द्वारा विशेष रूप से इस खण्ड को त्वरित ऋण प्रदान करने हेतु 105 यूनियन एम.एस.एम.ई. फर्स्ट शाखाएं (यूएमएफबी) शुरू की गई हैं.

• बैंक ने इन स्थानों पर एम.एस.एम.ई. के वित्तपोषण के लिए 22 से अधिक क्लस्टर की पहचान की है, जहां कम/ शून्य संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ रियायती शर्तों पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं.

• अनौपचारिक क्षेत्र को बैंक वित्त के अंतर्गत लाने के लिए बैंक द्वारा पीएमएमवाई, पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया और पीएम-स्वनिधि जैसी सरकार प्रायोजित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं.

• बैंक ने डिजिटल चैनल के माध्यम से एम.एस.एम.ई. ग्राहकों को परेशानी-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शिशु मुद्रा एसटीपी, किशोर और तरुण एसटीपी, नारी शक्ति एसटीपी और जीएसटी गेन एसटीपी के तहत डिजिटल जर्नी (https://msme.unionbankofindia.co.in/#/mudra-main) भी शुरू की हैं. इन चैनलों के माध्यम से बैंक ने एम.एस.एम.ई. खण्ड को लगभग 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग जगत का पहला बैंक है जिसने डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए एम.एस.एम.ई. क्रेडिट कार्ड जारी किया है और अब तक 20,000 से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं.

निष्कर्ष: सरकार और अन्य हितधारकों के निरंतर समर्थन के बावजूद, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की भारी ऋण मांग को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से पूरा किया जाता है. इसका मुख्य कारण यह है कि ये इकाइयां वित्तीय क्षेत्र द्वारा वित्तपोषण के लिए आवश्यक पारंपरिक वित्तीय विवरणों को बरकरार नहीं रख पा रही हैं. इसी मुद्दे को निम्नलिखित तरीके से संबोधित किया जा सकता है:

• उधारकर्ताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी आदि जैसे डिजिटल सेवा प्रदाताओं का उपयोग करना.

• पारंपरिक तुलन पत्र आधारित फाइनेन्स के स्थान पर नकदी प्रवाह और अन्य डिजिटल डेटा के आधार पर हामीदारी अंकन (अंडरराइटिंग) करना.

• एम.एस.एम.ई. को ऋण के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत लाने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना.

एम.एस.एम.ई. इकाइयों के विकास में बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं. एम.एस.एम.ई. इकाइयों को समय पर ऋण उपलब्ध करवा कर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को मजबूत करते हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है.

♦♦♦

एम.एस.एम.ई.
भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी

एम.एस.एम.ई. ने हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ एम.एस.एम.ई. न सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं. गौरतलब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिक बाज़ार की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष ज़ोर दिए जाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रणनीति की दृष्टि से एम.एस.एम.ई. की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया कि अगले पाँच वर्षों में यह क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगारों के सृजन के लिए उत्तरदायी होगा.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

गौरतलब है कि जर्मनी और चीन की जीडीपी में एम.एस.एम.ई. की भागीदारी क्रमशः 55% और 60% है जो इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है एम.एस.एम.ई. की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं:

वित्तीय चुनौतियाँ: भारत में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में ऋण आपूर्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

इस क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण 16 ट्रिलियन रुपए ही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कुल व्यावहारिक ऋण की ज़रूरत 36 ट्रिलियन रुपए के सापेक्ष अब भी लगभग 20 ट्रिलियन रुपए का अंतर बना हुआ है.

इसके साथ ही बैंकिंग पहुँच की कमी के कारण भारत में एम.एस.एम.ई. को अधिकांशतः 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों'(एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) पर निर्भर रहना पड़ता है.

सितंबर 2018 से एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी ने एम.एस.एम.ई. की वित्तीय चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया है.

औपचारिकता की कमी: इस क्षेत्र में क्रेडिट गैप का एक प्रमुख कारण एम.एस.एम.ई. के बीच औपचारिकता की कमी रही है. देश में सक्रिय कुल एम.एस.एम.ई. में से लगभग 86% का पंजीकरण नहीं किया गया है. वर्तमान में भी देश के कुल 6.3 करोड़ एम.एस.एम.ई. में से केवल 1.1 करोड़ ही 'वस्तु और सेवा कर' (जीएसटी) व्यवस्था के साथ पंजीकृत हैं. इसके साथ ही इन 1.1 करोड़ एम.एस.एम.ई. में से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या और भी कम है. ऐसे में सीमित उपलब्धता और डेटा पारदर्शिता के अभाव में भारतीय एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की ऋण ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सका है.

तकनीकी बाधाएँ: भारत का एम.एस.एम.ई. क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो इसकी उत्पादन क्षमता को बाधित करता है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों (जिसे सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 के रूप में जाना जाता है) का उद्भव संगठित क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में एम.एस.एम.ई. के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है.

नियामकीय बाधाएँ: एम.एस.एम.ई. के संचालन के लिए बहुत-सी सरकारी अनुमतियों और सेवाओं की आवश्यकता होती है. नियामकीय जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना, करों का भुगतान, व्यापार शुरू करना और सीमाओं के पार व्यापार करना आदि एम.एस.एम.ई. की प्रगति में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. विनियामक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितता ने पूर्व में भी निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है.

उत्पादन की चुनौतियाँ: वर्तमान में देश में सक्रिय एम.एस.एम.ई. में अधिकांश फर्म सूक्ष्म उद्यम श्रेणी की हैं. देश का एम.एस.एम.ई. क्षेत्र मुख्य रूप से छोटी और स्थानीय दुकानों की भरमार से बना एक सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है, ऐसे में उनके व्यापार या उत्पादन को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है. इन समस्याओं के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत ही कम रहा है.

आगे की राह:

बॉण्ड मार्केट का विकास करना: हाल के वर्षों में भारतीय बॉण्ड बाज़ार में हुई प्रगति के बीच एसएमई बॉण्ड को बढ़ावा देने से एम.एस.एम.ई. की ऋण पूंजी बाज़ारों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है. एक तरफ जहाँ एसएमई बॉण्ड को प्रोत्साहित करने से एम.एस.एम.ई. को अन्य वित्तीय बिचौलियों की तुलना में कम ब्याज दर का लाभ मिल सकेगा, वहीं ये बॉण्ड बाज़ार में काम करने वाले जागरूक और शिक्षित निवेशकों के लिए एक व्यवहार्य उच्च रिटर्न के साधन के रूप में कार्य करेंगे.

स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था: डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए जो एम.एस.एम.ई. को परामर्श देने

के साथ उन्हें इस नई डिजिटल व्यवस्था में आगे बढ़ने में सक्षम बना सके.

श्रम कानूनों में सुधार: वर्तमान में देश में लागू श्रम कानून एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं. श्रम कानूनों में बदलाव किया जाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इन कानूनों को एम.एस.एम.ई. के लिए विकासोन्मुख ढाँचा प्रदान करने और श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बीच सही संतुलन स्थापित करना होगा.

विनियमन में सुधार: हाल के वर्षों में सरकार द्वारा व्यापार सुगमता पर विशेष ज़ोर दिया गया है परंतु इसी दौरान छोटे व्यवसायों के लिए रिपोर्टिंग, अनुमोदन और अनुपालन आवश्यकता आदि जटिलताएँ बनी हुई हैं. यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि एम.एस.एम.ई. का देश के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो, तो इसके लिए एम.एस.एम.ई. को आनुकूल नियामकीय ढाँचा प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है.

निष्कर्ष: एम.एस.एम.ई. एक लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ हड्डी का कार्य करते हैं. देश के मज़बूत आर्थिक भविष्य के लिए एम.एस.एम.ई. के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है. सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. भारत को ऐसे ही और उपायों को अपनाने की आवश्यकता है. अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में एम.एस.एम.ई. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी.

अमित सिंह चौहान
क्षे.का., चेन्नै ब्रॉडवे

पुरस्कार

दिनांक 26.09.2023 को मुंबई में आशीर्वाद संस्था द्वारा श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं) को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में पासबान-ए-अदब संस्था द्वारा बैंक को 'दुष्यंत सम्मान' प्रदान किया गया. दिनांक 17.09.2023 को श्री खैसर खालिद, विशेष पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र शासन, श्री अनूप जलोटा, विख्यात ग़ज़ल गायक एवं श्री आलोक त्यागी से बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मा.सं), श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.) और श्री विवेकानंद, मुख्य प्रबंधक (रा.भा.).

दिनांक 26.09.2023 को मुंबई में आशीर्वाद संस्था द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु बैंक को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया. साथ ही 'यूनियन सृजन' को श्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार प्राप्त हुआ. बैंक की ओर से श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं) ने पुरस्कार प्राप्त किया. साथ है श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उमप्र, श्री रामजीत सिंह, समप्र (रा.भा.), डॉ. सुलभा कोरे, तत्कालीन संपादक तथा श्रीमती गायत्री रवि किरण, संपादक.

दिनांक 22.09.2023 को नई दिल्ली में पीआरसीआई संस्था द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु क्षेत्रीय गृह पत्रिका श्रेणी में 'यूनियन सृजन' को स्वर्ण पुरस्कार और अंग्रेजी गृह पत्रिका श्रेणी में 'यूनियन धारा' को कांस्य पुरस्कार प्रदान किया गया. बैंक की ओर से श्री कबीर भट्टाचार्य, अंचल प्रमुख, दिल्ली और गृह पत्रिकाओं की संपादक श्रीमती गायत्री रवि किरण ने पुरस्कार प्राप्त किया.

एम.एस.एम.ई. : चुनौतियां और समाधान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रतिष्ठान अपने कारोबार को बढ़ाने या नया उद्यम शुरू करने के लिए एम.एस.एम.ई. ऋण का लाभ उठा सकते हैं. एम.एस.एम.ई. की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी- मुद्रा की स्थापना की गई थी. इसकी कल्पना समाज के वंचित वर्गों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है. इसके अलावा मुद्रा बैंक भी सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देता हैं. तथापि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतिया विद्यमान हैं, जो उनकी विकास संभावनाओं को प्रभावित करती हैं :

वित्तीय और नियामक समस्याएं- वित्त की उपलब्धता एम.एस.एम.ई. के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है जो उनकी वृद्धि की संभावनाओं को रोकता है. औपचारिक बैंकों से सस्ते वित्त की उपलब्धता होने के बावजूद जानकारी के अभाव में ऋण समय पर नहीं ले पाते तथा इसके साथ ही एम.एस.एम.ई. को कर अनुपालन और श्रम कानून में परिवर्तन के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करने के बावजूद, विनियमों और कर पंजीकरण का अनुपालन कठिन रहता है, जिससे कम पूंजी के कारण व्यवसाय बंद हो जाता है.

नवाचार की कमी- भारतीय एम.एस.एम.ई. में नवाचार की कमी है और उनके द्वारा उत्पादित अधिकांश उत्पाद पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं. इस क्षेत्र में उद्यमियों की भारी कमी है, इस कारण को नई प्रौद्योगिकियों और साधनों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है. परिणामस्वरूप एम.एस.एम.ई. को पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विशेष रूप से बड़ी फर्मों की तुलना में उत्पादकता के निम्न स्तर के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है.

छोटी फर्मों का बहुमत- एम.एस.एम.ई. में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है. इस प्रकार जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार के आपातकालीन 'लाइन ऑफ क्रेडिट', 'स्ट्रेस्ड एसेट रिलीफ', 'इक्विटी भागीदारी' और 'फंड ऑफ फंड ऑपरेशन' का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.

कम उत्पादकता : एम.एस.एम.ई. में उत्पादकता की कमी है लागत दक्षता के माध्यम से और कम कीमतों पर माल की उपलब्धता की कमी है. उनके छोटे-छोटे उत्पादन और कम मार्जिन उन्हें बड़ी फर्मों की तुलना में नुकसान पहुंचाते हैं. भारतीय एम.एस.एम.ई. अक्सर पुरानी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करते हैं जो नए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करते हैं, जो उनकी उत्पादकता को प्रभावित करता है.

तकनीकी परिवर्तन- एम.एस.एम.ई. को समय के साथ महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी वृद्धि की क्षमता प्रभावित होती है. भूमि मालिकाना अधिकारों में परिवर्तन के कारण गलत प्रबंधन और उत्पादकता में कमी आई है.

प्रतिस्पर्धा और कौशल- एम.एस.एम.ई. को बड़ी कंपनियों से अत्याधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो ई-कॉमर्स और वैश्वीकरण के कारण और अधिक बढ़ जाता है. जबकि प्रतिस्पर्धा नई नहीं है, एम.एस.एम.ई. कृषि, वस्त्र और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दबाव को रोकने के लिए संघर्ष करते हैं. एम.एस.एम.ई. अन्य देशों में अपने समकक्षों की तुलना में कौशल के संदर्भ में पीछे हैं. सीमित तकनीकी कौशल वाले अनौपचारिक साधनों पर निर्भरता उत्पादकता को रोकती है और छोटी फर्मों को कम कुशल कारीगरों के कारण दीर्घकालिक विकास से रोकती है.

श्रम संबंधी चुनौतियाँ- एक सफल विनिर्माण उद्यम कुशल श्रम पर निर्भर करता है. एम.एस.एम.ई. में कुशल कर्मियों और श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में कई विसंगतियां मौजूद हैं. किफायती कुशल श्रम की कमी ने एम.एस.एम.ई. की समस्याओं को और बढ़ा दिया है.

एम.एस.एम.ई. चुनौतियों का समाधान

सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. की उपरोक्त चुनौतियों का समाधान निम्न उपाय किए गए हैं:

समाधान पोर्टल से विलंबित भुगतान का निपटान : एम.एस.एम.ई. समाधान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा भुगतान में देरी से संबंधित अपने मामलों को सीधे पंजीकृत करने के लिए देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाना है. एम.एस.एम.ई. समाधान पोर्टल एम.एस.एम.ई. को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के समक्ष सामान/सेवाओं के खरीददार के खिलाफ विलंबित भुगतान के मामले सीधे दर्ज करने में सक्षम बनाता है.

संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड - एम.एस.एम.ई. के लिए उप-ऋण- उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) 26 जून, 2020 को संकटग्रस्त एम.एस.एम.ई. को पूंजीगत समर्थन

देने के लिए उपऋण के रूप में 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

एम.एस.एम.ई. के लिए फंड ऑफ फंड योजना- एम.एस.एम.ई. के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि से आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (एम.एस.एम.ई. योजना के लिए फंड ऑफ फंड योजना) के दिशा निर्देश जारी किए गए.

चैंपियन पोर्टल- चैंपियन पोर्टल छोटी इकाईयों को सहायता प्रदान कर उन्हें बड़ा बनाने के लिए आईसीटी आधारित एक प्रौद्योगिकी प्रणाली है. 54 बैंक/वित्तीय संस्थान/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य वित्तीय कार्पोरेशन और निजी क्षेत्र से संबधित 19 बैंक ऋण संबंधी पूछताछ के त्वरित समाधान के लिए पोर्टल में शामिल हैं.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है.

क्लस्टर विकास योजना- परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि (स्फूर्ति) योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2020 तक 736.67 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता द्वारा 317 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई.

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)- वर्तमान में प्रौद्योगिकी केंद्र(टीसी) के सफलतापूर्वक संचालन और प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र) के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन के उद्देश्य से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 2200 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) की शुरुआत की है. इसके अंतर्गत देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) की स्थापना और वर्तमान के टीसी का उन्नयन किया जाएगा.

खरीद और विपणन प्रोत्साहन- ई-मार्केट संपर्क बढ़ाने के लिए वर्चुअल व्यापार मेलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. एम.एस.एम.ई. मंत्रालय बाजार तक अधिक पहुंच बढ़ाने के लिए आईटीपीओ के साथ विचार-विमर्श कर एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान के परिसर में स्थायी प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है.

कॉयर विकास योजना- एम.एस.एम.ई. ने परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि (स्फूर्ति) के अंतर्गत अब तक 41 कॉयर क्लस्टर को अंतिम मंजूरी दी है. 41 अनुमति प्राप्त कॉयर क्लस्टर में 2 हेरिटेज, 19 बड़े, 11 लघु और 9 नियमित क्लस्टर सम्मिलित हैं.

इनक्यूबेटर द्वारा एम.एस.एम.ई. के उद्यम और प्रबंधकीय विकास को प्रोत्साहन : दो सौ से अधिक तकनीकी संस्थानों, उद्योग संघों और सामाजिक उद्यमों को इनक्यूबेशन केंद्र के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गई है. योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए व्यापार प्रस्ताव वाले अभिनव विचार आमंत्रित किए जाते हैं.

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी धन निधि (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) : सी.जी.टी.एम.एस.ई. के तहत, ट्रस्ट द्वारा 500 लाख रुपए की सीमा तक क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है, जो सभी नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएफजी और साथ ही दोनों) को, बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के, स्वीकृत किए गए हैं.

नवीन शुरुआत : स्कोर कार्ड मॉडल पर पीएमईजीपी के अंतर्गत इकाई की स्थापना करने और चयन की गति बढ़ाने के लिए आवेदन के चयन में जिला स्तरीय कार्यदल समिति (डीएलटीएफसी) की भूमिका को समाप्त कर योजना की प्रक्रिया सरल बनाया गया है.

सभी राज्यों में पीएमईजीपी लाभकर्ताओं को सहायता और परामर्श देने के लिए विपणन और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का प्रावधान किया गया है.

ऑनलाइन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण पोर्टल की शुरुआत की गई और लाभार्थियों को ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

पीएमईजीपी इकाइयों को उत्पादों के विविधीकरण की अनुमति दी गई. इससे बाजार की आवश्यकताओं इकाई की आर्थिक व्यावहारिकता में बढ़ोतरी होगी.

जियो-टैगिंग पोर्टल www.geotag.kvic.gov.in को तैयार किया गया और इसका संचालन किया जा रहा है. पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की जियो-मैपिंग की जाएगी जिससे उनके स्थान और इकाई की निगरानी आसानी से की जा सकेगी.

अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोज़गार सृजन में उल्लेखनीय योगदान के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत में एम.एस.एम.ई. की वृद्धि जबरदस्त रही है और इसकी विकास क्षमता बहुत अधिक है. भारतीय उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ावा देना, फंडिंग- फ़ाइनेंस और सब्सिडी, घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि, कच्चे माल और मशीनरी की खरीद, कम पूंजी की जरूरत आदि कारकों के कारण एम.एस.एम.ई. उद्योग में अपार सम्भावनाएं हैं.

प्रवीण कुमार
यू.एल.ए., गुरुग्राम

शिखर की ओर...

उच्च कार्यपालक वेतनमान VI में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई

आर. नागराजा
उप महाप्रबंधक

आर. सत्यनारायण
उप महाप्रबंधक

के. अरुणा सविता
उप महाप्रबंधक

डी. अपर्णा रेड्डी
उप महाप्रबंधक

मुनीश कुमार चोपड़ा
उप महाप्रबंधक

के.एन.वी. चिन्ना राव
उप महाप्रबंधक

दीपक जगदीश्वर सक्सेना
उप महाप्रबंधक

अशोक कुमार भोई
उप महाप्रबंधक

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

शुभमस्तु...

बी. जानकी राम
महाप्रबंधक

आशुतोष कुमार
उप महाप्रबंधक

के. एस. अनंत
उप महाप्रबंधक

आई. रवि कृष्ण
उप महाप्रबंधक

पोलूरि दत्तात्रेय वेंकटेश्वर शर्मा
उप महाप्रबंधक

जी. मुरुगन
उप महाप्रबंधक

संतोष कुमार शुक्ल
उप महाप्रबंधक

सोवन सेनगुप्त
उप महाप्रबंधक

हम आपके सुखद एवं सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं.

एम.एस.एम.ई. : विकास का प्रमुख कारक

एम.एस.एम.ई. सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय हैं जो सेवा उद्योग या वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और संरक्षण में काम करते हैं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एम.एस.एम.ई. को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है - विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम. सरकार ने एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की है, जहां निवेश के बजाय टर्नओवर एम.एस.एम.ई. को परिभाषित करेगा, जिसका लक्ष्य एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में पांच करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है. एम.एस.एम.ई. का वर्गीकरण इस प्रकार है:

वर्ग	निवेश	टर्नओवर
सूक्ष्म उद्यम	<1 करोड़	<5 करोड़
लघु उद्यम	<10 करोड़	<50 करोड़
मध्यम उद्यम	<50 करोड़	<250 करोड़

भारतीय एम.एस.एम.ई. विभिन्न व्यवसायों में 11.10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. अकेले विनिर्माण क्षेत्र में यह 3.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और भारत के विनिर्माण उत्पादन में सक्रिय रूप से 45% का योगदान देता है. यह निर्यात में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% वहन करता है.

एम.एस.एम.ई. इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं?

भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, सूक्ष्म और मध्यम आकार के उद्यमों का घर है. केंद्रीय एम.एस.एम.ई. मंत्री श्री नारायण राणे के अनुसार, देश का एम.एस.एम.ई. सेक्टर भारत की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा है. देश भर में फैले यह व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. जो विकास, रोज़गार, निर्यात और उत्पादकता को बढ़ाते हैं.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और पीआई मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पादन में एम.एस.एम.ई. विनिर्माण की हिस्सेदारी क्रमशः 36.9% और 36.9% थी. इसके अलावा, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में एम.एस.एम.ई. से संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी क्रमशः 49.8% और 49.5% थी.

भारत में एम.एस.एम.ई.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसाय (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र पर केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं का प्राथमिक फोकस रहा है क्योंकि यह रोजगार, मूल्य श्रृंखला निर्माण, विदेशी मुद्रा आय के मामले में समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास में एक मूल्यवान योगदानकर्ता है. बड़े उद्योगों के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता, क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, इत्यादि. एम.एस.एम.ई. मंत्रालय में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, कॉयर बोर्ड, विकास आयुक्त कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) जैसे विभिन्न संस्थान शामिल हैं.

भारत एम.एस.एम.ई. पर बड़ा दांव क्यों लगा रहा है?

भारत सरकार 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है. इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, एम.एस.एम.ई. एक प्रमुख रोजगार जनरेटर के रूप में सामने आया है और इसलिए भारत की उत्साही युवा आबादी के लिए अनगिनत कैरियर के अवसर पैदा किए जा सकते हैं.

सूक्ष्म क्षेत्र में लगभग 630.52 लाख उद्यम हैं, जिससे 1076.19 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जो उद्योग में कुल रोजगार का लगभग 97% है. लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम क्षेत्र में 0.05 लाख अनुमानित एम.एस.एम.ई. ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में कुल रोज़गार में से क्रमशः 31.95 लाख (2.88%) और 1.75 लाख (0.16%) लोगों को रोज़गार दिया.

आबादी के एक बड़े हिस्से को रोज़गार प्रदान करने और देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ एम.एस.एम.ई. मौजूदा बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

भारतीय एम.एस.एम.ई. का महत्वपूर्ण प्रभाव

निर्यात लक्ष्य हासिल करना: एम.एस.एम.ई. की मदद से, इंडिया इंक वित्त वर्ष 2023 तक 400 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है और 2027 तक निर्यात में 1 ट्रिलियन डॉलर के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को साकार करना चाहता है.

परिवर्तन का चालक: 20.73% स्वामित्व वाले एम.एस.एम.ई. का स्वामित्व महिलाओं के पास होने से महिला उद्यमी लगातार मजबूत हो रही हैं. सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के पास लगभग 66.27% एम.एस.एम.ई. का स्वामित्व है.

नवाचार और उद्यमिता: एसएमई अपने नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं. वे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक बड़े हिस्से के लिए भी जिम्मेदार हैं.

पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना: बड़ी संख्या में एसएमई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं और इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं.

लागत कम करना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: एम.एस.एम.ई. कई बड़ी कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वस्तुओं और सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एम.एस.एम.ई. के लिए वित्त प्रदान करके और निर्यात में अपनी हिस्सेदारी के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाकर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को और विकसित करने की योजना बना रहा है. एम.एस.एम.ई. के साथ उद्यमिता में हिस्सा लेने के लिए पूंजी जुटाना इसमें एक गति अवरोधक के रूप में कार्य करता है, इसलिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय नियमित अंतराल पर विभिन्न वित्तपोषण योजनाएं लेकर आता है, जबकि बैंक विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. के लिए डिज़ाइन की गई आकर्षक ऋण पेशकश भी करता है.

पिछले 50 वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र भारत के सबसे जीवंत और सबसे गतिशील आर्थिक क्षेत्रों में से एक बन गया है. चूँकि यह उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करता है, यह राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है. यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ऋण तक आसान पहुंच और दिवालियापन से सुरक्षा जैसे नीतिगत उपायों के माध्यम से एम.एस.एम.ई. का समर्थन करना जारी रखे. इससे यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.

सीमा प्रियदर्शिनी
क्षे.का., भुवनेश्वर

एम.एस.एम.ई. : नवीनतम रुझान एवं भविष्य

पिछले दो वर्षों में, महामारी ने चुनौतियों का भंडार तैयार किया है और विकसित होने, आगे बढ़ने और मजबूत होकर उभरने के अवसर प्रदान किए हैं. एम.एस.एम.ई. ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा, नए रुझानों का स्वागत किया और नवीनतम तकनीकों को अपनाया. उन्होंने डिजिटलीकरण और ब्रांडिंग की क्षमता को समझना शुरू कर दिया है, जिससे नए रास्ते बन रहे हैं.

निरंतर डिजिटल अपनाना : डिजिटलीकरण एक मौजूदा व्यवसाय मॉडल को संशोधित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का संक्रमण है और यह राजस्व और मूल्य-उत्पादन के अवसर उत्पन्न करने के लिए नई संभावनाएं प्रदान कर सकता है. कोविड-19 महामारी ने एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र में पारंपरिक दृष्टिकोण से डिजिटल माध्यम की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव की सुविधा प्रदान की. क्रिसिल की रिपोर्ट है कि भारत में 53% एसएमई और 47% सूक्ष्म-उद्यमों ने डिजिटल बिक्री प्लेटफॉर्म को अपनाया, जबकि पूर्व-कोविड आंकड़ा 29% था.

एम.एस.एम.ई. ग्लोबल मार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी डिजिटल परिवर्तन का एक हिस्सा है, जहां छोटे व्यवसाय ई-कॉमर्स का उपयोग करके दुनिया में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं. ये प्लेटफ़ॉर्म कम लागत, कम निवेश और उच्च स्तर के नवाचार पर एम.एस.एम.ई. की वृद्धि और विकास को संचालित करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध करने में मदद करते हुए कई कंपनियों को अपने ब्रांड और संचालन को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.

हालाँकि, कई एम.एस.एम.ई. का विपणन कम है और वे प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए विपणन शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा एम.एस.एम.ई. के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है. अत: बदलते समय के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए एम.एस.एम.ई. डिजिटल अपनाने में तेजी ला रहे हैं.

एम.एस.एम.ई. का अधिक औपचारिकीकरण : औपचारिकीकरण - या व्यवसायों का कानूनी पंजीकरण - गैर-मान्यता प्राप्त या अवर्गीकृत एम.एस.एम.ई. व्यवसायों को एक मान्यता प्राप्त इकाई बनने में मदद कर सकता है और इसलिए सरकारी योजनाओं, व्यावसायिक क्रेडिट और कर लाभ जैसे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है. इस पहल ने कई एम.एस.एम.ई.

मालिकों को अपने सपनों के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायता की. हालाँकि, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 99.7% एम. एस.एम.ई. अब भी अनौपचारिक रूप से काम करते हैं और उन्हें मिलने वाले लाभों से अनजान हैं. इसलिए, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय और भारत सरकार ने भारत के इस वंचित क्षेत्र की सहायता के लिए एम.एस.एम.ई. को औपचारिक बनाने की पहल की.

2023 में अधिक एम.एस.एम.ई. व्यवसायों के औपचारिक होने की उम्मीद है. नए या मौजूदा अनौपचारिक इकाइयाँ एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सभी लाभ और विभिन्न योजनाओं को प्राप्त करने के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन और एजीएम को संबोधित करते हुए एम.एस. एम.ई. मंत्रालय के सचिव श्री बीबी स्वैन ने कहा कि किफायती ऋण को आकर्षित करने के लिए भारतीय एम.एस.एम.ई. क्षेत्र अगले 25 वर्षों में और अधिक औपचारिक हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि 'उद्यम' या 'एम.एस.एम.ई. पंजीकरण' पोर्टल, जिसने 3 जनवरी 2023 तक पंजीकृत 1.31 करोड़ एम.एस.एम.ई. को पार कर लिया है, को प्रतिदिन लगभग 20,000 नए पंजीकरण मिलते हैं.

भारत से निर्यात की संख्या बढ़ाना : भारत के व्यापार और बाहरी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. भारत दूध, दालों और जूट के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और चावल, गेहूं, फल और कपास, मूंगफली, चीनी और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. यह मसालों, मछली, मुर्गीपालन, पशुधन और वृक्षारोपण फसलों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है. इनमें से अधिकांश छोटी उत्पादन इकाइयों में चलाए जाते हैं.

2028 तक भारत का औद्योगिक निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. चूँकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, देश के विकास के प्रमुख चालकों में से एक भारत के निर्यात की मात्रा में वृद्धि है, जो 37% बढ़ी है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2022 में भारत के समग्र निर्यात (माल और सेवाएँ संयुक्त) ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.72% की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की.

परंपरागत रूप से, एम.एस.एम.ई. ने भारत के निर्यात में लगभग 50% योगदान दिया है; इसलिए, निर्यात में वृद्धि छोटे व्यवसायों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और वितरित करने के विकास के अवसर का प्रतीक है. निर्यात बढ़ाकर, भारत अधिक नौकरियाँ प्रदान करने और अर्ध-कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए अवसर पैदा करने के लिए तैयार है.

भारत में उपभोक्ता मांग में वृद्धि : उपभोक्ता मांग क्रय शक्ति पर निर्भर करती है, जो किसी व्यक्ति या परिवार की खरीददारी करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है. यह उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करता है कि खरीददारी, रेस्तरां, मनोरंजन पार्क आदि पर खर्च करते समय वे अर्थव्यवस्था में कितना पैसा वापस लगाएंगे. यदि कीमतें घटती हैं, तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति अधिक होती है, जबकि जब मुद्रास्फीति होती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं. उपभोक्ता मांग 2023 में भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाती रहेगी. फिच सॉल्यूशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उपभोक्ता खर्च 2023 में ठोस वृद्धि का अनुभव करेगा और 2022 की तुलना में 2023 में घरेलू खरीद शक्ति 7.1% बढ़ने की उम्मीद है.

एम.एस.एम.ई. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने डोमेन का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू और वैश्विक बाजारों की उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रृंखला का उत्पादन कर रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप, भारत में बहुत सारे नए एम.एस.एम.ई. व्यवसाय फल-फूल रहे हैं. इसलिए, बढ़ी हुई घरेलू खपत एम.एस.एम.ई. के लिए बढ़ने और सभी क्षेत्रों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अधिक घरेलू उत्पादों का उत्पादन करने का एक जबरदस्त अवसर है.

निष्कर्ष : एम.एस.एम.ई. भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. इसलिए, सरकार एक समग्र और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश कर रही है जो 2023 में एम.एस.एम.ई. को और आगे बढ़ने में सक्षम बना सके. जैसा कि देखा जा सकता है, 2023 हर व्यावसायिक क्षेत्र के लिए एक शानदार वर्ष बन रहा है. छोटे व्यवसाय अपने काम करने के तरीके को बदल रहे हैं और अपने निवेश से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने दर्शकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ रुझान भी स्थापित कर रहे हैं.

तकनीकी प्रगति और उच्च उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के साथ, एम.एस.एम.ई. अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, मंदी और मुद्रास्फीति के बावजूद, उभरती प्रौद्योगिकियाँ दुनिया भर के उद्यमियों को भीड़ में खड़े होने में मदद कर रही हैं. एम.एस.एम.ई. उद्यमी उद्योग के बदलते परिदृश्य को अपना सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अवसर तलाश सकते हैं.

बिपिन कुमार भगत
क्षे.का., पुणे मेट्रो

सी.जी.टी.एम.एस.ई. :

एम.एस.ई. क्षेत्र की वृद्धि और विकास का इंजन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) की स्थापना 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.), भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी. सी.जी.टी.एम.एस.ई. का उद्देश्य सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को गारंटी कवर प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को उत्प्रेरित करना है.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. की चार मुख्य योजनाएं:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएस-I): यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को दिए गए ऋण के लिए एमएलआई को गारंटी कवर प्रदान करती है.

एन.बी.एफ.सी. के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएस-II): यह योजना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के माध्यम से एम.एस.ई. को दिए गए ऋण के लिए एमएलआई को गारंटी कवर प्रदान करती है.

अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सी.जी.एस.एस.डी.): यह योजना एम.एस.ई. को दिए गए अधीनस्थ ऋण के लिए एमएलआई को गारंटी कवर प्रदान करती है.

पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सी.जी.एस.-पी.एम.एस.): यह योजना पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को दिए गए ऋण के लिए एमएलआई को गारंटी कवर प्रदान करती है.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. के प्रमुख उद्देश्य

सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को गारंटी कवर प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना.

एम.एस.ई. को ऋण देने के जोखिम को कम करना और एमएलआई को इस क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना.

- भारत में एम.एस.ई. क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना.
- संपार्श्विक से योग्यता-आधारित उधार की ओर बदलाव लाना.
- उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना.
- रोजगार के अवसर पैदा करना.
- क्रेडिट गारंटी तंत्र में विश्वास पुनर्जीवित करना.

एम.एल.आई. की जिम्मेदारियां

व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों के चयन में उचित परिश्रम करना और विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय के साथ ऋण सुविधाओं का मूल्यांकन करना चाहिए. खाते को आंतरिक रूप से रेटिंग दी जानी चाहिए और वह निवेश ग्रेड का होना चाहिए. एमएलआई द्वारा उधारकर्ता से ली गई प्राथमिक प्रतिभूति की सुरक्षा करनी चाहिए. एम.एल.आई. द्वारा बकाया राशि की वसूली करने और ट्रस्ट के हितों की रक्षा करने में तत्परता बरतता और अकाउंट पर कड़ी निगरानी रखा जाना अपेक्षित है.

गारंटीकृत खाते में वसूली की सुविधा के लिए, या गारंटर के रूप में अपने हितों की सुरक्षा के लिए, समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. - विशेषताएं

कोई संपार्श्विक नहीं (हाइब्रिड सुरक्षा के मामले को छोड़कर)

कोई तृतीय पक्ष गारंटी नहीं

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आर.ओ.आई (31.10.2018 से प्रभावी)

एसएचजी को छोड़कर एम.एस.ई. क्षेत्र में सभी प्रकार की फर्म/कंपनियां या अन्य कानूनी रूप से गठित निकाय, व्यक्तिगत उधारकर्ता, छोटे व्यवसाय के लिए उधारकर्ता ₹500.00 लाख

शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान ने सी.जी.टी.एम.एस.ई. की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रति उधारकर्ता ₹500.00 लाख रुपये तक की गतिविधि को भी पात्र बना दिया है.

एम.एस.ई. खुदरा और थोक व्यापारियों की एक्सपोजर सीमा प्रति एम.एस.ई. उधारकर्ता ₹500 लाख रुपये तक है.

सी.जी.टी.एम.एस.ई.-हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल

सी.जी.टी.एम.एस.ई. हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल एक ऐसा उत्पाद है जो सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है, जबकि क्रेडिट सुविधा का शेष हिस्सा इसके अंतर्गत अधिकतम ₹500 लाख तक कवर किया जा सकता है.

हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल एमएलआई

के लिए एम.एस.ई. को ऋण देने में सहज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से वे जो पूरी ऋण राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. यह मॉडल एम.एस.ई. को अपनी पूरी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में रखे बिना वित्त तक पहुंच प्रदान करता है. संपार्श्विक सिक्योरिटी भी ली जा सकती है और इस संपार्श्विक सिक्योरिटी के आधार पर व्यक्तिगत गारंटी भी प्राप्त की जा सकती है.

क्रेडिट सुविधा के उस हिस्से के लिए गारंटी कवर जो संपार्श्विक द्वारा कवर नहीं किया गया है, अधिकतम प्रति उधारकर्ता 500 लाख तक की अनुमति है.

पारि -पासु शुल्क के बजाय एक कल्पित चार्ज होता हैं.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. गारंटी मंजूरी/बकाया या अधिकतम बकाया (कार्यशील पूंजी खातों के मामले में) संपार्श्विक सुरक्षा के कम मूल्य तक सीमित होगी.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. - कवरेज में अपात्र गतिविधियां

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पात्र नहीं हैं.

आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा मॉडल (हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल) के तहत पात्र ऋणों को छोड़कर किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी द्वारा समर्थित क्रेडिट सुविधा का हिस्सा है.

यह ब्याज दर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं ली जाती है.

गारंटी कवर की तिथि के अनुसार खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सी.जी.टी.एम.एस.ई. गारंटी कवरेज (01.04.2023 से)

उधारकर्ता श्रेणी	अधिकतम गारंटी कवरेज (01.04.2023 से)		
	5 लाख रु तक	5 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक	50 लाख रुपये से अधिक और 500 लाख
अति लघु उद्योग	85%	75%	
पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एम.एस.ई. (सिक्किम, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सहित)	80%		75 %
अग्निवीर से उमर का आनेवाली द्वारा महिला उद्यमियों/एम.एस.ई. हेतु	85%		
आकांक्षी जिले में स्थित एम.एस.ई.	85%		
ज़ेडईडो प्रमाणित एम.एस.ई.	85%		
एससी/एसटी उद्यमी/विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	85%		
उधारकर्ताओं की अन्य सभी श्रेणियां	75%		

सी.जी.टी.एम.एस.ई. : भविष्य एवं संभावनाएं

डिज़िटाइज़ेशन: सी.जी.टी.एम.एस.ई. आने वाले वर्षों में अपने परिचालन को डिज़िटाइ. जेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है. इससे ट्रस्ट की सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी.

कवरेज का विस्तार: सी.जी.टी.एम. एस.ई. अधिक एम.एस.ई. और अधिक प्रकार के ऋणों को शामिल करने के लिए अपने कवरेज का विस्तार करने की संभावना है. इससे वित्त तक पहुंच को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने में मदद मिलेगी.

नए उत्पाद और सेवाएँ: सी.जी.टी.एम.एस.ई. द्वारा एम.एस.ई. क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद और सेवाएँ विकसित करने की संभावना है. उदाहरण के लिए, ट्रस्ट हरित अर्थव्यवस्था या डिजिटल अर्थव्यवस्था में एम.एस.ई. का समर्थन करने के लिए नए उत्पाद विकसित कर सकता है.

निष्कर्ष : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम. एस.एम.ई.) राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इन आर्थिक लाभों के अलावा, एम.एस.एम.ई. राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाते हैं. वे पारंपरिक कौशल और शिल्प को संरक्षित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक विकास में योगदान देने में मदद करते हैं. इसलिए सतत आर्थिक विकास के लिए एम.एस.एम.ई. आवश्यक हैं. वे रोजगार सृजन और नवाचार के इंजन हैं, वे गरीबी और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एम.एस.एम.ई. को समर्थन देकर, सरकारें सभी के लिए अधिक समृद्ध और समावेशी भविष्य बनाने में मदद कर सकती हैं.

सुनील कुमार
यू.एल.ए., गुरुग्राम

आयात पर निर्भरता कम करने में एम.एस.एम.ई. की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं. वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ (एम.एस.एम.ई.) न सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं. गौरतलब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिक बाज़ार की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष ज़ोर दिये जाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रणनीति की दृष्टि से एम.एस.एम.ई. की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान नया नहीं है और उनके विकास को समर्थन देने के लिए अतीत में कई पहलें की गई हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस क्षेत्र को नए सिरे से प्रोत्साहन दिया है और एम.एस.एम.ई. को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं. ऐसा ही एक उपाय है आधार उद्योग मुफ्त योजना. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और स्वदेशी विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने में एम.एस.एम.ई. की आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है.

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 2020 में भारत सरकार द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था. इस मिशन का एक प्रमुख घटक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) का सशक्तिकरण है.

एम.एस.एम.ई. और भारतीय स्वतंत्रता : आजादी के शुरुआती दिनों से ही, एम.एस.एम.ई. का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. एम.एस.एम.ई. सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्तशिल्प, ऑटोमोटिव और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए हैं. इनकी वृद्धि और लचीलेपन ने आयात पर देश की निर्भरता को कम कर दिया है, जिससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान मिला है.

इसके अलावा, एम.एस.एम.ई. आपूर्ति श्रृंखला विकास को बढ़ावा देते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं जो विभिन्न उद्योगों का समर्थन करते हैं. आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी से अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ती है, जिससे यह अधिक आत्मनिर्भर हो जाती है और बाहरी व्यवधानों के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है.

भविष्य की ओर, एम.एस.एम.ई. नवाचार और तकनीकी उन्नति के अग्रदूत बने रहेंगे. उनकी चपलता उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, भारत को नवाचार का केंद्र बनाने और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की अनुमति देती है. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का विकास न केवल आर्थिक स्वतंत्रता में बल्कि रोजगार सृजन, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी योगदान देता है.

भारत में एम.एस.एम.ई. को समझना : एम.एस.एम.ई. भारत के औद्योगिक परिदृश्य का आधार है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, एम.एस.एम.ई. भारत की जीडीपी, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. यह क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख जनरेटर है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में.

एम.एस.एम.ई. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह भारत के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 45% और कुल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा हैं. इसका मतलब यह है कि एम.एस.एम.ई. देश की आर्थिक वृद्धि के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है. कपड़ा उद्योग में, एम.एस.एम.ई. का कुल रोजगार में लगभग 60% योगदान है. यह परिधान, जूते और अन्य उत्पादों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कृषि क्षेत्र में, एम.एस.एम.ई. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उर्वरक और कृषि मशीनरी जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन में शामिल हैं. कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सेवा क्षेत्र में, एम.एस.एम.ई. परिवहन, पर्यटन और खुदरा जैसी कई गतिविधियों में शामिल हैं. एम.एस.एम.ई. भारत में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं को रोजगार देता है. यह लगभग 111 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो देश के कार्यबल का लगभग 40% है.

आत्मनिर्भरता के लिए उत्प्रेरक: एम.एस.एम.ई. भारत की आत्मनिर्भरता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, विभिन्न माध्यमों से आर्थिक स्वतंत्रता लाते हैं. ये उद्यम देश की आयात पर निर्भरता को कम करने, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने और एक मजबूत और आत्मनिर्भर आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आयात पर भारत की निर्भरता को कम करके एम.एस.एम.ई. आत्मनिर्भरता में योगदान देने के प्राथमिक तरीकों में से एक है. घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके, एम.एस.एम.ई. विदेशी उत्पादों पर देश की निर्भरता को रोकने में मदद करते हैं. यह स्थानीयकृत उत्पादन न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव और व्यवधानों के खिलाफ इसके लचीलेपन को भी बढ़ाता है. स्थानीय मांग को पूरा करके और आयात को कम करके, एम.एस.एम.ई. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देते हैं जो बाहरी झटकों को बेहतर ढंग से झेल सकती है.

एम.एस.एम.ई. आपूर्ति श्रृंखला विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उद्योगों में परस्पर जुड़ाव का जाल बनता है. वे देश में उद्यमों की कुल संख्या का 60% हिस्सा हैं, और विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में ये उद्यम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों का समर्थन करते हैं. आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी घरेलू उत्पादन और वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देती है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भरोसा करने की आवश्यकता कम हो जाती है. देश की आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर यह परस्पर निर्भरता अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता को बढ़ाती है और इसकी आत्मनिर्भरता में योगदान देती है.

एम.एस.एम.ई. की नवीन भावना और चपलता घरेलू नवाचार और तकनीकी प्रगति में योगदान करती है. ये उद्यम बड़े निगमों की तुलना में अधिक फुर्तीले और लचीले हैं, जो उन्हें बदलती बाजार मांगों के लिए जल्दी से अनुकूलित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की अनुमति देते हैं. उनके द्वारा नवीन प्रथाओं और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से भारत की तकनीकी प्रगति में योगदान होता है और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है. जैसे-जैसे एम.एस.एम.ई. बढ़ते हैं और नवप्रवर्तन करते हैं, वे भारत के लिए नवप्रवर्तन का केंद्र बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान में एम.एस.एम.ई. की भूमिका : आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एम.एस.एम.ई. की महत्वपूर्ण भूमिका है. ये रोजगार, नवाचार और निर्यात के प्रमुख चालक हैं और उनकी वृद्धि भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है. निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जिनसे एम.एस.एम.ई. भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान दे सकते हैं:-

स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना : आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक मुख्य उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है. एम.एस.एम.ई. भारत में बनी वस्तुओं का उत्पादन करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. सही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, एम.एस.एम.ई. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं जो आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं.

रोजगार के अवसर पैदा करना : एम.एस.एम.ई. भारत में महत्वपूर्ण नियोक्ता हैं और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. सही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, एम.एस.एम.ई. अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां नौकरी के अवसर कम हैं. इससे न केवल बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी बल्कि देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में भी योगदान मिलेगा.

नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना : एम.एस.एम.ई. अपनी नवोन्मेषी और उद्यमशीलता भावना के लिए जाने जाते हैं. सही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, वे नई प्रौद्योगिकियां, उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं जो आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना सकती हैं. सरकार ने एम.एस.एम.ई. के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसे कई पहल शुरू किए हैं.

निर्यात को बढ़ावा देना : भारत के निर्यात में एम.एस.एम.ई. का महत्वपूर्ण योगदान है और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनकी वृद्धि आवश्यक है. सही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ, एम.एस.एम.ई. ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं. इससे न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश के लिए विदेशी मुद्रा भी उत्पन्न होगी.

निष्कर्ष : लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है. यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और रोजगार के बड़े अवसर का निर्माण करता है एम.एस.एम.ई. अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों को अपने में समाहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रछन्न बेरोजगारी की समस्या कम करने में सहायक है. एम.एस.एम.ई. सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक भी है और द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस तथ्य को देखते हुए कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है और आयात को कम करता है यह आवश्यक है कि इन्हे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एकीकृत होना चाहिए क्योंकि यह तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनने का एक अवसर है. जीवीसी का हिस्सा होने से एम.एस.एम.ई. गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम बनेंगे जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक स्वीकार्यता होगी.

शशि भूषण कुमार
क्षे.का., पटना

स्वतंत्रता दिवस समारोह

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अंचल प्रमुख, भोपाल

अंचल प्रमुख, हैदराबाद.

अंचल कार्यालय, गांधीनगर

केंद्रीय कार्यालय एनेक्स मंगलूरु और अंचल कार्यालय, मंगलूरु

अंचल कार्यालय, पुणे

अंचल कार्यालय, विजयवाड़ा

अंचल कार्यालय, राँची

अंचल कार्यालय, कोलकाता

क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी

क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय कार्यालय, बालेश्वर

क्षेत्रीय कार्यालय, रायगड़ा

क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, कलबुरगी

क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ

पारंपरिक उद्योगों का महत्व

अक्सर हम समाचार पत्र एवं औद्योगिक प्रकाशनों में पारंपरिक उद्योग के बारे में पढ़ते या जानकारी प्राप्त करते हैं. पर पारंपरिक उद्योग की परिभाषा क्या है? पारंपरिक उद्योग आर्थिक गतिविधियाँ हैं जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए पारंपरिक तकनीकी, शारीरिक श्रम और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है. यह उद्योग आमतौर पर पीढ़ियों से किसी क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और वे अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय रीति-रिवाजों, कौशल और सामग्रियों को प्रतिबिंबित करते हैं. पारंपरिक उद्योग किसी देश के विरासत के प्रमुख घटक हैं, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं. भारत के पारंपरिक उद्योगों के कुछ उदाहरण है:

हस्तशिल्प: कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, गहने और धातु का काम जिसमें हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन शामिल है. ये शिल्प अक्सर सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़े होते हैं और कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं.

हैंडलूम और खादी वस्त्र: पारंपरिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके कपड़े और वस्त्रों की बुनाई, जिसमें कपास, रेशम और ऊन जैसी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है.

कृषि उत्पादन: पारंपरिक खेती और कृषि पद्धतियाँ जिनमें फसलों की खेती, पशु पालन और छोटे पैमाने की कृषि संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं.

खाद्य प्रसंस्करण: पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण विधियाँ जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, खमीरीकरण, खाद्य पदार्थों को सुखाना, आदि.

कुटीर उद्योग: छोटे पैमाने पर विनिर्माण या उत्पादन गतिविधियाँ जो आमतौर पर घरों या छोटी कार्यशालाओं में की जाती हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, मिठाई के डिब्बे बनाना, कागज उत्पादन इत्यादि.

मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी की वस्तुएं: मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण, स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी का उपयोग करके किया जाता है और हाथ से या सरल उपकरणों का उपयोग करके आकार दिया जाता है.

हर्बल और पारंपरिक चिकित्सा: स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं के आधार पर हर्बल उपचार, पारंपरिक दवाओं और हर्बल तेल आदि का उत्पादन किया जाता है.

हस्तकला और हस्तशिल्प उत्पादन: पेंटिंग, मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं का निर्माण, जो स्थानीय कला और कलाकारी के माध्यम से उस क्षेत्र की परंपराओं को दर्शाते हैं.

मछली पालन और जलीय कृषि: मछली पकड़ने और जलीय कृषि के पारंपरिक तरीके स्थानीय रूप से निर्मित नावों और जालों का उपयोग करते हैं.

पारंपरिक संगीत और प्रदर्शन कलाएँ: पारंपरिक संगीत, नृत्य और रंगमंच का प्रदर्शन, जो अक्सर किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग होते हैं.

पारंपरिक उद्योगों का महत्व: पारंपारिक उद्योग ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और वे सांस्कृतिक परंपराओं तथा प्रथाओं को संरक्षित करते हुए लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं. जबकि पारंपरिक उद्योग अपनी प्रामाणिकता और शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं. पारंपरिक उद्योगों को समर्थन देने और बनाए रखने के प्रयास सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास और इन गतिविधियों में शामिल लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं. पारंपरिक उद्योग किसी समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनका महत्व विभिन्न प्रकार से देखा जा सकता है:

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: पारंपरिक उद्योग किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़े होते हैं. वह उन स्थानीय रीति-रिवाजों, शिल्प कौशल और पारंपरिक कौशल का संरक्षण करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं. यह उद्योग किसी समुदाय के इतिहास, कला और परंपराओं से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं.

सांस्कृतिक विविधता: पारंपरिक उद्योग किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं. विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग पारंपरिक उद्योग हो सकते हैं, जो उन क्षेत्रों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं.

कौशल और ज्ञान हस्तांतरण: पारंपरिक उद्योग पारंपरिक ज्ञान और कौशल के भंडार के रूप में कार्य करते हैं. यह ज्ञान आमतौर पर पुरानी पीढ़ियों से नई पीढ़ी तक विरासत के रूप में दिया जाता है, जिससे अद्वितीय तकनीकों और विशेषज्ञता की निरंतरता सुनिश्चित होती है. ये कौशल सांस्कृतिक प्रथाओं और शिल्प कौशल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास: पारंपरिक उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, जो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में. वे बेरोजगारी को कम करने में मदद करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए आय-सृजन के अवसर प्रदान करते हैं.

पर्यावरण-अनुकूल: कई पारंपरिक उद्योग टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर आधारित हैं. वे स्थानीय रूप से उपलब्ध, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और रसायनों और मशीनरी का न्यूनतम उपयोग करते हैं, जिससे वे पर्यावरण-अनुकूल बन जाते हैं.

पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन: पारंपरिक उद्योग सांस्कृतिक पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं. पर्यटक अक्सर उन स्थानों पर जाकर अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं जहां पारंपरिक शिल्प बनाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पारंपरिक उत्पाद बेचे जाते हैं. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय समुदायों को अतिरिक्त आय मिल सकती है.

निर्यात और आर्थिक विकास: हस्तशिल्प, कपड़ा, पारंपरिक खाद्य उत्पाद और पारंपरिक उद्योगों से अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, जो देश की आर्थिक वृद्धि और विदेशी मुद्रा आय में योगदान देता है.

सामुदायिक सामंजस्य: पारंपरिक उद्योग करीबी समुदायों द्वारा चलाए जाते हैं. यह सामाजिक सामंजस्य और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है, सामुदायिक एकता को बढ़ाता है.

पारंपरिक उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ: भारतीय पारंपरिक उद्योगों का एक लंबा इतिहास है. ये उद्योग न केवल क्षेत्रीय असमानता को कम करने और आय तथा धन के न्यायसंगत वितरण में महत्वपूर्ण योगदान देता हैं, बल्कि अपेक्षाकृत कम पूंजी पर ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशेष उत्पादों का विकास पारंपरिक उद्योगों के उत्पादों के लिए एक सुअवसर है, परन्तु पारंपरिक उद्योगों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, बाजारों तक सीमित पहुंच, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता, तकनीकी अक्षमता, पूंजी के कम साधन, अपर्याप्त मार्केटिंग और ब्रांडिंग इत्यादि शामिल है.

इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रौद्योगिकी में निवेश, कौशल विकास, वित्त तक पहुंच, ब्रांडिंग और सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है. सरकारी पहल और उद्योग संघ इन कठिनाइयों को दूर करने और तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में पारंपरिक उद्योगों को पनपने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. ऐसा करने से, एक समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि पारंपरिक उद्योग उसके आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें.

पारंपरिक उद्योगों के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल: भारत सरकार ने पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ 2005 में एक कोष बनाया था, जिसका लक्ष्य इन व्यवसायों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके सतत विकास में सहायता करना है. इस प्लानिंग के साथ 'स्कीम ऑफ़ फण्ड फॉर रीजेनरेशन ऑफ़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI-स्फूर्ति)' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई. 'स्फूर्ती' का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक उद्योग में ग्रामीण उद्यमियों और शिल्पकारों को स्थायी रूप से रोजगार देना है. यह कार्यक्रम समूहों में सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण, उन्नत उपकरणों के वितरण, नए उत्पाद विकास आदि में भी सहायता प्रदान करता है ताकि उनके उत्पाद बाजार द्वारा संचालित हों. उत्तर-पूर्वी राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में, एम.एस. एम.ई. मंत्रालय ने अब तक 513 क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 336 क्लस्टर क्रियाशील हैं.

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने और भी कई सारी योजनाएँ निकाली है जैसे क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस). इस स्कीम के तहत, 15% अग्रिम पूंजी सब्सिडी देकर, खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग इकाइयों जैसी छोटी कंपनियों को अपनी तकनीक उन्नत करने में मदद करता है. प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2008 में शुरू की गई यह योजना एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करना है.

निष्कर्ष : भारत में पारंपरिक उद्योग विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण हैं. वे न केवल देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करते हैं बल्कि आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में भी योगदान देते हैं. इन उद्योगों को समर्थन देना उन कुशल कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं. इसके अलावा, कई पारंपरिक उद्योग पर्यावरण संरक्षण की आधुनिक मांगों के अनुरूप टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करते हैं. इन उद्योगों का समर्थन करके, भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर सकता है, ग्रामीण रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है, और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है अंततः देश में समग्र विकास और एक संतुलित आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा दे सकता है.

लीना सैकिया
अं.का., पुणे

एम.एस.एम.ई. : ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण का उपाय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में अत्यधिक जीवंत और गतिशील हुआ है और इसके महत्व को सारी दुनिया ने पहचाना है. एम. एस.एम.ई. किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख अंग है. एम.एस.एम.ई. न केवल आर्थिक विकास एवं उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीरण में भी मदद करते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है. एम.एस.एम.ई. देश के प्राकृतिक सम्पत्तियों, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्र धन के न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान देते हैं. सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के लिए पूरक का काम करते हैं. वर्तमान में देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इनका योगदान बढ़ता ही जा रहा है.

जहां तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने विभिन्न अवसरों और चुनौतियों को जन्म दिया है, वहीं भारत में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए उत्पादकता बढ़ाने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के भी कई अवसर खुले हैं. भारत द्वारा किए गए अन्तरिक्ष मिशन में कई कल-पुर्जे छोटे एवं मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए गए थे जिसके कारण इन इकाइयों को एक नई पहचान मिली है.

भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है. यह हिस्सा आज भी पारंपरिक कृषि एवं मानसून पर निर्भर है और अपनी पूरी ज़िंदगी कृषि और मानसून के भरोसे गुजार देता है. पारंपरिक कृषि एवं मानसून पर निर्भरता इन्हें कई बार बड़ी मुश्किल में डाल देती है परंतु इनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है. सरकार इनके विकास के लिए हमेशा नए-नए कदम उठाती है एवं इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है पर यह इतना आसान नहीं है. कृषि एवं मॉनसून पर निर्भरता को कम करने के लिए इनके पास दूसरा विकल्प होना जरूरी है. एम.एस.एम.ई. उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो इन्हें दूसरा विकल्प प्रदान कर सकता है. एम.एस.एम.ई. उद्योग काफी कम लागत में स्थापित किए जा सकते हैं एवं सरकार भी ऐसी इकाइयों के लिए कई तरह की सब्सिडी देती है. ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार कैसे इन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

किसी भी व्यवसाय में कुछ जोखिम के कारक होते हैं और कुछ चुनौतियाँ होती हैं. ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ और उनका समाधान इस प्रकार हैं:

व्यवसाय की समझ एवं कौशल :

ग्रामीण परिवेश में खुद का व्यापार स्थापित करने एवं उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए जरूरी समझ और कौशल की कमी होती है क्योंकि . ज्यादातर लोग कृषि के काम में ही निपुण होते हैं और उद्योग चलाने के लिए जरूरी कौशल या मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता. इसकी कमी से ही ग्रामीण एवं पिछड़े प्रांत के लोग खुद का उद्योग स्थापित करने का जोखिम उठाने से डरते हैं. ऐसे में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचने वालों को नि:शुल्क जानकारी एवं मार्गदर्शन देने वाली संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए जो किसी भी समय उनकी सहायता के लिए उपलब्ध हो. साथ ही उद्योग स्थापना का दृढ़ निश्चय करने वालों को उस क्षेत्र में जरूरी कौशल की शिक्षा देने का कार्य भी होना चाहिए.

उद्योग एवं उससे जुड़े नियामक एवं विधिक प्रक्रिया की जानकारी:

किसी भी उद्योग के लिए कई नियामक एवं विधिक प्रक्रियाएँ हैं, जैसे जीएसटी निबंधन, अग्निशामक बोर्ड से मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी आदि कई प्रक्रियाएँ पूरी करनी होती है, जिसके लिए जरूरी जानकारी एवं प्रावधान के बारे में उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई होना चाहिए. इसके लिए एक ही स्थान पर सभी तरह के निबंधन करवाने की सुविधा होनी चाहिए एवं उसके लिए जरूरी कागजात एवं दस्तावेज़ तैयार करने के लिए भी एक प्राधिकरण होना चाहिए जो उद्यमी को इन सभी पेचीदे काम में उलझने से बचा सके. समय-समय पर इन मंजूरियों की पुनरीक्षा के लिए भी मार्गदर्शन एवं सहयोग का प्रावधान होना चाहिए.

वित्तीय लेखा-जोखा एवं लाभ-हानि का सही आकलन करने की समझ :

किसी भी व्यवसाय के लिए उसके लाभ-हानि का लेखा-जोखा बहुत जरूरी होता है जो उसके लागत मूल्यों, उत्पादन क्षमता एवं उत्पादकता के साथ-साथ उसके विक्रय मूल्य एवं बाज़ार में उसके प्रतिस्पर्धिता को भी निर्धारित करता है. ऐसी स्थिति में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों के लिए वित्तीय लेखा-जोखा एवं लाभ-हानि का हिसाब रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी इकाई का रिकॉर्ड पूरी तरह गोपनीय ढंग से सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर उस इकाई का पूरा ब्यौरा हासिल कराया जा सके.

कच्चे माल से दूरी एवं दर इकाई उत्पादन लागत का अधिक होना:

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर

किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एक प्रमुख चुनौती है. चाहे वह लोहा हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, धागा हो या किसी भी तरह का कोई भी कच्चा माल, उसे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक लाने का खर्च ही बहुत ज्यादा हो जाता है. साथ ही मांग तथा पूंजी की उपलब्धता के हिसाब से ये इकाइयां छोटी-छोटी मात्रा में कच्चे माल मांगा सकती हैं जिसके कारण दर इकाई लागत मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है. ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि कच्चे माल को क्षेत्रीय स्तर / ग्रामीण स्तर पर संचित किया जाए एवं विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों के संचयन की समुचित व्यवस्था की जाए. इसमें ग्रामीण इकाइयों द्वारा साझा किए जाने वाले तर्ज पर संयुक्त संचयन की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है जिससे इकाइयों के लागत मूल्य में कमी लायी जा सकती है एवं कच्चे माल की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है.

विपणन के लिए बाजार :

किसी भी व्यवसाय के लिए बाज़ार की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की खपत के लिए ग्रामीण बा. जार काफी नहीं हैं. उचित मूल्य और उचित बिक्री स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यापक बा. जार की उपलब्धता एक अति महत्वपूर्ण कारक है. परंतु ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों जैसे शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की दूरी के कारण एवं अत्यधिक दर इकाई परिवहन पर होने वाले खर्च के कारण प्रतिस्पर्धिता पर संशय हो सकता है. अत: ऐसी स्थिति में पुन: साझा स्तर पर परिवहन एवं संचय की व्यवस्था करने से ग्रामीण उत्पादों को उचित बाज़ार, उचित मूल्य और उचित लाभ मिलने की पूरी संभावना है.

उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं :

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जहां बिजली, पानी, सड़क आदि की सहज उपलब्धता में कमी होती है या उनकी गुणवत्ता पर संशय होता है, वहाँ किसी भी उद्योग के फलीभूत होने पर भी संशय होता है क्योंकि बुनियादी सुविधाओं की कमी से विभिन्न तरह की समस्याएँ जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वाहनों की रख-रखाव पर अत्यधिक खर्च, बिजली की कमी से उत्पादन में समस्याएँ आदि ऐसी कई समस्याएँ हैं जिनसे ग्रामीण इकाइयों के भविष्य पर खतरा मँडराता है. ऐसी स्थिति में हर लक्षित गाँव एवं क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र / सोसाइटी की स्थापना एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिसमें ग्रामीण इकाइयों के लिए मूलभूत सुविधाएं एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं. इससे ग्रामीण इकाइयों की कुछ मुश्किलें जरूर कम हो जाएंगी.

जैसा कि पाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त सभी समस्याओं से वहाँ के निवासियों में उद्यमिता के जोखिम उठाने का हौसला नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में उपर्युक्त उपायों से उनकी कुछ समस्याओं एवं चुनौतियों को हल किया जा सकता है. यह सही है कि सरकार प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट अप योजना, स्टैंड अप योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे कई योजनाओं के द्वारा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करती है; बैंक भी कई प्रकार की नयी-नयी योजनाएँ लाकर लोगों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, परंतु निश्चय ही, उपर्युक्त चुनौतियाँ इन सभी योजनाओं पर भारी पड़ रही हैं इसीलिए ग्रामीण वर्ग उद्यमिता का जोखिम उठाने से डर रहा है.

ऐसी स्थिति में यह एक बहुत सही विकल्प होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबन्धित उद्योगों को ज़ोर-शोर से बढ़ावा दिया जाए क्योंकि ऐसे उद्योगों में कच्चा माल कृषि उत्पाद ही होते हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं. इससे निम्न समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है:

कृषि उत्पादों का उत्पादन सामयिक होता है जबकि इसकी जरूरत पूरे साल होती है. इसलिए कृषि उत्पादों का संग्रहण सही तरीके से होना बहुत जरूरी है. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में उद्यमिता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है.

ज़्यादातर ग्रामीण लोग कृषि उत्पादों से पूरी तरह वाकिफ होते हैं अत: उनके लिए इस क्षेत्र में उद्यम लगाना मुश्किल नहीं होगा. कृषि क्षेत्र में सामयिक बेरोजगारी बहुत हानिकारक होती है क्योंकि बोवाई के बाद किसानों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है. ऐसी स्थिति में सामयिक बेरोजगारी के दौरान वो अपने उद्यम पर पूरा ध्यान दे सकते हैं.

भारत में ज्यादातर लोग धान और गेहूँ की खेती करते हैं और व्यावसायिक फसलों की पैदावार काफी कम होती है. इसका कारण उनके संग्रहण में आने वाली कठिनाइयाँ हैं. हालांकि व्यावसायिक फसलों की मांग एवं विक्रय मूल्य में निरंतरता रहती है पर किसान उस जोखिम के लिए तैयार नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में उचित संग्रहण के जरिये किसान अपने व्यावसायिक फसलों का उचित मूल्य साल भर पा सकता है.

यह सर्वविदित है कि कृषि उत्पादों का जो मूल्य बाज़ार में होता है उससे कहीं कम किसानों को मिलता है. इसका प्रमुख कारण उसके संग्रहण पर होने वाले खर्च हैं. ऐसे में अगर किसान अपने उत्पादों का संग्रहण अपने ही उद्योगों में करे या उन कृषि उत्पादों के और बेहतर उपयोग की कोई विधि निकाल ले तो उसे अपने उत्पादों का और उचित मूल्य मिल सकता है.

अत: यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सरकार को आर्थिक सहायता के अलावा साझा स्तर पर परिवहन, संग्रहण, संचयन, एवं अन्य साझा सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए. किसी भी व्यवसाय के लिए आय की निरंतरता ही उद्यमी को जोखिम लेने के लिए तैयार कर सकती है. इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए. उपर्युक्त सभी उपायों से यह संभव है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोग उद्यम स्थापित करने की प्रेरणा ले सकें एवं जोखिम उठाने को तैयार हो सकें.

कुन्दन कुमार सिन्हा
जेड.ए.ओ., विशाखपट्टणम

एम.एस.एम.ई. : भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय परिप्रेक्ष्य में एम.एस.एम.ई. का महत्वपूर्ण स्थान है. भारत एक कृषि प्रधान देश है और आबादी की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है. भारत की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी अधिक है और यह आबादी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अमृत का कार्य कर रही है. आज विश्व भर में भारत ही एकमात्र देश है, जिसके पास युवा कार्यशील पूँजी सबसे अधिक मात्रा में है.

भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला एम.एस.एम.ई. क्षेत्र ही है. वर्तमान में लगभग 6.5 करोड़ सक्रिय एम.एस.एम.ई. इकाइयाँ लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं.

अत्यधिक आबादी के कारण भारत ज्यादातर वस्तुओं के आयात पर निर्भर है, लेकिन सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, स्टैंड अप इंडिया आदि. इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न देशों से सम्पर्क कर उनके वहाँ स्थापित उद्योगपतियों से भारत में निवेश हेतु विभिन्न सुविधाओं का वायदा किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी देश में उद्योगों का विकास होता है तो उसका चहुँ ओर प्रभाव होता है और वह देश की अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अभिवर्धन करता है.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है. इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम सरकार द्वारा पुरानी चली आ रही एम.एस.एम.ई. की परिभाषा को बदलने का कार्य किया गया ताकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सही आकलन किया जा सके. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का भी इसमें अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है. विभिन्न सरकारी पोर्टल के द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में पारदर्शिता का विकास हो रहा है, साथ ही यह सभी हितधारको में एक नए आत्मविश्वास को जन्म दे रहा है.

भारत में आज कई युवाओं द्वारा स्टार्ट अप स्थापित किये जा रहे हैं. ये स्टार्ट अप्स न केवल उन युवाओं के अपने आईडिया को वास्तविकता में बदलने का मौका दे रहे हैं, अपितु यह दूसरे युवाओं में भी एक नए जोश का संचार कर रहे हैं और उनमें उद्यमिता का विकास कर रहे हैं.

भारतीय युवा आबादी को एकीकृत करने में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इससे न केवल बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाई जा सकती है, अपितु यह सामाजिक असमानता को भी कम करने में सहायक भूमिका निभा सकता है. भारतीय परिप्रेक्ष्य में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका व जिम्मेदारी है.

भारत में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार कई प्रकार के संबल लेकर आई है. अगर बड़े पैमाने पर देखें तो देश में वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु सरकार पीएलआई (प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव) स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम के माध्यम से सरकार बड़े उद्योगों व उत्पादनकर्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. इसकी वजह से न केवल देश में होने वाले आयात में कमी आएगी, अपितु निर्यात संवर्द्धन से विदेशी मुद्रा भण्डार में भी इज़ाफ़ा होगा. साथ ही अपने उत्पादन को बढ़ाने हेतु इन उद्योगों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमताओं की अभिवृद्धि की जा रही है, जिससे देश में एम.एस.एम.ई. के लिए एक नया बाजार निर्मित हो गया है, साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने स्तर पर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है. जैसे कई सरकारें कई प्रकार के लाइसेंस व कागजी कार्यवाही में राहत प्रदान कर रही है, साथ ही टैक्स आदि में रियायतें प्रदान कर रही हैं. सरकारों द्वारा नव उद्यमिता को पोषित करने हेतु कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र हर जगह मौजूद है, सुई से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक किसी न किसी प्रकार से एम.एस.एम.ई. जुड़ा हुआ है. एक बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में इस क्षेत्र का अपना महत्व है. साथ ही, अब भी कई एम.एस.एम.ई. इकाईयाँ हैं जो पारंपरिक तौर-तरीकों से चालित हैं, वे अभी तक एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर नहीं आई हैं और सरकारों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रही हैं.

भारत एक विकासशील देश है और आज भारत को आर्थिक दुनिया की पाँच बढ़ती ताकतों में गिना किया जाता है. साथ ही मानव संसाधनों की प्रचुरता ने भी विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान भारत की ओर खींचा है. आज भारत विश्व में एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार बन कर उभरा है और यही सारी परिस्थितियाँ भारत के एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए संजीवनी बूटी का कार्य कर रही हैं.

देश के आर्थिक रखवाले अर्थात् बैंकों द्वारा भी एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं. आज एम.एस.एम.ई. इकाई को आसानी से ऋण उपलब्ध हो इस दिशा में भी बैंकों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली व नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहें हैं. इन सभी सकारात्मक कदमों के चलते आज देश में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र अपने सबसे अच्छे समय से गुजर रहा है. साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र के भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अहम भूमिका है और देश की अर्थव्यवस्था की धुरी इसी क्षेत्र पर निर्भर है.

अशोक कुमार धाकड़
एम.एल.पी., उदयपुर

M.S.M.E. : An Indian Perspective

Introduction : Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Sector has long been recognized as the backbone of India's economy and plays a pivotal role in fostering economic growth, employment generation, and poverty alleviation. With over 63 million registered MSMEs, this sector contributes significantly to the Gross Domestic Product (GDP) of India.

Definition and Classification : In India, MSMEs are categorized based on their investment in plant and machinery or equipment. These classifications have evolved over time, with revisions in 2015 and 2020 to better align with the changing economic landscape.

Micro Enterprises: These are the smallest entities, typically owned and operated by a single individual. Micro-enterprises have investments of upto ₹1 crore in plant and machinery or equipment and annual turnover not more than Rs. 5 crores.

Small Enterprises: Small enterprises are slightly larger than micro-enterprises. They have investments between ₹1 crore and ₹10 crores in plant and machinery or equipment and annual turnover not more than Rs. 50 crores.

Medium Enterprises: Medium enterprises are the largest among MSMEs, with investments ranging from ₹10 crores to ₹50 crores in plant and machinery or equipment and annual turnover not more than Rs. 250 crores.

MSMEs are the lifeblood of the Indian economy for several reasons:

Employment Generation: MSMEs are one of the largest employers in India, providing jobs to millions of people, including those in rural areas. They are crucial in reducing unemployment and underemployment.

Contribution to GDP: MSMEs contribute significantly to India's GDP, accounting for approximately 29% of the GDP as of 2020. Their role in economic development cannot be overstated.

Promoting Entrepreneurship: MSMEs nurture entrepreneurship. They offer opportunities for individuals with innovative ideas and limited resources to establish and grow their businesses.

Regional Development: MSMEs are dispersed across the country, including rural and backward regions. Their presence helps in regional development by reducing regional disparities.

Export Growth: MSMEs play a vital role in India's export sector, contributing to around 49% of the country's total exports. They manufacture a wide range of products that find markets worldwide.

Factors that have led to the growth of M.S.M.E.: Increasing internet penetration, customer's familiarization with digital payments fuelled by B2C ecommerce players facilitate M.S.M.E. sector growth.

Tie-ups with new-age non-banking finance (FinTech) companies allowed access to timely collateral free finance to MSMEs.

It provides opportunity for budding entrepreneurs to build creative products boosting business competition and fuels growth.

Small industries and retail businesses in tier-II and tier-III cities create opportunities for people to use banking services and products.

Campaigns like Skill India, Startup India, Digital India and Make in India aim to provide M.S.M.E. players with a level playing field and a definitive push towards enhanced productivity.

Younger generations shift from agriculture towards entrepreneurial activities creates job prospects for others.

Challenges Faced by MSMEs

MSMEs face numerous challenges that hinder their growth and sustainability viz., Lack of Access to Finance, Infrastructure Deficiencies, Limited Technological Adoption, Regulatory Compliance, Skill Gaps and Marketing and Access to Markets.

Government Initiatives to Support MSMEs : The Indian government has recognized the critical role of MSMEs in the country's economic development and has implemented

various policies and initiatives to address their challenges and promote growth:

Financial Support: The government has launched schemes like the Pradhan Mantri Mudra Yojana to provide financial support to MSMEs, particularly micro-enterprises, through loans and credit facilities.

Credit Guarantee Fund Scheme: The Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises helps MSMEs secure collateral-free loans up to ₹5 crores.

Technology Upgradation: The Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) provides incentives for technological improvements and modernization of MSMEs.

Ease of Doing Business: Various measures have been taken to simplify regulatory compliance and reduce the bureaucratic burden on MSMEs.

Market Linkages: The government encourages MSMEs to participate in government procurement through schemes like the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs).

Skill Development: Skill India is an initiative aimed at enhancing the employability of the Indian workforce, including in the M.S.M.E. sector.

Export Promotion: Export-oriented MSMEs receive support through various schemes and incentives, such as the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme.

MSMEs in a Post-Pandemic World

The COVID-19 pandemic had a profound impact on MSMEs in India. The lockdowns and disruptions in supply chains hit these enterprises hard. However, they also demonstrated remarkable resilience and adaptability. Many MSMEs shifted their focus to produce essential goods like personal protective equipment (PPE) and hand sanitizers during the pandemic, showcasing their ability to pivot quickly in response to changing circumstances.

In the post-pandemic world, MSMEs are poised to play a pivotal role in India's economic recovery. Here are some key considerations:

Digital Transformation: The pandemic accelerated the adoption of digital technologies among MSMEs. Going forward, investing in digital infrastructure and e-commerce capabilities will be crucial for growth.

Supply Chain Resilience: MSMEs need to reassess their supply chain strategies to ensure resilience in the face of future disruptions. Diversifying suppliers and adopting just-in-time inventory practices can help.

Export Opportunities: As global markets recover, MSMEs should explore export opportunities. The government's export promotion schemes can provide support in this regard.

Sustainable Practices: There is growing global demand for sustainable products and practices. MSMEs that prioritize sustainability can tap into this market and gain a competitive edge.

Access to Finance: Improving access to finance remains a priority. Fintech solutions and alternative lending platforms can help bridge the credit gap for MSMEs.

Collaboration: MSMEs can benefit from collaboration and networking. Industry clusters and associations can facilitate knowledge sharing and collective marketing efforts.

Model that can be learned from other economies:

By providing employment and income, SMEs can raise income, living standards and consumer spending. SMEs can aiding the atmanirbharta vision, especially in the manufacturing sector. This pattern is observed in countries with strong manufacturing sectors such as Germany and China. China's pattern is more relevant to India due to a similarity in size and population as well as its recency. SMEs make up over 99% of all enterprises in China today, with an output value of at least 60% of its GDP; they generate more than 82% of employment opportunities.

As per China's national economic census, manufacturing SMEs accounted for nearly 53% of its total incorporated SMEs and 65% of the total employment in SMEs.

With global manufacturing moving out of China, our SMEs can play a key role in sustaining the manufacturing that is shifted to India.

Some other gaps remain, needing urgent attention:

A primary one is the regulatory framework for SMEs that prevents a growth-oriented mindset.

The concessions awarded to SMEs in terms of tax-breaks and low interest rates must be extended beyond what is currently provided if they are to target higher growth rate.

Credit access to SMEs as well as the mechanism to seek payment from buyers needs bettering to ensure financial viability.

The present redressal system on recovery of payments, particularly from organisations with influence such as PSUs, may discourage SMEs from pursuing formal action against defaulters.

SMEs may find it difficult to choose grievance redressal over building business relationships with large buyers who may falter on timely payments.

Priority ought to be given to scaling up economies with state support as the gains from such support in generating employment and overall economic prosperity outweigh the economic costs.

Conclusion : MSMEs are the lifeblood of the Indian economy, driving growth, employment, and innovation. Despite the challenges they face, they have demonstrated remarkable resilience and adaptability, particularly in the face of the COVID-19 pandemic. With the right support, including continued government initiatives, improved access to finance, and investments in technology, MSMEs are poised to lead India's economic recovery and contribute significantly to its journey towards becoming a global economic powerhouse. MSMEs deserve attention, support, and recognition for their invaluable contribution to India's development and prosperity. The Indian M.S.M.E. sector acts as a bulwark for the Indian economy, providing resilience to ward off global economic shocks and adversities. India needs to ease the regulatory burden of small units and aid their survival through fiscal support. Above all, they need a level-playing field vis-à-vis big business.

Joy Ghosh
Z.L.C.,
Bhubaneswar

बधाई

दिनांक 24.08.2023 एवम् 25.08.2023 को श्री बृजेश कुमार तिवारी, क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली ने "कौन बनेगा करोड़पति" में सहभागिता की.

दिनांक 02.07.2023 को भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद कार्यालय द्वारा आयोजित वॉकथॉन प्रतियोगिता-2023 में क्षे.का. अहमदाबाद से तीन स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में श्री सिद्धार्थ मालिक जी को प्रथम और श्री अमरदीप सिंह जी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा वॉकथॉन पूरा करने पर श्री दीपक चावड़ा को मेडल प्राप्त हुआ है.

सीएसआर गतिविधियां

बैंक की सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत सुश्री ए.मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में दिव्यांग बच्चों की सेवा से जुड़ी एनजीओ संस्था शिशु सरोथी ट्रस्ट को कंप्यूअर, एसी, वाटर कूलर, कुर्सियां आदि भेंट किया गया.

दिनांक 22.09.2023 को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी के क्षेत्र प्रमुख श्री गौरव कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र ज्योलीकोट, नैनीताल के ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह को मोम भेंट की.

दिनांक 27.09.2023 को मऊ क्षेत्र द्वारा "एमपावर हर" योजना के तहत श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख के कर कमलों से सोनी धापा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज, मऊ में छात्राओं को शुद्ध एवं शीतल पेय जल की सुविधा के लिए वॉटर कूलर प्रदान किया गया.

दिनांक 08.09.2023 को इंदौर में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए मणिमेखलै ने महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ई-रिक्शा वितरित किए.

दिनांक 18.08.2023 को गाजीपुर के गहमर में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में सीएसआर गतिविधि के अंतगर्त वाटरकूलर, कुर्सी के साथ बैंक के विभिन्न ग्राहकों को बार कोड भी वितरीत किया गया.

दिनांक 24.08.2023 को मऊ द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख के कर कमलों से स्ट्रीट वेंडर्स एवं फेरी वालों को बैंक का लोगो मुद्रित छाता वितरित किया गया.

दिनांक 09.09.2023 को श्री जी एन दास, महाप्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय, श्री सर्वेश रंजन, अंचल प्रमुख, श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख द्वारा प्रोजेक्ट पावर के तहत स्कूल में खेल गतिविधि के लिए सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर के प्राचार्य को पोर्टा केबिन (स्पोर्टस यूटिलिटी) सुपुर्द की गई.

दिनांक 05.08.2023 को कस्तूरबा छात्रालय में हरिजन सेवक संघ के सहयोग से पावर हिम कार्यक्रम का आयोजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा द्वारा किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री ऋषिकेश मिश्रा, प्रमुख-एलएंडडी एवं बड़ौदा क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख श्री प्रशांत एम देसाई जी उपस्थित हुए.

दिनांक 17.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, आणंद द्वारा सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत मेघवा(गाना) प्राथमिक विद्यालय के 118 स्कूली छात्रों को स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई. इस अवसर पर श्री रमेश बजरोदिया, उप क्षेत्र प्रमुख; स्कूल प्रिंसिपल; सरपंच ग्राम पंचायत और आर्या चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

दिनांक 01.09.2023 को श्रीमती रेणु नायर, महा प्रबंधक द्वारा पुन्नक्कल भगवती मंदिर में ई-हुंडी की भेंट.

दिनांक 15.09.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय पुणे मेट्रो की ओर से वाघोली शाखा द्वारा नारी सशक्तिकरण मुहिम के अंतर्गत, भारत के प्रथम प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वाडेबोल्हाई, वाघोली को "नर्सिंग पॉड" प्रदान किया गया.

दिनांक 05.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, आणंद में प्रोजेक्ट पावर के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया. श्री ऋषिकेश मिश्रा, प्रमुख- एल एंड डी, क्षेत्र प्रमुख श्रीमती ऋचा जाजोरिया; श्री भानू प्रताप सिंह एवं श्री रमेश बजरोलिया उपक्षेत्र प्रमुख एवं स्कूल प्रबंधक की उपस्थिति में दृष्टिबाधित दिव्यांग मंडल स्कूल, मोगरी में सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत बैंक द्वारा स्कूली बच्चों को जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की किट दी गई.

दिनांक 31.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय,बेंगलूरु उत्तर से सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत कर्नाटक परीक्षा प्राधिकार, बेंगलूरु को 10 कंप्यूटर प्रदान किया गया.

MSMEs : Challenges and Solutions

MSMEs can play a significant role in creating an inclusive and sustainable society. They encourage a balanced regional development, gender equality, and the use of banking services and products. MSMEs can become the 'growth engine of the nation.

Challenges faced by MSMEs:

Financial Constraints: This is a significant impediment for the M.S.M.E. sector. with only 16% of SMEs having timely access to finance, forcing small and medium-sized businesses to rely on their own resources.

Lack of Formalisation: Almost 86% of the country's manufacturing MSMEs are unregistered. Only about 1.1 crore of the 6.3 crore MSMEs are registered with the Goods and Services Tax (GST) regime and the number of income tax filers is even lower. As a result of limited availability and access to data, as well as legacy underwriting methods, the credit requirement of Indian MSMEs' have largely gone unmet.

Access to Technology: Majority of MSMEs use outdated technology that prevents them from keeping up with the modern world. Adoption of new technology and training employees is difficult and expensive, especially in manufacturing where both physical equipment and software are involved. Lack of access to IT education contributes to the technological gap. Another significant factor is lack of awareness, which reduces willingness to invest in advanced technology solutions.

Skill Development: Skilled employees are critical for business growth. Multinational corporations (MNCs) recognise this and place on-the-job training at the heart of their operations. Unfortunately, small-scale businesses fail to upskill their workforce, causing them to suffer unknowingly.

Creativity: Businesses are becoming more knowledge-based, and their success and survival are inextricably linked to their creativity, and innovation. To remain competitive, MSMEs must learn and incorporate the process of innovation into their daily operations. However, they lack the resources and capacity to undertake innovations.

Competition: With increased competition, Indian MSMEs are finding it difficult to sell their products in both domestic and international markets. Small-scale enterprises face stiff competition from global counterparts as well as domestic giants due to their massive scale of operation (large corporations). While the government does provide protection for such small-scale businesses, competition remains largely one-sided.

Red-Tapism: MSMEs require various approvals and entrepreneurs are forced to navigate various government departments in order to obtain construction permits, enforce contracts, pay taxes, start a business, and trade across borders. In addition, regulatory risks and policy uncertainty, limit scaling-up of MSMEs.

Steps to support MSMEs:

Prime Minister's Employment Generation Programme: The scheme, implemented by the KVIC, aims to generate employment opportunities in rural and urban areas by setting up new self-employment ventures/projects/ micro enterprises. The programme also aims to provide continuous sustainable employment to prospective artisans and unemployed youth and increase the wage-earning capacity of artisans and contribute to the growth of rural and urban employment.

Credit Linked Capital Subsidy Scheme: Its objective is to facilitate technology upgrade among MSEs (Micro and Small) by providing capital subsidy of 15% (on institutional finance of up-to Rs 1 crore availed by them) for induction of well-established and improved technology in the specified 51 sub-sectors/products.

Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): It provides collateral-free credit to the micro and small enterprise sector.

Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS): This scheme will help enterprises in

the services sector meet various technology requirements. It also has a provision to grant 25% capital subsidy for procurement of plant & machinery and service equipments through institutional credit to MSMEs owned by SC/ST entrepreneurs without any sector specific restrictions on technology upgradation.

Mudra Loan Scheme: It was launched in April, 2015 for providing loans up to INR 10 lakh to the non-corporate, non-farm small/ micro enterprises. It encompasses 3 financing loans: Tarun (loans up to INR 10 Lakhs), Kishore (loan up to INR 5 Lakhs), Shishu (loan up to INR 50,000).

Digitalisation: Digital Banking provides banking facilities online, like cash deposit, withdrawal, fund transfer, updating of passbook etc., that historically were only available to customers when physically present in a bank branch.

Services:

Building Awareness on Intellectual Property Rights (IPR) for MSMEs: It has been launched to promote awareness about IPRs among MSMEs by assisting them in technology upgrade and enhancing competitiveness and effective utilisation of IPR tools.

Trade, Import and Export for MSMEs: M.S.M.E. support and development organisation, National Small Industries Corporation (NSIC), will assist MSMEs working with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) across multiple areas. APEDA members will get access to NSIC schemes, which would help them address issues pertaining to technology adoption, skills, product quality and market access.

Support by Union Bank of India:

The Union Bank of India has inked with digital app lending with financial assistance up to INR 10.00 lakh at subsidised interest rates to micro enterprises. To reinvigorate the Indian M.S.M.E. sector.

Meta India has announced the launch of online resource centre 'Grow Your Business Hub', to help MSMEs find relevant information, tools and solutions curated to cater to their business goals.

Union Bank of india support MSMEs through various products like Union M.S.M.E. Suvidha Scheme, Union Liqui Property Scheme, Union Rent Scheme, Union Parivahan Scheme, Union Progress Scheme, Union Professional Scheme, Union Turnover Plus Scheme, Union Ayushman Plus Scheme, Union MUDRA Scheme, Union Nari Shakti Scheme, Union Start –Up Scheme, Stand up India Scheme, Union General Credit Card Scheme, PM SVANidhi Scheme, Union GST Gain Scheme, Union Sanjeevani Scheme, Union Arogyam Loan Scheme, Union Alankaar Scheme, Union Loan Guarantee Scheme for Covid affected sectors (ULGSCAS), Union Residential Real Estate Inventory Support Scheme, Union e-Way Bills Solution Scheme, Union Export, Union Equipment Finance, Financing Traders against Electronic Negotiable Warehouse Receipt (eNWR Finance), Union Contractor Scheme, Union Solar Scheme

The M.S.M.E. sector has been fast in going digital. Digitising the sector could help in enhancing efficiency and reliability, cutting costs, and keeping up with latest technological trends.

Digital Initiatives in M.S.M.E. by Union Bank of India:

Putting the country on par with developed nations. While lower costs will encourage more MSMEs to use logistics services powered by technology.

With the advent of online e-commerce platforms, MSMEs have got access to a channel to expand their markets. However, to meet the growing demand for e-commerce in suburban and rural areas, they will require assistance. Our Bank as a technologically advanced last-mile delivery partner capable of facilitating transactions at competitive rates.

Conclusion:

MSMEs can play a vital role in growth of the economy as India enters the Amrit Kaal phase. They can help in inclusive and balanced development and make India a global manufacturing hub. Our Bank has been supporting the MSMEs through various initiatives, The need is to focus on the implementation and realizing the outcomes.

Ramesh Kumar
R.O., Raipur

M.S.M.E. : A Major Driver of Growth

The Micro, Small and Medium Enterprises (M.S.M.E.) sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last five decades. It contributes significantly in the economic and social development of the country by fostering entrepreneurship and generating large employment opportunities at comparatively lower capital cost, next only to agriculture. MSMEs are complementary to large industries as ancillary units and this sector contributes significantly in the inclusive industrial development of the country.

MSMEs are the backbone of most economies worldwide, playing a pivotal role in driving economic growth, generating employment, and fostering innovation. These enterprises encompass a diverse range of businesses, from small-scale manufacturing units and service providers to innovative startups. MSMEs often serve as incubators for new ideas and technologies, contributing significantly to a nation's GDP. Their adaptability and resilience are especially crucial during economic downturns, as they can pivot quickly to address changing market demands. Governments and financial institutions have recognized the importance of supporting MSMEs through tailored policies, access to credit, and capacity-building programs, fostering an environment conducive to entrepreneurship and sustainable development. In a rapidly evolving global landscape, MSMEs continue to prove their significance as engines of economic vitality and innovation. MSMEs are complementary to large industries as ancillary units and this sector contributes significantly in the inclusive industrial development of the country.

Why M.S.M.E. is truly a driver of economic growth and prosperity ?

1. Job Creation and Inclusive Growth:

One of the most critical aspects of MSMEs is their capacity to generate employment. In both developed and developing nations, these enterprises are labor-intensive, providing jobs for a substantial portion of the population. They offer opportunities for skilled and unskilled labor, benefiting not only urban areas but also rural regions.

As per the National Sample Survey (NSS) 73rd round conducted, M.S.M.E. sector has been creating 11.10 crore jobs (360.41 lakh in Manufacturing, 0.07 lakh in Non-captive Electricity Generation and Transmission, 387.18 lakh in Trade and 362.82 lakh in Other Services) in the rural and the urban areas across the country.

Distribution of employment in the MSME sector category wise

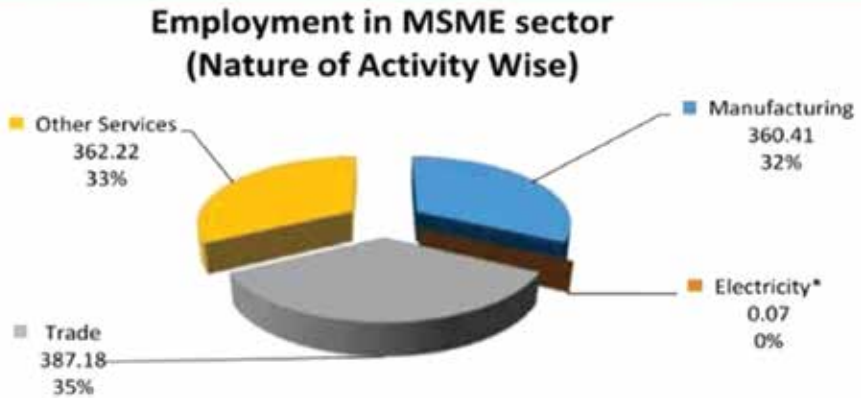

Source: Annual Report M.S.M.E. 2022-23.

The MSMEs are producing a wide range of products and services to meet demands of domestic as well as global markets. On an average this sector has almost 634 lakh units. M.S.M.E. SAMPARK portal is a digital platform wherein jobseekers (passed out trainees/ students of Tool Rooms & Technical Institutions) and recruiters get connected.

2. M.S.M.E. enables the downtrodden and brings parity between Urban and Rural sector:

India being a rural based economy, many of the landless rural masses depend on M.S.M.E. activities. Especially the Micro sector with 630.52 lakh estimated enterprises accounts for more than 99% of total estimated number of MSMEs. Small

sector with 3.31 lakh and Medium sector with 0.05 lakh estimated MSMEs accounted for 0.52% and 0.01% of total estimated MSMEs, respectively. Out of 633.88 estimated number of MSMEs, 324.88 lakh MSMEs (51.25%) are in rural area and 309 lakh MSMEs (48.75%) are in the urban areas. M.S.M.E. sector is thus playing a great role in brining parity between the urban and the rural population.

Percentage share of Rural and Urban MSMEs

Source : Annual report of M.S.M.E. 2022-23

3. M.S.M.E. acts as a Catalyst of growth:

MSMEs are more than just business; they are growth catalysts that empower the economic engines of our nation. MSMEs are often dispersed throughout a country, including rural and less-developed areas. Their presence can help reduce regional economic disparities by bringing economic opportunities to areas that might otherwise be neglected. Their influence on economic development and sustainability is undeniable. These small and medium-sized enterprises are instrumental in driving economic growth, creating employment opportunities, and fostering innovation.

4. M.S.M.E. acts as a Cradle of Innovation:

Innovation is the lifeblood of modern economies. MSMEs, by their very nature, are drivers of innovation. Their nimbleness allows them to adapt swiftly to evolving market conditions, experiment with new technologies, and create inventive solutions to real-world problems. These businesses often challenge the status quo and introduce disruptive innovations that reshape industries and market dynamics. Some MSMEs are at the forefront of innovation, particularly in industries like technology, biotechnology, and renewable energy

5. M.S.M.E. Nurtures Entrepreneurship:

M.S.M.E. is the soul of Entrepreneurship. They offer a fertile ground for aspiring business owners to turn their dreams into reality. Startups and small businesses frequently serve as the breeding ground for fresh ideas and innovations. These enterprises are agile, enabling entrepreneurs to test new concepts, adapt to market changes, and push the boundaries of traditional industries. The spirit of entrepreneurship promoted by MSMEs not only fuels individual dreams but also collectively pushes economies.

6. M.S.M.E. gives opportunities for inclusive growth :

M.S.M.E. are the true champions and enablers of inclusive growth. They empower marginalized groups, such as women, minorities, and the economically disadvantaged, by offering them economic opportunities and access to entrepreneurship. This inclusive approach is essential for creating a more equitable society, bridging income gaps, and addressing social disparities. Moreover, it broadens the consumer base, thereby increasing demand for products and services.

7. M.S.M.E. makes economy more Resilient:

In the times of economic uncertainty, MSMEs display remarkable resilience. Their adaptability allows them to pivot swiftly and explore new avenues, ensuring business continuity even during challenging periods. This resilience is critical for the overall economic stability of a nation. Many MSMEs adopt sustainable and environmentally friendly practices, which can reduce vulnerability to environmental risks and regulations, contributing to long-term resilience.MSMEs can cater to niche markets and respond to changing consumer preferences more rapidly than larger corporations. This market flexibility allows them to tap into emerging opportunities and adjust to economic changes. The way

MSMEs responded during the Covid pandemic is the best example of the resilience of the M.S.M.E. sector.

8. M.S.M.E. : A booster to export :

MSMEs play a crucial role in boosting exports for many countries. Their agility, innovation, and ability to cater to niche markets make them valuable export boosters. MSMEs often produce niche or specialized products that are in demand globally. Their ability to cater to specific customer requirements can be a competitive advantage in the export market Governments and other stakeholders are providing the necessary support and resources to further help MSMEs thrive in the global market. They are truly instrumental in boosting a country's export capacity. They can tap into international markets and contribute to foreign exchange earnings as well.

9. M.S.M.E. makes the country Self Reliant:

MSMEs often provide essential services such as healthcare, education, and financial services in remote areas, thereby contributing to self-reliance by improving access to these service. MSMEs are usually deeply rooted in their communities. They engage in various social and community development activities, which foster self-reliance by empowering local populations. MSMEs engage in various economic activities, such as manufacturing, processing, and service provision. Many MSMEs participate in local supply chains, reducing reliance on global supply networks. They add value to raw materials and inputs locally, reducing the need for imports and hence contribute to a more firm self-reliant nation.

Conclusion : Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) stand as the formidable growth drivers of our economy, embodying the spirit of innovation, inclusivity, and resilience. These unsung heroes not only contribute significantly to the GDP but also create job opportunities, empower marginalized groups, and foster a culture of entrepreneurship. Their agility in adapting to changing market dynamics and their commitment to innovation make them essential in shaping the economic landscape.

Way forward:

The importance of MSMEs cannot be overstated. Governments, financial institutions, and the society at large must recognize their pivotal role and provide support to ensure their continued growth. By doing so, we can harness the boundless potential of MSMEs and pave way for a more prosperous, equitable, and sustainable future for all. The economic growth and well-being of our nation is intricately intertwined with the success of these small and medium-sized enterprises, making them an indispensable cornerstone of our collective prosperity.

Deepak N S
U.L.A., Hyderabad

M.S.M.E. AND STARTUPS

MSMEs are crucial for the growth of the economy from the point of view of generating employment, decrease in dependence on import from other countries & self-reliance of the country. It is very important that if a nation is to grow and develop, MSMEs must grow exponentially. A nation must formulate policies and take care of MSMEs very carefully in a parental manner. In the recent past, we have seen so many budding entrepreneurs with innovative ideas emerging in the form of Start Ups. A very fine policy is framed by the policymakers to ensure robust growth of MSMEs and success of Start Ups.

Significance of Startups:

Innovation: Startups often bring fresh, disruptive ideas to the market, leading to technological advancements.

Job Creation: They offer employment opportunities, especially for young professionals.

Economic Growth: By attracting investments, startups contribute to the country's economic growth.

Challenges Faced by Startups:

Funding: While India has a growing investor ecosystem, securing funds remains a hurdle for many startups.

Regulation: Navigating the complex regulatory environment can be tough for new businesses.

Competition: The Indian market is becoming increasingly saturated with new startups, leading to stiff competition.

Government Initiatives:

M.S.M.E. Ministry: The government established the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises to support and promote MSMEs.

Startup India: Launched in 2016, this initiative aims to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in India. It provides incentives like tax breaks, easier compliance, and patent registration.

MUDRA Bank: The Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA) provides financial support to MSMEs.

Atmanirbhar Bharat Abhiyan: In light of the COVID-19 pandemic, the Indian government announced this initiative to make India self-reliant. It includes several measures to support MSMEs, like collateral-free loans and equity infusion.

Recent Trends and Developments in India:

Initiatives Taken: The Indian government, has launched various initiatives. The "Make in India" campaign, GST (Goods and Services Tax), and initiatives for MSMEs like credit support schemes, innovation drives, and skill development programs are notable examples.

Digital India & MSMEs/Startups: With the push towards digitization through the "Digital India" campaign, MSMEs and startups have been leveraging technology for growth. The emergence of e-commerce platforms, digital payment systems, and online service delivery models has opened new avenues for them.

Some of the popular Government schemes that might be helpful for Startups are Pradhan Mantri Mudra Yojana, Credit Guarantee Trust Fund for Micro & Small Enterprises (CGTSME), Financial Support to MSMEs in ZED Certification Scheme, Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation (CLCSS), Design Clinic for Design Expertise to MSMEs, ASPIRE – A Scheme for the Promotion of Innovation, Rural Industries, and Entrepreneurship, Support for International Patent Protection in Electronics and Information Technology (SIP-EIT), Multiplier Grants Scheme (MGS), Single Point Registration Scheme (SPRS), Extra Mural Research or Core Research Grant (CRG), High-Risk and High-Reward Research, ATAL Innovation Mission (AIM), Startup India Seed Fund (SISF), Venture Capital Assistance (VCA) and New Generation Innovation & Entrepreneurship Development

These are beneficial schemes for startups, students, and budding entrepreneurs. The key objective behind these schemes remain the same: strengthening the bond between the industries and the Indian Government.

In conclusion, while significant strides have been made in recent years to improve the ease of doing business in India, further reforms are needed, especially keeping the M.S.M.E. sector in mind. A more conducive business environment can lead to a robust growth of MSMEs, thereby driving economic growth and job creation in the country.

Rahul Jain
Z.O., Chandigarh

प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र

इडुक्की

इडुक्की केरल का एक खूबसूरत जिला है, जो प्रकृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध स्थलों में से एक है. इडुक्की का आधे से अधिक क्षेत्र जंगल से ढका हुआ है. इस जिले में स्थित आनेमुडि चोटी की ऊंचाई 2,695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है. केरल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध इडुक्की पहाड़ी रिसॉर्ट अपने वन्यजीव अभयारण्यों, खूबसूरत बंगलों, चाय कारखानों, रबड़ के बागानों और जंगलों के लिए जाने जाते हैं. 26 जनवरी 1972 में कोट्टायम जिले से अलग होने के बाद इडुक्की को जिले के रूप में घोषित किया गया था. इडुक्की में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं. हरी-भरी

पहाड़ियों से चारों ओर घिरी इस जगह में आप ट्रेकिंग, कैम्पिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, बोट राइड, जंगल सफारी और हाथी सफारी जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं.

इडुक्की हिल स्टेशन घूमने के लिए नवंबर से अप्रैल तक की अवधि को सबसे अच्छा समय माना जाता है. केरल का प्रमुख पर्यटक स्थल और सबसे बड़ा जिला होने के कारण इडुक्की में सभी बजट के होटल उपलब्ध हैं. अगर साहसिक गतिविधियों के साथ-साथ आप प्राकृतिक सुन्दरता का आनंद उठाना चाहते हैं, तो इडुक्की जरूर जाएं.

अरविंद कुमार
अं. का. विजयवाडा

Role of MSMEs in Indian Economy

The Indian growth experience in the post-reform period has been a subject of great interest to analysts across the board-from academicians to policy-makers. The country witnessed an unprecedented economic crisis in 1991 triggered off by the cumulative impact of fiscal imbalances assuming unsustainable proportions, alarming deterioration in the Balance of Payments' position and severe inflationary pressures. With a view to restore macro-economic stability and catapult the economy onto a high growth trajectory, the Government of India introduced a set of comprehensive and radical structural reforms. The New Economic Policy of 1991 laid the foundation for engineering a paradigm shift in the structural and operational framework of the economy from being one that was controlled and regulated through a centrally administered planning process to one characterized by an increasing degree of market-orientation. Despite accentuation in the incidence of poverty, unemployment, the scale of inequality and the increased vulnerability of the economy to external pressures in the post-reform period, there is general consensus among experts that the fundamentals of the economy are strong and that it has exhibited remarkable flexibility, maturity and dynamism to register sustainable growth in the medium and long term. It would be pertinent here to consider the factors that are likely to propel India's growth story vis-à-vis those that are likely to constrain it.

Traditional economic theory attributes a nation's growth potential to the dual factors of its resource endowments and the efficiency with which they are deployed in the production process. Since fixed capital like plant and machinery have a certain productive capacity, it is reasonable to assume that given a particular level of fixed capital, an expansion of output will result in the lowering of the average cost of production and thereby enhance efficiency of the production process. Further, since the operation of internal and external economies of scale which lead to optimization of resources have been associated with large-scale production, traditionally the role of large manufacturing units has been considered to be central to the endeavor of industrialization. This raises an important question of whether large industries are more efficient production units as compared to the small scale sector. This is where the micro-economic objective of efficiency seems to come into conflict with the macro-economic goal of equity. In a labour-abundant and capital-scarce country like India, the small scale sector comprising of micro small and medium enterprises occupies a crucial position in the economy with respect to parameters like employment-generation, contribution to national income, export earnings and as an important driver of domestic demand. Specifically, the M.S.M.E. sector has the following three-dimensional role to play in the Indian economy:

1. The most viable and sustainable solution to the problem of unemployment in India lies in the steady expansion of a vibrant and broad based M.S.M.E. sector with strong horizontal and vertical linkages in the industrial structure. The widely prevalent incidence of disguised and seasonal unemployment in rural India can be effectively addressed through development of the village and cottage industry segments.

2. The optimum utilization of local resources and entrepreneurial ability can be ensured only through local small business enterprises;

3. A steadily expanding M.S.M.E. sector can serve as an effective automatic stabilizer in the economy and help in subverting the magnitude of external shocks whose probability increases with the increasing degree of globalization.

The contribution made by the M.S.M.E. sector to the Indian economy needs to be assessed in terms of the sector's role in achievement of key macro-economic objectives like economic growth, full-employment and equitable distribution of income and wealth. This may be summarized as follows:

Goal of sustainable economic growth: Economic growth refers to a quantitative increase in the productive capacity of the economy

which in turn forms the basis for achieving a qualitative rise in the living standards of the residents of the nation (commonly referred to as economic development). Variables like Gross Domestic Product (GDP) are generally understood to be indicators of the nation's economic strength in that it is common to associate rapid economic growth with high GDP growth rates. Also, the sectoral composition of the economy in terms of the relative contribution of primary, secondary and tertiary activities to national income is considered to be indicative of the extent of economic transformation from being an under-developed nation to becoming a developed one. By contributing 29% of India's GDP and 45% of manufacturing output in FY 2022-23, the M.S.M.E. sector is making a significant contribution to the nation's economic progress and transformation.

Goal of full-employment: Keeping unemployment rates as close to the natural rate of unemployment (referred to as the minimum rate of unemployment resulting from real or voluntary economic forces like labour turnover, technological displacement and unemployability) has historically been a major challenge confronting policy-makers in India. MSMEs have been considered an effective instrument to address this concern. The following words of Shri P. C. Mahalanobis, architect of the historical Second five-year Plan (1956-61), can be seen as an acknowledgement of the employment potential of the small scale sector by policy-makers since early days of economic planning. "In view of the meagerness of capital resources there is no possibility, in the short run for creating much employment through the factory industries. On the other hand, in the village or cottage industries with any given investment employment possibilities would be ten or fifteen or even twenty times greater

The Third All India Census of Small-Scale Industries (SSI) held in 2001-02 highlights that the employment potential of the M.S.M.E. sector is significantly greater than that of the large industries. The census report shows that the average employment generated by the M.S.M.E. sector per Rs 1 lakh investment was 1.39, as against only 0.20 in respect of the large manufacturing sector indicating that the large scale industrial sector requires an investment of Rs.5 lakh to generate employment to one person whereas the M.S.M.E. sector generates employment for 7 persons with the same investment. A comprehensive study by the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in 1999 found that by investing a meagre 7-15% of the total manufacturing sector's capital the M.S.M.E. sector contributes to 35 to 40 per cent of total employment in the industrial sector. The contribution of the sector to employment generation is also evident from empirical data. The SSI sector employed 1.91 crore persons in 1994-95 and this number has steadily risen to 2.82 crore in 2004-05 and stood at 11 crore in 2022-23.

Goal of equitable distribution of income and wealth: According to data compiled by the Ministry of M.S.M.E., Government of India there were an approximate 1.2 crore registered M.S.M.E. units in November 2022 comprising mainly of micro and small industries. However the total number of units (including the unregistered ones) is estimated to be around 6.33 crores. These units are geographically distributed across the length and breath of the country and are engaged in a diversified range of activities in the manufacturing and services sectors. Due to the decentralised nature of ownership of M.S.M.E. units, expansion of this sector has a positive bearing on the equitable distribution of income and wealth and contributes to furthering the macro-economic objective of reduction in income inequality. Specific initiatives in the M.S.M.E. sector like the Pradhan mantri Mudra Yojana (PMMY), start-up India and stand-up INDIA have the potential to reduce disparities across social groups. For instance, the stand-up India campaign launched in January 2016 which provides incentives to persons from designated socially and economically backward communities and women entrepreneurs engaged in green-field projects has the potential to reduce inter-group disparities. Similarly, the PMMY launched in April 2015with the objective of making collateral-free loans available for setting up micro enterprises, has emerged as a viable alternative source of livelihood. The start-up India campaign, also launched in January 2016, aims at encouraging innovations and dynamic entrepreneurship through provisions like tax holidays and other incentives that create a conducive environment for start-

ups. These initiatives in the M.S.M.E. sector are significant in reducing the disparities across socio-economic groups.

Goal of balance in the external sector: This goal has assumed a lot of importance in the post-reform period wherein progressive integration of the Indian economy with the global economy became an instrument of policy. Developing countries like India struggle to maintain equilibrium in their balance of payments (BoP) account due to the relatively low elasticity of demand for their imports and exports. The scarcity of foreign exchange reserves is also a formidable challenge. Further, globalization increases the vulnerability of the economy to external shocks like recessionary trends in the economies of important trading partners. The M.S.M.E. sector contributes around 50% of India's export earnings and can therefore be termed as the single largest contributor to the nation's performance on the external front. The composition of the items exported by the sector is also noteworthy since a bulk of the exports of these units consists of non-traditional items like ready-made garments, sports-goods, finished leather products, woolen garments, processed foods, chemicals and allied products, and engineering goods.

Goal of optimum utilization of resources: The efficiency of small manufacturing units vis-à-vis large ones has been a subject of debate for long. A detailed study conducted by Sandasara (1969) seemed to suggest that the modern M.S.M.E. sector is relatively capital-intensive and does not really generate more employment per unit of capital when compared to the large scale sector and in fact exhibits lower factor productivity. To that extent the study concludes that M.S.M.E. units are relatively inefficient. However, other studies have drawn contradictory conclusions based on their assessment of the performance of the M.S.M.E. sector which show that the sector is actually more efficient. Studies suggest that at the all-India level, the small-scale sector was more efficient than the large-scale sector. With regard to investment-output ratio, the Third All India Census of Small-Scale Industries held in 2001-02 notes that the SSI sector fared almost on par with the large industries. This is evident from the assessment that an investment of about Rs. 43,000 was required in the organized sector to generate an output worth Rs.1 lakh, whereas in the small scale industries (SSI) sector, a marginally higher investment of Rs.48,000 was required to generate the same quantum of output. It is possible to infer from these studies that MSMEs are notably efficient in the utilization of resources and contribute significantly to the macro-economic objective of optimization.

Goal of price stability: M.S.M.E. units may not directly contribute to this goal but they definitely help in creating a competitive environment in the economy which has positive implications for ensuring competitive prices for closely substitutable products and services offered by them. Also, through their strong backward and forward linkages in the industrial structure they serve as a stable source of inputs for large industries. This helps in maintaining continuity in the production process and to that extent prevents price rise arising out of supply-side bottlenecks.

It is evident that the M.S.M.E. sector occupies a central position in the structural and functional framework of the Indian economy and is making a significant contribution to achievement of the country's key socio-economic goals. It would therefore be appropriate to describe the sector as the backbone of the Indian economy.

Economic growth is not merely about numbers, it is an aspiration. For a country whose history has witnessed its structural retrogression from being an industrially advanced economy in the medieval period to being relegated to the ranks of a poor agrarian economy during the colonial era, restoring its glory is certainly an aspiration. Given the central role the M.S.M.E. sector plays and can potentially play in the translation of India's growth prospects into achievement, the sector deserves special attention of policy-makers, financial institutions and society at large. The day India is recognized as a land of entrepreneurs, we as a nation would indeed be very close to our endeavor of making a mark on the international scene as a force-to-reckon-with, a force the world cannot afford to ignore.

Dr Kalyanlakshmi Chitta
R.O., Greater Pune

Continued Digital Adoption Under M.S.M.E.

India, the world's fifth largest economy, is aiming for the third slot in the coming years. Economic growth is meaningful when it touches both big and small, reaching across all socio-economic strata and boosting our smaller entities, namely the micro, small, and medium enterprises. The policies of the Government of India are in the right direction to transition India's chiefly agrarian economy to an industrial one that is based on the manufacturing of goods and dissemination of services. Yet, growth in manufacturing seems to have hit multiple speedbumps along the way, especially in terms of its potential to generate employment in the country.

The COVID-19 pandemic facilitated a significant shift from the traditional approach to the digital medium among the M.S.M.E. ecosystem. A report by CRISIL states that 47% of micro enterprises and 53% of SMEs have adopted digital sales platforms as against the Pre-COVID figure of 29%. Among the 566 MSEs surveyed, the Gems & Jewellery sector led in tech adoption followed by the Textile Sector and another survey by the Endurance International Group reveals that 50% of MSMEs incorporated technologies like WhatsApp, MS teams, Zoom app and Video Conferencing tools for daily business operations. Experts project that the M.S.M.E. space will be instrumental in creating close to 90mn jobs by 2030. Digital adoption will prove to be a milestone in M.S.M.E. sectors.

MSMEs face several challenges when it comes to scaling their businesses. These include limited resources, lack of access to certain technologies, and a need to stay competitive in an ever-evolving digital landscape. Fortunately, digital adoption can help MSMEs overcome these obstacles and scale their business.

Digital Adoption In recent years, widespread digital transformation has completely revolutionised how businesses operate. From small businesses to large multinationals, digital adoption has enabled companies to move beyond traditional business models and leverage technology to scale their businesses. This includes using cloud computing, artificial intelligence, machine learning and blockchain technology. Digital adoption can help MSMEs quickly and cost-effectively scale their operations.

Indian MSMEs are rapidly migrating from offline to online and adopting technology to improve their operations and increase efficiency while providing timely customer service. This trend is expected to further take shape in 2023, which will help MSMEs reach an even wider customer base, streamline their processes, and reduce costs.

Digital adoption also enables MSMEs to stay competitive in the digital age. By utilising innovative solutions and embracing digital transformation, MSMEs can increase visibility, facilitate better communication with customers, speed up transactions, etc. For instance, businesses can use social media platforms to reach new customers and create a stronger online presence.

Digital Adoptions that can help paradigm shift in the MSMEs Industries in their scale of business are as follows.

1. E-invoicing to Reduce Mistakes in Data Reconciliation : The e-Invoicing or electronic invoicing system, was introduced in 2020 under the Goods and Services Tax (GST) law. It is an innovative digital solution that helps to streamline the process of sending and receiving invoices. E-invoicing helps businesses to manage their invoices with an easily accessible and secure digital platform. This allows businesses to reduce the amount of paperwork associated with invoicing, saving time and money.

MSMEs that haven't already done it can implement e-invoicing to reduce mismatch mistakes in data reconciliation between sellers and purchasers under the GST Input Tax Credit system. This can be especially beneficial as invoices can be easily reviewed and validated before sending them out. In addition, e-invoicing can eliminate fake GST invoices and help improve communication between

businesses and their customers, as invoices can be sent directly to them via email or text.

It can also help MSMEs improve their visibility and transparency in the digital space. By providing easy access to invoices, small businesses can ensure that customers can keep track of their transactions. From 1st October 2022, the Government of India made e-invoicing mandatory for businesses with a total annual turnover of more than Rs.10 crores in any previous financial year from 2017-18 to 2021-22.

2. Selling Through Digital Platforms : Integrating digital tools into operations can help MSMEs access additional resources and expand their reach. For example, businesses can use e-commerce platforms like M.S.M.E. Global Mart to reach customers beyond their local area and sell products online. Selling through platforms or e-commerce portals play an important role in MSMEs' growth. Small businesses can display or sell their products anywhere in the world using e-commerce. These platforms drive MSMEs' growth and development at low costs with low investments, and high levels of innovation. According to the MSMEs Go Digital report from ICRIER, a very small percentage of MSMEs have their own website since that requires a larger investment, both in terms of time and cost; thus, most MSMEs are dependent on e-commerce platforms for their online sales.

MSMEs can also register on M.S.M.E. Global Mart, a Business to Business (B2B) platform that facilitate MSMEs with the ability to connect and market themselves. Small businesses can use it to increase their internet presence, connect with customers and suppliers, find trade leads, and receive infinite tender alerts based on keywords.

3. Adopting Digital Payment Methods : India has been adopting digital payments at a rapid pace over the last few years, and the ecosystem will continue to grow in the coming years too. The digital payment ecosystem can unlock massive value for M.S.M.E. in 2023 by helping them reduce inconvenience to their customers and suppliers, reduce the administrative burden on their business, and minimise the risk of losing essential records. This may include using mobile payments, such as Google Pay or Phone Pay, or digital wallets, such as PayPal or Paytm. Businesses should also invest in digital payment infrastructure that is secure and reliable, as well as a customer service system that can support digital payments.

Digital Payment provides consumers with contactless and cashless payment methods, which helps MSMEs with easy record-keeping, convenience, and relatively inexpensive adoption. The volume of digital payments of M.S.M.E. has been increasing yearly, with 7422 crore transactions in FY 2022, up by 33% from FY 2021, according to the Ministry of Electronics and IT (MeitY). The comfort with digital payments has been rising up, with UPI being the most popular mode, particularly among M.S.M.E. customers.

4. Increased Visibility: Digital adoption can help MSMEs increase their visibility, as digital tools enable businesses to reach more customers and markets than ever before. From social media platforms to search engine optimisation, digital adoption can help MSMEs expand their reach and attract new customers.

5. Streamlined Processes: Digital adoption can help MSMEs streamline existing processes and make operations more efficient. From cloud computing to automated tools, digital adoption can help MSMEs reduce costs and make their businesses more efficient.

6. Staying ahead: Digital adoption can help MSMEs gain a competitive edge by staying ahead of the curve. By leveraging the latest trends and technologies, businesses can remain competitive and be better positioned to capitalise on opportunities.

7. Greater Access to Resources: Digital adoption can also help MSMEs access resources that would otherwise be unavailable. From data analytics to cloud computing, digital adoption can help businesses gain access to the tools and technologies they need to scale their operations.

8. Cost Savings: Last but not the least, digital adoption can help MSMEs save money. Businesses can reduce costs and increase their bottom line by leveraging digital solutions.

Conclusion : Finally, businesses should also consider educating their customers about the benefits of digital payments. By explaining the convenience, security, and speed of digital payment systems, they can encourage their customers to adopt to these systems. Additionally, businesses should also ensure that their customers have access to the necessary tools and resources to make digital payments. This will help ensure the successful adoption of digital payments in the long term.

Neeraj Kumar Kashyap
Z.L.C.,
Visakhapatnam

M.S.M.E. : Latest Trends and Road Ahead

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the Indian economy. They contribute to around 30% of the country's GDP and employ over 11 crore people. MSMEs are also major contributors to exports and innovation.

At the heart of India's bustling economy, micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have established an indomitable presence. These dynamic businesses contribute about 30% of India's GDP and provide livelihoods to more than 40 crore people. Notably, MSMEs are the unsung heroes of exports and innovation, contributing significantly to India's economic landscape.

Latest Trends in M.S.M.E. Sector:

The M.S.M.E. sector is in a constant state of flux, influenced by countless trends reverberating across its region. These trends demonstrate the adaptability and resilience that have become the hallmark of the industry.

Digital Renaissance:

As the digital revolution touches every sector, MSMEs are leveraging digital technology to redefine their operations. By adopting digital tools and platforms, these businesses are improving efficiency, productivity, and market reach. The digital wave is enabling MSMEs to explore new markets, connect with untapped customer segments, and streamline their internal processes. This digital transformation not only strengthens their competitive advantage but also helps them grow sustainably.

E-commerce:

India's e-commerce sector is experiencing unprecedented growth, bringing new opportunities to MSMEs. These companies leverage e-commerce platforms to market their products and services, beyond geographical boundaries. E-commerce provides a way for MSMEs to reach unexplored markets, interact directly with customers, and diversify their revenue sources. This trend creates a level playing field, allowing small and medium-sized businesses to compete on the global stage.

Export Escalation:

With growing global demand for Indian goods and services, MSMEs are shifting their focus towards exports. Whether through exporting directly or partnering with exporters, these companies are expanding their horizons. Increased focus on exports not only diversifies India's customer base but also positions them as vital cogs in the global supply chain, thereby amplifying India's economic resonance on the international arena.

Women Entrepreneurship:

One of the most encouraging trends in the M.S.M.E. sector is the growing number of women entrepreneurs in India. Women are advancing rapidly in a variety of fields, bringing new perspectives, innovative ideas, and unique aspects of leadership. Their growing presence underlines the industry's inclusivity and highlights its central role in promoting gender equality.

Increased Durability:

In an era characterized by growing environmental consciousness, the demand for sustainable products and services is booming in India. MSMEs are actively capturing this trend, developing many types of sustainable services. These products and services not only align with evolving consumer preferences but also meet global sustainability requirements. MSMEs appear to be pioneers in environmentally friendly solutions, positioning themselves as responsible and pioneering companies.

AI and ML Trends:

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) technologies are penetrating the M.S.M.E. landscape, optimizing operations in myriad ways. MSMEs are automating tasks, improving customer service, and developing innovative products and services using these technologies. By leveraging AI and ML, these companies improve operational efficiency, reduce costs, and stay competitive in a rapidly changing business environment.

Growth of the Gig Economy:

The gig economy opens new perspectives for MSMEs. These companies can now tap into a large pool of freelancers and qualified professionals for a specific project. The gig economy provides flexible and cost-effective solutions for tasks that require specialized expertise, allowing MSMEs to access high-level talent without the cost of hiring full-time staff.

Social Media Origins:

Social media platforms have become indispensable tools for MSMEs to connect with their target audience. They provide businesses with a direct way to build customer relationships, generate leads, and drive sales. MSMEs who know how to leverage social media can improve their brand visibility, engage with customers on a personal level, and gain a competitive advantage.

The Way Forward for MSMEs in India:

The future of Indian MSMEs is bright, supported by a series of government initiatives and interventions. Realizing this potential requires strategic acumen and collaborative efforts in several key areas.

Innovation:

Innovation is the lifeblood of successful MSMEs. These companies must foster an environment conducive to innovation, fostering creativity in product development, process improvement, and marketing strategy. Innovation not only sets them apart but also allows them to adapt to changing market dynamics.

Digital Capabilities:

In the era of digitalization, MSMEs must continue to adopt digital technology. Whether it is adopting e-commerce platforms, digital marketing strategies, or automating processes, digital fluency is essential to accessing new, future markets. Collaborate with a broader customer base and streamline operations.

Export-Focused Approach:

MSMEs can explore exporting directly or partnering with export companies to tackle the complexities of international trade. Export-oriented efforts not only diversify revenue sources but also enhance the stature of MSMEs in the global arena.

Skills Training:

A highly skilled workforce is the foundation of any successful business. MSMEs need to invest in skills development programs, ensuring that their employees have the necessary skills. This investment in human capital is key to stimulating growth and development.

Market Access:

Transparent market access is a must for MSMEs to thrive. The government is actively working to create opportunities for MSMEs to enter the market, including through e-commerce platforms and export promotion programs. MSMEs should proactively leverage these initiatives to expand their market reach.

Challenges and Opportunities for MSMEs:

Although the future of MSMEs in India looks bright, these businesses face many challenges. Recognizing and overcoming these obstacles is essential to realizing their full potential:

Financial Access:

Access to finance remains a major obstacle for MSMEs. These businesses often have difficulty obtaining loans from banks and financial institutions, limiting their growth trajectory. Addressing this issue is essential for the sustainable expansion of the industry.

Lack of Skilled Workforce:

There is a shortage of skilled workers in the M.S.M.E. sector, which hinders growth and development.

Competition from Large Corporations: MSMEs often compete with large companies, which possess more resources and economies of scale.

Regulatory Compliance: Complying with various regulations can be complex for MSMEs due to limited resources and expertise.

Infrastructure Constraints:

Poor infrastructure, including inadequate roads and inconsistent power supply, can hinder the efficient operation of MSMEs.

The Indian government is actively addressing these challenges by providing financial assistance, simplifying regulations, and investing in skill development programs.

Conclusion:

MSMEs are a vital cog in the Indian economic engine. They contribute significantly to GDP, employment, and exports. With the support of the Government and by embracing innovation and technology, MSMEs can overcome their challenges and thrive. By doing so, they will not only benefit their businesses but also contribute to the overall growth of the Indian economy.

Ramaswamy Kumar
U.L.A., Mangaluru

M.S.M.E.: Way Towards Industrialization of Rural and Backward Areas

The success of a self resilient economy is conditioned on the growth of M.S.M.E. sector. Micro, small and medium enterprises sector, is one of the major contributor to India's Gross Value Addition after the services sector. M.S.M.E. contribute to 45% of India's exports while creating 14.20 crore jobs in the country. The data from Confederation of Indian Industry, shows that, the share of Micro, Small & Medium industries is 99.47%, 0.52%, 0.01% of total MSMEs respectively.

Rural India, in the last century witnessed rapid changes such as climate change, reduced dependance on agriculture, migration of rural youth to urban and metro centres for employment, conversion of agricultural lands to non agriculture for the purpose of real estate etc. However, on the bright side we also see farm mechanization, improved irrigation facilities, development of cottage industries, higher productivity, improved living standards etc.,.

Migration of rural poor, and youth to urban and metro areas is a serious concern and needs to be addressed by the policy makers. It not only affects agriculture, but also, several sectors which directly or indirectly depend on rural population, viz. cottage industries, small trading units, and tertiary industries.

Employment generation at rural and semi urban areas is found to be an effective alternative to address migration of rural population issue.

Government of India has launched several schemes in this direction, which ultimately leads to Employment generation in Rural areas, finally aiming at improving productivity while simultaneously addressing poverty alleviation.

Some of the measures of the Govt of India which contributed to the industrialization of rural and backward areas are,

1. Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP) & expanding its scope
2. Expanding the scope of CGTMSE
3. Expanding the scope of CGFMU
4. Cluster Development Schemes

Setting up of SIDBI & expanding its scope: Small industries Development Bank of India, was set up in the year 1990, now being regulated by Reserve Bank of India, acting as a apex regulatory body for overall licensing and regulation of MSMEs in India. It operates 'Institutional Finance Program', a refinance program to increase money supply to MSE sector besides financing directly to MSMEs. It is very active in the development of Micro finance institutes(MFIs), through SIDBI foundation. Its promotion and development program focuses on rural enterprises promotion and entrepreneurship development.

As a part of non financial intervention, SIDBI in association with CRISIL introduced India's first sentiment index for MSEs- namely 'CriSidEx'. SIDBI in association with Trans Union CIBIL, launched 'M.S.M.E. Pulse', and in association with Equifax launched 'Microfinance pulse'. Both are quarterly reports on M.S.M.E. credit activity.

Setting up of Udyami Registration portal: With an aim to boost the upcoming MSMEs, Ministry of M.S.M.E., Govt of India started Udhyam portal (Udhyam Assist Portal) on 01.07.2020. Identity makes the difference while getting access to finance from formal systems. Udhyam portal is an easiest way to create identity as it requires only applicant's Aadhaar and PAN during the process of registration. It's a one time registration and no renewal of registration is required. All new as well as existing enterprises can register themselves under Udhyam Registration number. Along with Individuals, Sole proprietors, HUFs, Companies can also be registered under this portal at free of cost. After successful registration MSMEs will be given with a e-certificate 'Udhyam Registration Certificate'. This portal is fully integrated with Income Tax & GSTIN systems. No enterprise shall file more than one Udyam Registration. However, any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration.

Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP) & expanding its scope: PMEGP is a earmarked scheme in the journey towards industrialization of Rural and urban areas aiming at bringing together widely dispersed traditional artisans, rural and urban unemployed youth and give them self employment opportunities to the extent possible at their own place. It commenced in the year 2008, and recently it got approval from the 15th Finance commission cycle to continue up to 2025-26. The scheme is being administered by KVIC at the central level and monitored by KVIB & DIC at the field level. It promotes setting up of new industries under micro category. Govt of India is providing margin money subsidy ranging from 15% to 35% depending on the category of the borrower.

Expanding the scope of CGTMSE: CGTMSE new guidelines w.r.t coverage and risk premium, highly promotes entrepreneurship across the country, as for getting institutional finance collateral security is the barrier which has been addressed through credit guarantees.

Cluster Development Schemes: A cluster is a group of enterprises located within an identifiable and as far as practicable, contiguous area or a value chain that goes beyond a geographical area and producing same/similar products/ complementary products/services, which can be linked together by common physical infrastructure facilities that help address their common challenges.

The main objectives of the CDP are,

i. To support the sustainability and growth of MSEs by addressing common issues such as improvement of technology, skills & quality, market access, etc.

ii. To build capacity of MSEs for common supportive action through formation of self help groups, consortia, upgradation of associations, etc.

iii. To create / upgrade infrastructural facilities in the new / existing Industrial Areas / Clusters of MSEs.

iv. To set up Common Facility Centres (for testing, training, raw material depot, effluent treatment, complementing production processes, etc).

v. Promotion of green & sustainable manufacturing technology for the clusters so as to enable units switch to sustainable and green production processes and products

As of now in our country, 201 common facilitation centers and 309 Infrastructure Development projects approved by the ministry of M.S.M.E. to help the MSMEs to compete with the external market. (Source: https://my.msme.gov.in/mymsme/reg/COM_ClusterForm.aspx)

Conclusion: The schemes discussed herein are an indicative list of initiatives of Government of India which contribute to promotion of industrialization of Rural as well as urban areas while promoting entrepreneurship. M.S.M.E. being an employment intensive sector, contributes to upliftment of poverty, improvement in living standards at micro level and helps to reduce dependence on import, removal of regional disparities, and economic health of the country at the macro level.

N Visweswara Gupta
Z.L.C.,
Visakhapatnam

नई प्रतियोगिता / New Contest

फोटो - **अरूण सुदर्शन एस**
क्षे. का., कडपा

स्लोगन लिखें / Write a Slogan

क्या यह तस्वीर आपके मन में किसी पुरानी याद, किसी गहन भावना या सृजनात्मकता को अंकुरित कर रही है? हर तस्वीर एक दास्तां बयां करती है. तथापि, यदि आप अपने भावों को 2 पंक्तियों में पिरोकर प्रस्तुत करना चाहें तो तुरंत अपनी कलम का जादू दिखाते हुए इस चित्र के लिए उचित स्लोगन लिखें और अपने कार्यालय क्षेत्र के संवाददाता के माध्यम से हमें प्रेषित करें.

अपनी प्रविष्टि भेजते समय निम्नलिखित का अवश्य ध्यान रखें:

स्लोगन केवल 2 पंक्तियों का ही हो.

प्रविष्टि हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती है. परिपत्र सं. 7869 दि: 19.12.2022 के अनुसार दोनों श्रेणियों में अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे.

एक स्टाफ सदस्य एक ही प्रविष्टि हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है.

प्रतियोगिता केवल बैंक के सेवारत कार्मिकों के लिए ही है.

सभी संवाददाता अपने क्षेत्र से प्राप्त प्रविष्टियों को समेकित कर निर्धारित तिथि तक uniondhara@unionbankofindia.bank पर प्रेषित करें.

प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 है.

शब्द संख्या का ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रविष्टियों को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा.

Is this picture evoking some old memory, some deep emotion or sparking creativity? Every picture is worth a thousand words. However, if you want to express yourself feelings in 2 lines, then let your pen create magic. Write a suitable slogan for this picture and send it to us through the correspondent of your office Region.

Please ensure the following while submitting your entry:

Slogan should be of only 2 lines.

The entry may be sent in Hindi or English. In terms of circular no. 7869 dt. 19.12.2022 separate prizes shall be awarded under each category Both the categories have different prizes.

A staff member may submit only one entry, either in Hindi or in English.

This contest is open only for the staff members presently in service of the Bank.

All correspondents are requested to consolidate the entries of their Region by the stipulated date and send them to uniondhara@unionbankofindia.bank.

The last date for sending entries is 12th January, 2024

Entries, duly, adhering to the specified word limit, received by the last date, shall only be included in the competition.

यूनियन धारा प्रतियोगिता क्र 166 - 'शीर्षक लिखें'

पुरस्कार	हिन्दी श्रेणी	अंग्रेजी श्रेणी
प्रथम	**श्री राजेन्द्र तिवारी,** पालम विहार शाखा, क्षे. का., गुरुग्राम	**सुश्री सबरी सुकुमारन नायर,** श्रीकारियम शाखा, क्षे. का., तिरुवनंतपुरम
द्वितीय	**श्री पंकज नेव्हल,** क्षे. का., नागपुर	**श्री गणपति झा,** क्षे. का., बेंगलूरु उत्तर
तृतीय	**श्री प्रमोद कुमार चौधरी,** गुड़गाँव शाखा, क्षे. का., गुरुग्राम	**श्री अश्विनी कुमार,** क्षे. का., एर्णाकुलम
प्रोत्साहन	**श्री विशाल अवस्थी,** क्षे. का., पंजागुट्टा	**सुश्री अंकिता रॉय,** क्षे. का.,काकीनाड़ा

नवभारत, सशक्त भारत

सन् सैंतालीस की वह जगमगाती एवं उत्साहित सुबह
जन-जन के लिए नया पैगाम लेकर आई
एक नए स्वतंत्र एवं अद्भुत भारत का हुआ उदय
पूरे ब्रह्मांड में है खुशहाली छाई
नई आशाओं को मन में रखकर,
उम्मीदों का दामन थामे
नव भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़े
हरित क्रांति की चमत्कार ने,
हर कटोरे में है अन्न भरे
परमाणु बम बनाकर पूरी दुनिया को
अपना दम दिखलाया
अब हमें उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजना आया
प्रज्ञान ने चाँद पर अपने पदचिन्हों को
चहुँओर फैलाया
विक्रम ने भी तिरंगे झंडे को चाँद पर लहराया
हम न रुके थे, और न रुकेंगे
ऐसा हमने आदित्य - एल 1 को
रवि की परिक्रमा के लिए भेज
पूरी दुनिया को बतलाया
उदारीकरण के दौर में बाहें फैलाकर
पूरी दुनिया का हमने स्वागत किया
तकनीकी और मानव संसाधन के दम पर
हमने है दुनिया पर भारत के नाम का डंका बजाया
पूरे विश्व में हमने प्रजातंत्र का झंडा है लहराया
सर्वधर्म समभाव भी हमने दुनिया को है सिखलाया
मजबूत है कदम, हमारे हौसलों में भी जान है
हम सब हैं भारतवासी, भारत हमारी शान है!!

पीयूष कुमार झा
यू.एल.ए., मंगलूरु

मां की राखी, चंदा मामा को

आखिर मिल ही गई राखी, मेरे मामा को आज,
भेजी है जो मां ने प्रेम से,
विक्रम के साथ और कहा था मां ने,
देखो विक्रम! उतरना हल्के पांव,
मामा के आंगन.
और फिर सौंप देना यह रक्षा सूत्र मामा के हाथ.
प्रणाम कर फिर मामा से जोर से कहना
मामा मैं आ गया.
बिलकुल ऐसा ही विक्रम ने किया, मामा ने फिर
लगा कर गले विक्रम से कहा
पूरी दुनिया से मिला हूं मैं, पर विक्रम
अपनी मां से कहना कि
तुझसे मिल कर मजा आ गया.
अपनी मां से कहना मैं ध्यान रखूंगा,
मान रखूंगा, इस भेजी हुई राखी का
सम्मान रखूंगा.
पूरी दुनियां के सामने न झुकने दूंगा,
उनका शीश, वो सदा मुस्कुराए,
प्रगति यूं ही करती जाए
और अबकी बार जल्दी ही सूरज बाबा के यहां
जरूर जाए
यही खासियत है तुम्हारी मां में कि उनके बच्चे
पूरे ब्रह्मांड को समाए हैं
अपने परिवार में विश्व की प्रगति में,
तुम्हारी मां का योगदान अहम होगा
तभी भारत विश्व गुरु होगा
यह मेरा उनको वचन होगा.

प्रवीण मिश्र
कानपुर मुख्य शाखा

चलो मैं गीत गाता हूँ

चलो मैं गीत गाता हूँ
तुम्हें फिर से बुलाने को
सफर में आखिरी पर हूँ
किया वादा निभाने को
मैं देहरी पार बैठा हूँ
पर थक के हार बैठा हूँ
हुई आंखे मेरी बोझल
है सच, बीमार बैठा हूँ
गला सूखा, बदन रूखा
नब्ज़ भी हो रही धीमी
तुम्हें पल देखने भर की
उम्र बस शेष है जीनी
नहीं सोया में अब तक चैन से
जब से गयी हो तुम
मेरा सर गोद में रख लो
मुझे अंतिम सुलाने को
चलो मैं गीत गाता हूँ
तुम्हें फिर से बुलाने को
मुझे इस भीड़ ने घेरा
किसी ने गाँव भी जाना
मेरे हाथों पर तेरे नाम
की लिखनी से पहचाना
बचाने जान को मेरी
बुलाये, वैद्य भी आला
सुना जो नाम साँसो में
मुझे बौरा ही कह डाला
चली आओ तनिक जल्दी
कहीं दम छूट न जाए
नहीं मरना बिना देखे
कसम यह टूट न जाए
जुदा होके बहुत रोया
अभी तक याद है मुझको
गले आके लगा लो तुम
मुझे अंतिम रुलाने को.
चलो मैं गीत गाता हूँ
तुम्हें फिर से बुलाने को
सफर में आखिरी पर हूँ
किया वादा निभाने को

राहुल
क्षे.का., हिसार

Wanderer

Thoughts, wander in the forest of mind and soul

Struggling to find a way forward

Resolutions made and die, like waves ashore

Restless, keep coming, moaning

Reaching but not concluding

Leaving trail after trail like lines of destiny

On the palm of heart but to end in endless loops

Dawn brings light not clarity

Noons deepen pondering but closing

Evenings rekindle hope to forge

Nights shackle, stifle, surrender imminent

But it's a circle turning vicious

Where am I heading if not moving

Falling and embracing abyss till another dawn

Is the slumber becoming hibernation

To what avail, philandering notions spreading contagion

Weaving the web, tightening the noose, choking swell

Aint I a creator or creation playing devil

Explore relations, contemplate reach, figures turn grey

Defeat writ large, fathom dissolving self, cant turn ash

Wonder the end will come to rescue

or destiny has turned nomad

Rajnish Khare
Chief Digitization Officer
C.O., Mumbai

RACE ON

Turn up the heat,
Turn on the light
Stay focused in your game
Never let it out of sight

Keep moving ahead
With that slow and steady pace
You can lose a few miles
Never feel shy to be in the race

As long as you can
As hard as it was meant to be
Keep pushing, keep striving
It's just the start of your journey

For your competition is YOU
Awaken your potential
Let it flow, let it thrive;
Don't settle down, the best is yet to come...

Arit Roy
Z.O., Hyderabad

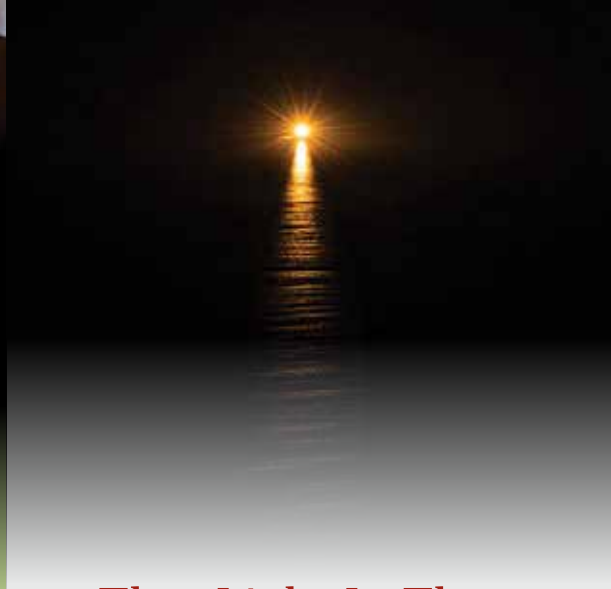

That Light In The Darkness

Taffeta even ! alluring in your light oh! God.
How that incandescent fill my heart.
Almighty, lead me to the etternal light .
Thy I plead for the light.
Light can only in benevolent heart. Iam valient in your prevalent light. Gesture in my heart is divineta light. Hamartia upshot of the darkness inside. To be elucidated with deity light...

Illuminate the esse with benevolence.
Nothing else can succour your world.

Thee I pleed for the light ...
Heavenly Father my whole hearted prayers.
Etternal light lead me ever.

Darkness never gap my heart.
And this is the promiss to heaven
Reprimanded by the world may be.
Kudos of you will light my world. Naos my heart should be ever.
Eagre my heart to the etternal light.
Slowly lead me to the etternal light.
Slowly lead me to the etternal light.

Divyasree K
Thoppumpaddy,
R.O., Ernakulam

यू जीनियस

दिनांक 25.08.2023 को मुंबई में श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में श्री योगेन्द्र सिंह, अंचल प्रमुख और श्री विजय कुमार, क्षेत्र प्रमुख की उपस्थिति में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में 143 स्कूल के 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया.

दिनांक 09.09.2023 को पटना में आयोजित यू-जीनियस क्विज प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए श्री आमीर सुबहानी, मुख्य सचिव, बिहार सरकार साथ में श्री संजीव दयाल, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना, श्री अरुण कुमार, महाप्रबंधक (मा.सं.), कें.का. मुंबई, श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख, रांची, श्री राजेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, पटना.

दिनांक 04.09.2023 को दिल्ली में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में श्री कबीर भट्टाचार्य, अंचल प्रमुख तथा श्री गोविंद मिश्रा, क्षेत्र प्रमुख-नई दिल्ली विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया.

दिनांक 25.08.2023 को वाराणसी में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में सिटी राउंड की विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए अंचल प्रमुख श्री गिरीश जोशी, उप अंचल प्रमुख श्री सत्येंद्र कुमार सिंह एवं अन्य कार्यपालकगण.

दिनांक 02.09.2023 को लखनऊ में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री सुमित श्रीवास्तव, अंचल प्रमुख तथा श्री मार्कन्डेय यादव क्षेत्र प्रमुख, लखनऊ.

दिनांक 09.09.2023, को आयोजित यू जीनियस क्विज प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए श्री राजेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, पटना, श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख, रांची तथा श्री मृत्युंजय तिवारी, अध्यक्ष, प्लेयर एसोसिएशन, बिहार.

दिनांक 13.09.2023 को अंचल कार्यालय, गांधीनगर द्वारा आयोजित "यू जीनियस" के प्रतिभागियों के साथ श्री विट्ठल बनशंकरी, अंचल प्रमुख, श्री के पी सिंह, उप अंचल प्रमुख श्री तुषार कान्त कर, क्षेत्र प्रमुख अहमदाबाद तथा श्री संतोष साहू, क्षेत्र प्रमुख गांधीनगर.

दिनांक 11.09.2023 को रायपुर क्षेत्र में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में क्षेत्र प्रमुख श्री अनुज कुमार द्वारा विजयी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया गया.

दिनांक 01.09.2023 को श्री नवीन जैन, अंचल प्रमुख, पुणे की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती द्वारा संयुकत रूप से आयोजित "यू जीनियस" कार्यक्रम के विजेताओं के साथ श्री मयंक भारद्वाज, उप अंचल प्रमुख; श्री एम वी एन रवि शंकर, क्षेत्र प्रमुख, नागपुर तथा अन्य कार्यपालक.

दिनांक 29.08.2023 को अंचल कार्यालय, पुणे द्वारा श्री मयंक भारद्वाज, उप अंचल प्रमुख के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आयोजित यू-जीनियस के विजेता टीम के साथ कार्यपालकगण.

दिनांक 08.09.2023 को हैदराबाद में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में विजेताओं के साथ श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद तथा अन्य कार्यपालकगण.

दिनांक 02.09.2023 को वरंगल में हैदराबाद अंचल के 5 गैर शहरी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त यू-जीनियस विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद तथा संबंधित क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 29.08.2023 को अंचल कार्यालय, विजयवाड़ा द्वारा यू-जीनियस कार्यक्रम में विजेताओं के साथ श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख तथा मुख्य अतिथि श्रीमती के जी वी सरिता, पुलिस अधीक्षक,सी आई डी, गुंटूर.

दिनांक 06.09.2023 को मंगलूरु में आयोजित यू-जीनियस कार्यक्रम में विजेताओं के साथ श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख; श्री सी डी ज्यांना, उप निदेशक, प्री यूनिवर्सिटी, दक्षिण कन्नडा; श्री चंद्रगुप्त, डीआईजीपी वेस्टर्न रेंज और श्री नरेंद्र नायक, चेयरमैन एक्सपर्ट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन.

Ankita J

Banker by Profession

Powerlifter by Passion

Ms. Ankita J is a banker by profession and a Powerlifter by passion. Powerlifting is a sport that consists of three attempts at maximal weight on three lifts: squat, bench press and deadlift. It focuses on legs, hips, chest, triceps, shoulders, back and hips. Women are rarely interested in these type of sports. – Ms. Ankita J is a Manager working in Thycaud branch of Tiruvananthapuram Region, and is not only passionate about this sport but has brought nationwide accolades to herself and the bank. Ms. Ankita is a gold medallist in National and State level Powerlifting. excerpts of her interaction with our correspondent Ms. Kala. C. S. is reproduced here :-

Congratulations on winning the Best Overall Lifter award in the prestigious Karnataka State Championships. We would like to know you better, could you please tell us about your childhood ?

I was Born and brought up in Mavelikara-Haripad in Alappuzha. My Father was into business, and my mother is a UBI employee, currently posted as BH Haripad branch. Coming from a typical middle-class family, importance was always given to academics and not sports or extracurricular activities.

Tell us about your academics

I studied in Bishop Moore Vidyapith, Mavelikara till the 10th standard. I was in KV NTPC, Kayamkulam up to 12th. I was an All India topper in Biology and English in 12th std CBSE boards. After that I went to study BTech Civil Engg from Govt Engg College, Kottayam.

How did you get attracted to powerlifting?

I started weight training after I gained a bit of weight and gradually, I fell in love with it. I have been regularly working out since 2018. The combination of strength, technique, and discipline in powerlifting fascinated me, inspiring me to explore the sport. I wanted to push my limits and unlock my potential and that's how I got hooked into this sport. I started training for powerlifting from April 2023, navigating a steep learning curve to witness significant progress.

Tell us about your role models in this sport.

Karlina Tongotea, IPF world champion from New Zealand in 76kg weight class and Amanda Ann Lawrence IPF world champion from USA in 84kg weight class are my role models.

Well, physical fitness is very important in this type of sport, can you tell us about your daily routine?

I begin my day at 6 a.m., cook my meals, work a full day, and dedicate evenings to powerlifting training.

I maintain physical fitness by scheduling regular workouts and adhering to a balanced diet, making conscious choices to stay active throughout the day.

People nowadays are struggling in maintaining their work-life balance. How do you maintain the zeal to continue your passion?

Balancing a demanding job with intense training schedules posed challenges, requiring resilience to overcome fatigue and doubt. My love for this sport keeps me going inspite of all the physical and mental stress that our job demands. I never miss my sessions and it's always rewarding.

Effective time management and clear priorities help me balance work commitments with dedicated time for powerlifting. A day without training feels incomplete for me so I make sure that I don't skip my training.

Tell us about the recognition you have received in this field?

I've received recognition and medals at various powerlifting competitions, validating the hard work invested in the sport. I would like to mention some of them,

1. PRO Pune Nationals, gold medals in Push- pull and deadlift only events in the U67.5kg bodyweight category and overall best female lifter in the push -pull category.

2. PRO Karnataka State, gold medals in Push- pull and deadlift only events in the U67.5kg bodyweight category and overall best female lifter in the push -pull category.

3. Trivandrum district powerlifting, gold medal in U63kg bodyweight category.

4. Kerala State powerlifting, gold medal in U63kg bodyweight category.

Tell us about your Plans for the future.

I aim to advance in both my career and powerlifting pursuits, competing at higher levels and taking on more challenging professional roles. My long-term dream is to win an international competition.

Any message to your fellow colleagues in the bank?

I don't think I am at a level that I can give a message but I just want to say "**ALWAYS DREAM BIG**" Do what your heart wants, then only you can excel in your career and passion.

Kala. C. S.
R.O.,
Tiruvananthapuram

First Loss Default Guarantee

First Loss Default Guarantee (FLDG) is an arrangement between two entities, often two regulated entities (REs). Or, in the case of digital lending, between the regulated entity and fintech lending service providers (LSPs), whereby the LSP guarantees to compensate the RE for loss due to default up to a certain threshold of the loan portfolio. Since losses only to a certain threshold are covered under this arrangement, it is called as first loss default guarantee or FLDG. While permitting FLDG, Reserve Bank of India has stipulated that FLDG arrangements conforming to these guidelines shall not be treated as 'synthetic securitization and/or shall also not attract the provisions of 'loan participation.

Genesis of First Loss Default Guarantee is linked to the startup movement

The rise of startups in India didn't happen overnight but over a gradual period. However, the exact year the startup revolution took shape in India, was 2008. Every problem comes with an opportunity. Recession that hit the world in the year 2008 forced businesses around the globe to reallocate their resources and lay off employees in large numbers. In India, it mostly affected the IT professionals, As per Investopedia, a startup as "a young company that is just beginning to develop." It is brought into function either because the founder(s) have come up with a unique solution (a product, software, or service) to erase a complicated problem or because they have found a more efficient way to recreate and distribute something that was already there.

Finance and Technology was the favorite sector for these startups because this sector was having great opportunity and required great ideas. Startups mixed finance with technology and made "Fintech" a new generation model which dealt with the financial problem with the help of technology. This model is a hit as it requires, less capital and manpower and the output to the cost ratio was high.

Guidelines of Reserve Bank of India on First loss default guarantee:

Reserve Bank of India has issued guidelines on First loss default guarantee on 08 June 2023. The guidelines are applicable to FLDG in case of digital lending only and not in any other form of lending.

First Loss Default Guarantee arrangements must be backed by an explicit legally enforceable contract between the Regulated Entity and the Lending service provider. Such contract, among other things, must contain the following details:

- **Extent of DLG cover:** The amount of guarantee must be explicitly mentioned in the contract. The guarantee should be at portfolio level and not the loan to loan guarantee.

- **Form in which FLDG cover is to be maintained with the Regulated Entity:** Regulated Entity shall accept the FLDG only in the form of Cash deposited with the Regulated Entity or Fixed Deposits maintained with a Scheduled Commercial Bank with a lien marked in favour of the Regulated Entity or Bank Guarantee in favour of the Regulated Entity. The cash deposit or Fixed Deposit should be upfront. Guarantee in no other form will be accepted.

- **Timeline for invocation of FLDG:** The Regulated Entity shall invoke FLDG within a maximum overdue period of 120 days, unless made good by the borrower before that.

- **Disclosure requirements:** Loan Service Providers shall publish on their website the total number of portfolios and the respective amount of each portfolio on which FLDG has been offered. Regulated entity has to ensure the compliance of the same.

- **Tenor of FLDG:** The regulated entity should not sanction any loan with a tenure more than the remaining period for which the FLDG agreement will remain in force. It means the FLDG shall not be less than the longest tenor of the loan in the underlying loan portfolio.

Cap on FLDG: Regulated Entity shall ensure that total amount of FLDG cover on any outstanding portfolio which shall not exceed five per cent of the amount of that loan portfolio. In case of implicit guarantee arrangements, the FLDG Provider shall not bear performance risk of more than the equivalent amount of five per cent of the underlying loan portfolio.

Applicability of Asset Classification, Income Recognition and Provisioning norms: The provision of Asset classification Income recognition and provisioning norms will be applicable as per extant guidelines. Recognition of individual loan assets in the portfolio as NPA and consequent provisioning shall be the responsibility of the Regulated Entity as per the extant asset classification and provisioning norms irrespective of any FLDG cover available at the portfolio level. The amount of FLDG invoked shall not be set off against the underlying individual loans. Recovery by the Regulated Entity, if any, from the loans on which FLDG has been invoked and realized, can be shared with the loan service provider in terms of the contractual arrangement.

Requirement of Regulatory Capital for the loan covered under FLDG: While calculating the required capital regulated entity should not reckon the availability of FLDG i.e., computation of exposure and application of Credit Risk Mitigation benefits on individual loan assets in the portfolio shall continue to be governed by the extant norms.

Other requirements with respect to FLDG:

Regulated Entities should have a Board approved policy before entering into any DLG arrangement. That policy shall include the following:

- Eligibility criteria for FLDG provider
- Nature and extent of DLG cover
- Process of monitoring and reviewing the DLG arrangement
- Details of the fees payable to the DLG provider

Regulated Entities shall ensure that all loan servicing, repayment, etc., shall be executed by the borrower directly in the Regulated Entities' bank account without any pass-through account/ pool account of any third party.

The disbursements shall always be made into the bank account of the borrower. REs shall ensure that in no case, disbursal is made to a third-party account, including the accounts of Loan Service Providers.

Regulated Entities shall provide a Key Fact Statement (KFS) to the borrower before the execution of the contract in a standardized format for all digital lending products. Reserve Bank of India has shared the format to be used for this purpose. The KFS shall, contain the details of Annual Percentage Rate (APR), the recovery mechanism, details of grievance redressal officer and the cooling-off/ look-up period. Any fees, charges, etc., which are not mentioned in the KFS cannot be charged by the REs to the borrower at any stage during the term of the loan.

Regulated Entities shall ensure that digitally signed documents (KFS, summary of loan product, sanction letter, terms and conditions, account statements, privacy policies of the LSPs shall automatically flow to the borrowers on their registered and verified email/ SMS upon execution of the loan contract/ transactions.

As per the Reserve Bank of India, the ultimate responsibility of Due diligence in digital lending lies with the lending institution and not with the lending service provider. However the primary selection of the borrower and lead generation lies with the lending service provider. For the purpose of selection of the borrower and lead generation, the lending service providers uses the digital and analytical tools available with them. By taking the First loss default guarantee from lending service provider, Lending Institutions want to ensure the basic due diligence in the selection of borrower and generation lead.

The recent development on First loss Default Guarantee is going to change the financial landscape of our country. The early bird benefit cannot be denied.

Dr. Deepak Kumar
U.L.A., Lucknow

Know Your Coin

You might have come across some social media posts as well as some newspaper articles where it was claimed that 5 rupees and 10 rupees coins of Sri Mata Vaishno Devi can give you the value of 10 Lakh to 20 Lakhs rupees or some old coins may make you a Lakhpati. Let us fund out the truth behind these claims.

Sri Mata Vaishno Devi coins were launched in 2012 in the denomination of Rs. 5 and Rs. 10 for general circulation. These coins do not have any premium on the face value.

Let us discuss more facts about the coins issued in India.

Commemorative coins Circulating coins and Circulating Commemorative Commemorative coins:

Commemorative coin is a coin issued to commemorate some particular event or issue with a distinct design with reference to the occasion on which they were issued. Many coins of this category serve as collector's items only, although some countries also issue commemorative coins for regular circulation.

Circulating coins are the coins which were minted by Reserve Bank of India for everyday transactions. 50 Paisa coin is the lowest circulating denomination of Indian Rupee. Other denomination in circulation are 1,2,5,10 and 20 rupees coin.

Circulating commemoratives coins are intended to be used for commerce, but the design will only be issued for a limited time to commemorate an event, anniversary, person or location, among other items.

Non-circulating legal tender (NCLT) are coins which are legal tender, and thus can be used to purchase goods or services, but are not intended to be used in such a manner. Rather, they are intended to be a collector's items with numismatic value, and are often produced in gold or silver, either in uncirculated condition or with a proof finish.

Proof and UNC coins

Proof Coins - Proof coinage refers to special early samples of a coin issue, historically made for checking the dies (as in demonstrating that something is true) and for archival purposes. Nowadays proofs are often struck in greater numbers specially for coin collectors (numismatists). Nearly all countries have issued proof coinage. Proof blanks are specially treated, hand-polished, and cleaned to ensure high-quality strikes. The blanks are then fed into presses fitted with specially polished dies and struck at least twice.

UNC coins are hand-loaded into the coining press and struck on specially burnished blanks, yet have a soft, matt-like finish appearance. These coins:

- Are made like circulating coins (which are used every day as money), but with a special process that produces a brilliant finish.
- Come with an official Certificate of Authenticity.

Mints in India : The India Government Mint operates four mints in the country for the production of coins:

- Mumbai, Maharashtra
- Kolkata, West Bengal
- Hyderabad, Telangana
- Noida, Uttar Pradesh

Under The Coinage Act, 1906, the Government of India is charged with the production and supply of coins to the Reserve Bank of India (RBI). The RBI places an annual indent for this purpose and the Government of India draws up the production programme for the India Government Mints on the basis of the indent.

The mint marks represent where the coins were minted or produced.

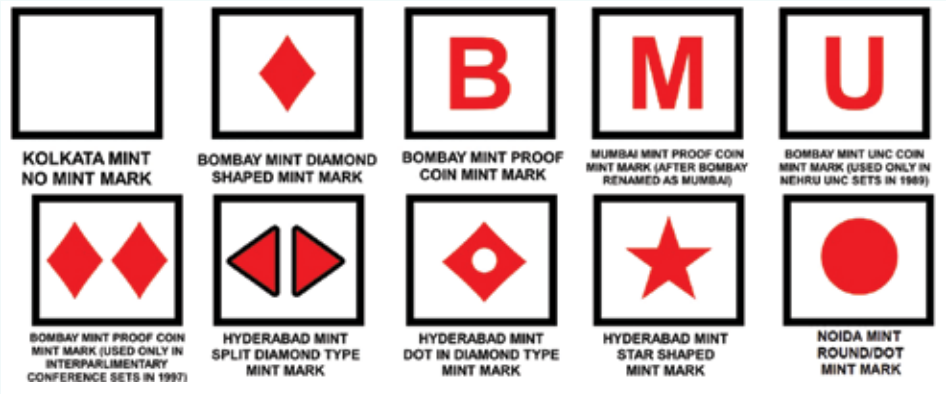

The mint mark is usually located just beneath the year.

Mumbai mint marks can be identified by one of the three mint marks:

- Diamond shaped mark below the date
- Letter 'B' below the date
- Letter 'M' below the date

Hyderabad mint marks can be identified by

- Split diamond below the date
- Dot in diamond below the date
- Star mark below the date

Noida mint has round dot mark below the year.

Kolkata mint does not have any mint mark.

Grading system of the coins

Coin grading is the process of determining the grade or condition of a coin, one of the key factors in determining its value. A "grade" measures a coin's appearance. There are generally five main components which determine a coin's grade: strike, surface preservation, luster, coloration and eye appeal. Grading is subjective and even experts disagree about the grade of a given coin.

As the collector market for coins grew rapidly in the late 19th and early 20th centuries, it became apparent that a more precise grading standard was needed. In 1948, well-known numismatist Dr. William Herbert Sheldon attempted to standardize coin grading by proposing what is now known as the Sheldon Scale.

SHELDON SCALE

Adjective	Design remaining	rading
Good (G-4)	10%	G
Very Good (VG-8)	25%	VG
Fine (F-12)	50%	F
Very Fine (VF-20)	75%	VF
Extremely Fine (EF-40, or XF-40)	90%	EF/XF
About Uncirculated (AU-50)	95% + some luster	UNC
Mint State (MS-60 to 64)	100% + luster	BU
Mint State (MS-65 to 70)	100% + full luster	FDC

How to buy and sell old coins

You can buy the coins at the following places –

- Whenever a new commemorative coin is issued by a mint, you can buy the Proof and UNC coin directly from the Mint online by logging into mint's website https://www.spmcil.com/ or https://www.indiagovtmint.in/
- You can visit the counters of RBI to get commemorative coins.
- You can buy old coins from online sites like OLX, eBay, coin bazaar etc.
- You can buy coins from well-known auction houses.

When it comes to selling of your old coins, always research the value of your coin and fix a fair price. It is always a good idea having your coins professionally graded and authenticated. You can sell the old coins/notes through commercial websites like OLX, eBAY, Snapdeal etc. Auctions Houses are the best place for selling coins. Selling through auction houses may take some time but these auction houses will give you the correct market price for your coin/note.

In India, there are many well-known Auction Houses such as:

- Todywalla Auction
- Bombay Auction
- Oswal Auction
- Marudhar Auction
- Virasat Auction

What makes a coin rare is not a fixed criterion. It all depends on demand and supply of the coin. Few factors which make a coin rare are as follows –

- Demand of the coin
- Mintage
- Error coin
- Age of the coin
- Condition of the coin
- Total coin minted.
- Coin now exists in very limited quantity.

Satendra Kumar Sharma
C.O., Annex,
Mangaluru

UDUPI SRI KRISHNA TEMPLE

Udupi Shri Krishna Temple is a sacred Hindu pilgrim destination in South India. Situated in the holy town of Udupi on the Arabian sea coast in Karnataka and founded in the 13th century by a Vaishnavite Saint and religious reformist Srila Madhvacharya, the Temple is considered highly significant to Krishna disciples and attracts thousands of devotees from different parts of the country, all year round.

ORIGIN OF THE NAME UDUPI: The name Udupi is derived from the combination of Sanskrit words 'Udu' meaning 'Stars' and 'Pa' meaning 'Lord'. 'Udupa' meaning, he who carries the moon on his head, means Lord Siva. Udupi thus also means the land of "Lord of the Stars" - Moon

SIGNIFICANCE OF UDUPI SRI KRISHNA TEMPLE

Krishna is delineated and worshipped in Udupi as the Bala Gopala, the most powerful form of worship in Krishnaism. Precisely for this reason, the Temple is known as Mathura of South India. Udupi attained the status of Vaikuntha, as it is believed that the Lord remained in Udupi, in response to the deep desire of Madhvacharya. Udupi is considered the final resting place of Lord. It is believed that impressed by the devotion of Kanakadas, who was denied entry into the Temple, Lord Krishna's idol turned from east to west to face him and a small hole was formed on the wall enabling Kanakadas to get a glimpse of the Deity. This hole is known as 'Kanakana Kindi', meaning window of kanaka. Even to this day Darshan of the Lord is through a grilled window known as the Navagraha Kitiki or Kanakana Kindi (Kanaka's window). The window has nine squares dedicated to the nine planets and is covered on all sides with silver plated carvings depicting the ten Avatars of Lord Vishnu.

TEMPLE HISTORY: The Udupi Temple is around 800 years old. Legend has it that the divine architect Vishwakarma created this sacred Idol of Krishna at the instance of Krishna's Consort Rukmini, who used to worship it in Dwaraka. Subsequent to Krishna's return to his heavenly abode, Arjuna deposited the idol in a place called Rukminivana which was lost in the sea during a massive flood that completely wiped-out Dwaraka. Centuries later a sailor from Dwaraka spotted a solid rock concealed in a large mass of clay and loaded it in his ship as a ballast. Later the ship was caught in a horrendous storm in the western coast of Malpe, and was safely brought ashore by Srila Madhvacharya, absorbed in composing 'Dvadasa -Stotra', with his divine power. The amazed Captain of the ship fell at Acharya's feet and offered him in return the lump covered in gopi-chandan clay, which later was found to be the beautiful Krishna Idol made of sandal wood. Madhvacharya purified the Idol in the nearby pond and installed it in the main Sanctum of the Matha for his worship. This pond later became

the famous Madhva Sarovar and the Sanctum Sanctorum, where the Idol was installed become the Udupi Temple.

TEMPLE ARCHITECTURE: Udupi Krishna temple is built in Dravidian architectural style on stone works with all essential features including the Sanctum Sanctorum where the Principal Deity of the Lord is housed. The main entrance is an arched pillar built of a large single stone accompanied by a four pillared spacious verandah and a mortified arch. Besides, the 9-holed silver-plated Kanakadasa attached to Chandrasala hall devotes itself to the sublime ambience created by the bells hanging over the arched entrance. The bricks structures in the Temple complex with terracotta tiles on roof and the wooden works on doors and windows add flavor to the traditional taste and style. The inner side of the Temple provides an auspicious feel with a centrally built large square shaped pond having a small Temple like structure in the middle with a cute bridge connecting to the main corridor. The rich stone art works in the structure, the attractive wooden marvels, and elegant motifs all around the Temple, make the internal ambience inviting.

The traditional Deepastambam that holds the sacred "Jyoti" is seen erected in the hall. Idols of Anjaneya, Panduranga, Lord Vishnu mounted on Garuda, holding conch and discus, all brought from Ayodhya, are installed in the hall. The holy tank Madhwapushkarani finds itself at the southern entrance. To the right of the main sanctum stands the statue of the Temple's founder, Shri Madhvacharya. Thus, on the whole, the Temple resembles a live Aashram.

PARYAYA UTSAVA: Udupi has eight Mathas collectively called "Ashta Mathas" which are centers of Dwaita Philosophy. Each Matha is headed by a Swamiji. These Mathas administer the Udupi Krishna Temple by way of a formal rotation model called "Paryaya" being held as a biennial event. The traditional Paryaya rituals start from early morning. The Swamiji of next Matha to take over temple management is taken in a palanquin in royal gala procession to the Temple, where he is given physical possession of the keys to the shrine by the Swamiji, currently in charge, symbolising transfer of rights to worship, control, and management of the Temple. Religious, durbar, shopping / food festivals etc., add to the grandeur of the celebrations. Udupi Paryaya tradition has been in practice for over 500 years.

A sequence of fourteen Poojas is performed to the Deity every day starting with the Nirmalya Visarjana in the pre-dawn hours of 5.30. In addition to this, a number of Sevas are offered to the God by devotees, some of them are Akhanda Saptotsava, Laksha Deepotsava, Maha Puja Rathotsava, Sarva Seva, Annadanam etc, making the atmosphere divine.

TEMPLE TIMING & DRESS CODE: Udupi Sri Krishna temple open & at 4.30 AM and closes at 9.30 PM. Devotees can wear any traditional ethnic dress.

BRAHMA RATHA: The Temple has two Chariots – wooden and golden. Sight of Golden Chariot with a golden horse statue pulling the chariot is considered auspicious. Devotees are allowed to see it during the traditional 'Saptotsava' event that is being celebrated to commemorate the installation of the Idol of Sri Krishna by Madhavacharya in the Temple, 800 years ago, on a Makara Sankranti Day.

Udupi Sri Krishna Temple is one of the seven Mukti Sthalas of Karnataka, the rest being Kollur, Subramanya, Kumbhashi, Kodeshwara, Sankaranarayana, and Gokarna. These seven Temples, built on land of Parashurama from the sea, together form the Parashurama Kshetras. Devotees believe that a holy trip to Udupi Krishna Temple is complete only after visiting the Anantheshwara and Chandramouleeshwara Temples which are older than Sri Krishna Temple and are situated next to it.

To sum up, Udupi should not be missed out from the list of sacred Temples to be visited, because it has been experienced by countless devotees that every visit to Udupi deepens our faith and every darshan of the Lord brings in a sense of security and spiritual feel in our hearts apart from eliciting positivity and enhancing our personal confidence.

Sreekala L.K.
DGM, C.O., Annex,
Mangaluru

सिलसिला यादों का

कहते हैं कभी कभी भावनाएँ किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के साथ इस कदर जुड़ जाती हैं कि दूसरा व्यक्ति उसकी सफलता या असफलता में स्वयं अपने को देखने लगता है. जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप में मौजूद हो. वह किस्से - कहानियों में भी हो सकता है.

बात उस समय की है जब मैं स्नातक का विद्यार्थी था और नौकरी के लिए पात्र होने के बाद पहली बार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (अब आईपीबीएस) के माध्यम से आवेदन किया था. लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार होना बाकी था. इस समय तक मेरा स्नातक पूर्ण हो चुका था.

एक दिन समाचार पत्र में मैं एक कहानी पढ़ रहा था. इस कहानी का पात्र बैंक की नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए घर से जा रहा है. रास्ते में वह यह सोच रहा है कि नौकरी के लिए उसका चयन होगा या नहीं. साक्षात्कार कैसा जाएगा आदि.

यहाँ पर जैसे-जैसे कहानी का किरदार आगे बढ़ता जाता है मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता जाता हूँ और उसकी सफल या असफल होने की धारणा मेरी अपनी धारणा होती जाती है कि यदि यह किरदार सफल होता है तो मैं भी सफल हो जाऊंगा नहीं तो मैं भी असफल हो जाऊंगा. मैं तुरंत कहानी का अंत नहीं देखता हूँ क्योंकि उसका भय और विश्वास अब मेरा भी भय और विश्वास बन चुका होता है.

यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि किसी कहानी के किरदार की सफलता या असफलता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की सफलता या असफलता के निर्धारण का पैमाना कदापि नहीं हो सकता है. एक पुरानी मूवी की चर्चा करता हूँ जिसमें नायिका अपने बीमार पति को अस्पताल में भर्ती करती है जहां उसके पति का ऑपरेशन किया जाना तय होता है. अस्पताल के उसी वार्ड में एक बच्ची का भी ऑपरेशन होना होता है. अब नायिका अपने पति के ऑपरेशन की सफलता या असफलता को बच्ची के ओपरेशन की सफलता या असफलता की धारणा बना लेती है. दुर्भाग्य से बच्ची का ओपरेशन सफल नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है. इस आधार पर नायिका डॉक्टर से अपने पति का ऑपरेशन कराने से मना करती है. डॉक्टर के बहुत समझाने पर वह अपने पति का ऑपरेशन कराती है जो सफल रहता है.

कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और मैं बड़ी ही गंभीरता से उसे पढ़ता जा रहा हूँ. किरदार अपने साक्षात्कार वाली जगह पहुंचता है जहां उसका साक्षात्कार प्रारम्भ होता है. मेरी स्थिति किरदार से अधिक खराब हो रही थी और उससे ज्यादा नर्वस मैं हो रहा था क्योंकि मैंने अपना भविष्य किरदार के भविष्य के साथ जोड़ लिया था.

खैर, उसका साक्षात्कार पूरा होता है और यह पता चलता है कि नौकरी के लिए उसका चयन कर लिया गया है. यह जानकार ऐसा लगा मानो मेरी नौकरी लग गई हो और मैं अपना साक्षात्कार तो जैसे भूल ही गया.

बाद में निर्धारित तारीख को मेरा भी साक्षात्कार होता है, मेरा भी चयन होता जिसमें मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आबंटित होता है.

सन्तोष कुमार श्रीवास्तव
सेवानिवृत्त,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

समझौता

सुचि सुबह से रो रही थी. उसके रोने से सब परेशान हो रहे थे.

संगीता को बैंक जाना था. ब्रांच में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी. घर के काम भी निपटाने थे.

संगीता के पति सौरभ मुम्बई में थे और संगीता दिल्ली में थी. नौकरी में स्थानांतरण चलता ही रहता है.

आखिर परेशान हो कर संगीता ने पूछा :

"बेटी आप रोती क्यों है? आपकी तबियत ठीक है न."

सुचि रोते हुए बोली :

"आप मेरे साथ नहीं रहती है, झूलाघर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा रोने का मन हो रहा है."

लेकिन संगीता समझ गयी कि सुचि को डांटने की नहीं समझाने की जरूरत है.

संगीता, सुचि को घर में बने चिडिया के घोंसले के पास ले गयी, जो अपने बच्चों को दानें ला ला कर खिला रही थी. संगीता बोली : "देखो सुचि ये कितने प्यारे बच्चे हैं और उनकी माँ कितने प्यार से दाना ला कर खिला रही है, और बच्चे भी खूब खुश हैं, जब उनकी माँ जाती है, तब ये बच्चे रोते तो नही हैं न. ऐसे मैं भी बैंक जाती हूँ. वहाँ जा कर काम करती हूँ और आपके लिए नयी नयी चीजें लाती हूँ, रोना अच्छी बात नहीं है."

सब समझ कर सुचि खुश हो गयी, और बोली "माँ मैं समझ गयी, आप हम बच्चों को कितना प्यार देती है, और हम ज़िद करते हैं और परेशान करते हैं. अब अगर यह चिडिया भी रूठ कर बैठ जाए तो ये बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे. अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, जो आप खिलाएंगी वह प्यार से खाऊँगी अब तो आप खुश हो न माँ. "सुचि की प्यारी-प्यारी बातों से संगीता की आँखों में आंसू आ गये. वह सोचने लगी, "कामकाजी महिलाओं के बच्चे कितनी जल्दी जीवन से समझौता कर लेते हैं" फिर सुचि को गले लगाकर बोली :

"हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा!"

संतोष श्रीवास्तव
सेवानिवृत्त,
एस.टी.सी., भोपाल

हमें गर्व है

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत आने वाली तिरुमला शाखा के श्री षैजु कुमार जे एस, प्रधान खजांचि एवं लिपिक की सुपुत्री सुश्री अर्चना एस आर, कक्षा- 12, आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन, तिरुवनंतपुरम ने 55वां केरल राज्य शूटिंग चैम्पियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता. उनको कुल 4 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए.

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में पदस्थ श्री शक्ति सिंह, कारोबार संबंध प्रबंधक के सुपुत्र विराज सिंह गहलोत ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एसओएफ़ अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड परीक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया.

क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद के अंतर्गत सबैस्टियन रोड शाखा के अधिकारी श्री एम. विनय कुमार ने गोवा में आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड रेटिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं साथ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया.

व्यंजन

सोयाबीन चिली

सामग्री - सोयाबीन - 50 ग्राम, प्याज-1, हरी मिर्च - 4, शिमला मिर्च - 1/2 पीस, हरी प्याज़ - 1/2, गाजर - 1, तेल - 100 ग्राम, जीरा - 1 चम्मच, अंडा - 1, लहसून अदरक पेस्ट - 2 चम्मच, काली मिर्च - 1/2 चम्मच, मक्के का आटा - 2 चम्मच, नमक (स्वाद अनुसार), सोया सॉस - 2 चम्मच, मिर्ची सॉस - 3 चम्मच, विनेगर - 2 चम्मच, धनिया पत्ता

बनाने की विधि - सबसे पहले पानी में थोडा सा नमक डालें और सोयाबीन को डाल कर उसे 2 मिनट उबाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड दें. अब प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटा-छोटा काट लें. सोयाबीन को अब पानी से निचोड लें. फिर उसमें अंडा, सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, मक्के का आटा और थोडा सा नमक डालकर अच्छा से मिलाएं. फिर उसे तेल में अच्छे से तल कर निकाल लें. फिर गैस पर पैन चढ़ाएं और उसमें तेल और जीरा डालें. फिर उसमें प्याज और गाजर को डाल कर थोडी देर भूनें. फिर उसमें शिमला मिर्च और नमक डाल कर थोडी देर भूनें. फिर उसमें सोया सॉस, टोमॅटो सॉस और वीनेगर डाल दें. उसके बाद सोयाबीन फ्राई को डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल कर उसे अच्छे से मिलाएं. अब उसमें धनिया पत्ता डालकर गैस को बंद कर दें. फिर उसे सर्विंग बॉउल में निकाल लें. अब हमारी सोयाबीन चिली बन कर तैयार है.

संदीप नथुराम बिरवाडकर
जोखिम प्रबंधन विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

समाचार केंद्र से

दिनांक 09.08.2023 को नई दिल्ली में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा लाभांश का चेक माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन को सौंपा गया. संयुक्त सचिव (बैंकिंग) श्री समीर शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

दिनांक 06.09.2023 को मुंबई में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै तथा एनपीसीआई की मुख्य परिचालन अधिकारी सुश्री प्रवीणा राय द्वारा एमपीरियो रुपे मेटल डेबिट कार्ड और रुपे एमपावर हर डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कार्ड जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है.

दिनांक 17.07.2023 को मुंबई में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै की अध्यक्षता और कार्यपालक निदेशकगण तथा उच्च कार्यपालकगण की गरिमामयी उपस्थिति में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रारंभ किए गए 'एमपावर हर' तथा 'पावर हिम' कार्यक्रमों का पहला वार्षिकोत्सव मनाया गया.

दिनांक 25.07.2023 को मुंबई में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै की अगुवाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत नए डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म को तैयार करने तथा डिजाइन करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मेसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई.

दिनांक 19.08.2023 को हैदराबाद में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई), सीसो कार्यालय का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर श्री के एम रेड्डी, सीसो उप महा प्रबंधक, अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

दिनांक 19.08.2023 को हैदराबाद में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर वर्टिकल प्रमुख श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल, महा प्रबंधक, श्री राकेश मेश्राम, उप महा प्रबंधक, अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

दिनांक 05.09.2023 को मुंबई में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास की उपस्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय सहायता के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

दिनांक 25.09.2023 को मुंबई में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ द्वारा मफ़तलाल केंद्र के 6वीं मंज़िल में केंद्रीय कार्यालय के कतिपय विभागों के नवीन परिसर का उद्घाटन किया.

दिनांक 11.09.2023 को अंचलीय ज्ञानार्जन केंद्र, हैदराबाद में आयोजित जोखिम अधिकारी सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री रामसुब्रमणियन एस, कार्यपालन निदेशक. मंचासीन हैं श्री अश्विनी कुमार चौधरी, मुख्य जोखिम अधिकारी.

दिनांक 08.09.2023 को मुंबई में श्री सी एम मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और श्री शकील खान, मुख्य जोखिम अधिकारी, वास्तु हाउसिंग फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते का उद्देश्य बैंक के लिए एक गुणवत्तापूर्ण एम.एस.एम.ई. उधार पोर्टफोलियो बनाना है.

समाचार (उत्तर)

दिनांक 08.09.2023 को इंदौर में आयोजित मेगा रीटेल एक्स्पो में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, श्री राजीव मिश्रा, श्री बिरजा प्रसाद दास, अंचल प्रमुख भोपाल, उप अंचल प्रमुख श्री वेद प्रकाश अरोरा, उप अंचल प्रमुख श्री नीरज सिंह एवं अन्य कार्यपालकगण की उपस्थिति में उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया.

दिनांक 26.08.2023 को लखनऊ में आयोजित मेगा रीटेल एक्सपो में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक तथा श्री मार्कन्डेय यादव, क्षेत्र प्रमुख की उपस्थिति में उधारकर्ताओं को ऋण संवितरण किया गया.

दिनांक 28.07.2023 को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, मऊ को पुरस्कार प्रदान किया गया.

दिनांक 29.08.2023 को भोपाल में श्री नितेश रंजन कार्यपालक निदेशक द्वारा किसानों से भेंट की गयी, साथ ही केसीसी एसटीपी पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी. उनके द्वारा किसानों को डेबिट कार्ड भी प्रदान किए गए.

दिनांक 10.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, बठिंडा द्वारा नाभा में श्री अरुण कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ और श्री आशीष सुवालका, क्षेत्र प्रमुख, बठिंडा द्वारा कृषि संरचना निधि योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ऋण संवितरण किया गया.

दिनांक 08.09.2023 को मनेर शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित आउटरीच ऋण शिविर के अवसर पर अपने कर-कमलों से लाभार्थी को ऋण स्वीकृति का चेक सौंपते हुए श्री अरुण कुमार, महाप्रबंधक (मा.सं.) तथा श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख, रांची साथ में श्री राजेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख, पटना अन्य गण-मान्य गण.

दिनांक 25.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'अब नारी की बारी अभियान' के अंतर्गत श्री अरुण कुमार, महाप्रबंधक द्वारा 50 महिला उद्यमकर्ताओं ऋण मंजूरी पत्र प्रदान किया गया. साथ हैं श्री गोविंद मिश्र, क्षेत्र प्रमुख, नई दिल्ली तथा अन्य कार्यपालकगण.

दिनांक 16.09.2023 एवं 17.09.2023 को श्री कबीर भट्टाचार्य, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में दिल्ली अंचल द्वारा संयुक्त रूप से 'मेगा रीटेल एक्स्पो' का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया. साथ हैं उप अंचल प्रमुख और क्षेत्र प्रमुख तथा अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य.

दिनांक 12.09.2023 को भागलपुर क्षेत्र के श्री गुणानन्द गामी, महाप्रबंधक तथा श्री इश्तियाक अरशद, क्षेत्र प्रमुख के नेतृत्व में भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में मेगा एसएचजी ऋण शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में 75 आजीविका स्वयं सहायता समूह को कुल दो करोड़ दस लाख रुपए का ऋण संवितरित किया गया.

दिनांक 28.08.2023 को दुमका में कृषि व स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख, राँची, श्री मुकेश कुमार- क्षेत्र प्रमुख-धनबाद, द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण मंजूरी चेक प्रदान किया गया.

स्वर्ण ऋण में लखनऊ अंचल द्वारा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक को केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त शील्ड भेंट करते हुए उप अंचल प्रमुख श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, श्री प्यारेलाल एवं गोल्ड लोन नोडल अधिकारी सुश्री अंकिता श्रीवास्तव.

दिनांक 07.08.2023 को आई आई टी, बीएचयू में प्रवेश ले रहे छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा देने के लिए अंचल प्रमुख श्री गिरीश जोशी की उपस्थिति में आयोजित विशेष कैंप में 50 से अधिक छात्रों के ऋण अनुमोदित किए गए.

दिनांक 14.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के क्षेत्राधीन दिबियापुर शाखा का उदघाटन किया गया. इस अवसर पर श्री सुमित श्रीवास्तव अंचल प्रमुख, श्री अमित कुमार सिन्हा क्षेत्र प्रमुख, श्री निर्भय नारायण सिंह उप क्षेत्र प्रमुख एवं शाखा कार्यालय के स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे.

मऊ क्षेत्र की मधुबन शाखा के नवीन परिसर का उद्घाटन दिनांक 26 सितंबर, 2023 को क्षेत्र प्रमुख श्री मिथिलेश कुमार जी द्वारा किया गया.

समाचार (पूर्व)

दिनांक 22.08.2023 को श्री ऋषिकेश मिश्र, एल & डी विभाग प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के सभी स्टाफ एवं शाखाओं से मुख्य प्रबंधक को संबोधित किया गया.

जुलाई 2023 माह के लिए प्रोजेक्ट पावर के तहत पहचान किए गए आकांक्षी जिला खुर्दा के शाखाओं में बेहतरीन कार्यनिष्पादन हेतु श्री जीएन दास, महाप्रबंधक, श्री सर्वेश रंजन, अंचल प्रमुख तथा श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख द्वारा विजेता शाखा एवं रनर-अप शाखा को रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई.

दिनांक 21.09.2023 को बस्ता शाखा का उदघाटन करते हुए श्री सर्वेश रंजन, अंचल प्रमुख, भुवनेश्वर. साथ में हैं श्री जयगोपाल बेहेरा, क्षेत्र प्रमुख, बालेश्वर तथा श्री शशिकांत शिअल शाखा प्रमुख, बस्ता शाखा.

दिनांक 21.07.2023 को श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख, भुवनेश्वर तथा विद्यालय के प्राचार्य श्री सत्यजित मिश्र द्वारा केंद्रीय विद्यालय 5, भुवनेश्वर के परिसर में पौधारोपण किया गया.

दिनांक 28.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के परिसर में आयोजित एम.एस.एम.ई. आउटरिच कैम्पेन में श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख तथा कार्यपालकों द्वारा ग्राहकों को मंजूरी पत्र वितरित किए गए.

दिनांक 21.09.2023 को खइरा शाखा का उदघाटन करते हुए श्री सर्वेश रंजन, अंचल प्रमुख, भुवनेश्वर, श्री जयगोपाल बेहेरा, क्षेत्र प्रमुख, बालेश्वर तथा श्री जय कृष्ण राउत, शाखा प्रमुख, खइरा शाखा.

दिनांक 27.09.2023 को श्री जयगोपाल बेहेरा, क्षेत्र प्रमुख, बालेश्वर की अध्यक्षता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भुवनेश्वर के साथ एम.एस. एम.ई. हेतु विपणन एवं ऋण सुलभता सेवा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया.

दिनांक 21.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, रायगड़ा द्वारा कासा अभियान माट्टीकौन गांव में आयोजित किया गया, जिसमें उप क्षेत्र प्रमुख श्री कुबेर माझी जी, जे. के. रोड, रायगड़ा के शाखा प्रमुख श्री अनिल माझी एवं विपणन अधिकारी श्री पंकज कुमार साहु उपस्थित रहे.

समाचार (पश्चिम)

दिनांक 01.08.2023 को क्षे.का मुंबई दक्षिण द्वारा मेगा आउटरिच अभियान का आयोजन किया गया. श्री सी.एम मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री योगेंद्र सिंह, अंचल प्रमुख, मुंबई तथा श्री विजय कुमार, क्षेत्र प्रमुख, मुंबई दक्षिण द्वारा ग्राहकों को सांकेतिक चेक प्रदान करते हुए.

दिनांक 06.09.2023 को यूनियन लर्निंग अकादमी डिजिटल ट्रान्स्फ़ोर्मेशन, पवई में "स्मार्ट क्लासरूम" का उद्घाटन श्री अरुण कुमार, महाप्रबंधक (मासं) द्वारा श्री हृषिकेश मिश्रा प्रमुख- एल एंड डी तथा डॉ. चेतना पाण्डे, उप महाप्रबंधक(मा.सं) की उपस्थिति में संपन्न हुआ.

दिनांक 21.07.2023 को भायखला डिजि - मंडी का उद्घाटन श्री योगेंद्र सिंह, अंचल प्रमुख, मुंबई द्वारा किया गया. साथ हैं सुश्री सौम्या श्रीधर, उप अंचल प्रमुख, श्री विजय कुमार, क्षेत्र प्रमुख, मुंबई(द), श्री समीरन रॉय चौधुरी, उप क्षेत्र प्रमुख, मुंबई (द) उपस्थित रहे.

दिनांक 07.09.2023 को असदपुर में आयोजित आउटरीच कैंपेन में श्री मनोज कुमार, महाप्रबंधक तथा श्री अनूप तराले, क्षेत्र प्रमुख द्वारा ग्राहकों को ऋण मंजूरी के सांकेतिक चेक प्रदान किया गया.

दिनांक 08.09.2023 को आउटरीच कैंप के अंतर्गत श्री प्रफुल्ल कुमार सामल, मुख्य वित्तीय अधिकारी स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए. साथ में क्षेत्र प्रमुख श्री आशीष मालवीथ तथा उप क्षेत्र प्रमुख श्री अजय कुमार.

दिनांक 05.08.2023 को निजामपुरा शाखा, वडोदरा में रीटेल आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया जिसमें श्री ऋषिकेश मिश्रा, प्रमुख-एल एंड डी तथा श्री प्रशांत एम देसाई, क्षेत्र प्रमुख द्वारा ऋण मंजूरी पत्र वितरित किए गए.

दिनांक 03.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अंतर्गत कृषि लोन पॉइंट का उदघाटन श्री एम वी एन रवि शंकर, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया. साथ हैं श्री राजेश यादव तथा श्री एम शिवकुमारण, उप क्षेत्र प्रमुख और स्टाफ सदस्य.

दिनांक 21.07.2023 को बड़ौदा में श्री विट्ठल बनशंकरी, अंचल प्रमुख गांधीनगर, श्री प्रशांत एम देसाई, क्षेत्र प्रमुख बड़ौदा एवं अन्य कार्यपालकगण की उपस्थिति में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

दिनांक 16 एवं 17.09. 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा श्री एम वी एन रवि शंकर, क्षेत्र प्रमुख एवं श्री गौरव अग्रवाला, क्रेड़ाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में रिटेल एक्स्पो का आयोजन किया गया.

दिनांक 24.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा डबल्यू सी एल, उमरेड कोलियरी के स्टाफ सदस्यों के लिए ग्राहक जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख श्री एम वी एन रवि शंकर, डबल्यू सी एल, उमरेड कोलियरी के सभी यूनियन के अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे.

समाचार (दक्षिण)

दिनांक 11.09.2023 को प्रबंध निदेशक व सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै ने स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूरु परिसर में "यूनिवर्सिटी पोर्टल" तथा नव निर्मित "यूनियन स्टूडियो" का लोकर्पण किया. इस अवसर पर श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मासं), श्री जी.एन. दास, महाप्रबंधक (मासं), श्री हृषीकेश मिश्र, प्रभारी, ज्ञार्नाजन एवं विकास (मासं) तथा डॉ. चेतना पाण्डेय, उप महाप्रबंधक (मासं) भी उपस्थित रहें.

दिनांक 19.08.2023 को हैदराबाद में आयोजित मेगा रीटेल एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलै. साथ हैं श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद तथा अन्य कार्यपालकगण.

दिनांक 27.07.2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर गतिविधियों के तहत प्रियदर्शनी चिल्ड्रन्स पार्क, एर्णाकुलम का विधिवत् उद्घाटन करते हुए श्री टी जे विनोद, सासंद सदस्य. साथ में उपस्थित हैं श्री एन.एस.के उमेश, जिला कलेक्टर तथा श्री आर नागराजा, क्षेत्र प्रमुख, एर्णाकुलम क्षेत्र.

दिनांक 07.09.2023 और 08.09.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुंटूर द्वारा आयोजित मेगा आउटरीच कार्यक्रम में श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक, (आई टी), श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख और श्री कुन्दन लाल, क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे.

दिनांक 15.09.2023 को पीण्या में आयोजित एम.एस.एम.ई., आउटरीच कार्यक्रम में श्री बिजू वासुदेवन, अंचल प्रमुख, बेंगलूरु अंचल श्री राजेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु उत्तर, श्री कनकराजू सी. एमएलपी प्रमुख, बेंगलूरु उत्तर उपस्थित थे.

दिनांक 20.07.2023 को आयोजित ग्राहक बैठक रायचूर में श्री बिजू वासुदेवन, अंचल प्रमुख, बेंगलूरु अंचल व श्री सी.वी. सुधीर, क्षेत्र प्रमुख उपस्थित ग्राहकों से चर्चा करते हुए.

दिनांक 11.09.2023 को खम्मम में कल्लूर शाखा के शाखा प्रमुख, श्री आनंद भास्कर को श्री रवींद्र बाबु, महाप्रबंधक, कें.का के कर कमलों से श्री ए हन्मंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री एस प्रकाश बाबु एवं श्री टी वी सुंदर कृष्णा, उप क्षेत्र प्रमुख, की उपस्थिति में रोलिंग ट्रॉफी प्रदान किया गया.

दिनांक 25.07.2023 को श्री अजय कुमार, महा प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित मेगा आउटरीज कार्यक्रम में श्री बिजू वासूदेवन, अंचल प्रमुख, बेंगलूरु, श्री राजेश मिश्रा, उप अंचल प्रमुख एवं श्री असीम कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 04.08.2023 को श्री रूपलाल मीना, महा प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया गया. उनका स्वागत करते हुए श्री असीम कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख और कार्यपालकगण एवं शाखा प्रमुख.

दिनांक 20.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शुर की अधीनस्थ शाखाओं की समीक्षा बैठक में 10 मिलियन एवं 20 मिलियन स्वर्ण ऋण वितरण करने वाली शाखाओं के शाखा प्रमुखों को क्षेत्र महाप्रबंधक मंगलूरू श्रीमती रेणु के नायर ने शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. साथ हैं क्षेत्र प्रमुख श्री टी एस श्याम सुंदर तथा उप क्षेत्र प्रमुख श्रीमती प्रीति रामचन्द्रन.

दिनांक 01.09.2023 को श्रीमती रेणु नायर, महा प्रबंधक द्वारा मुलवुक्काड एटीएम का विधिवत् उद्घाटन.

दिनांक 31 07.2023 को कलबुरगी क्षेत्र की व्यापार समीक्षा बैठक में शाखा प्रबंधकों को पुरस्कार वितरण करते हुए क्षेत्र प्रमुख श्री सी.वी सुधीर.

दिनांक 04.09.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक में शाखा प्रमुखों को संबोधित करते हुए श्री असीम कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख. साथ हैं श्री रोहन कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख एवं श्री गुरूप्रसाद, उप क्षेत्र प्रमुख, कार्यपालकगण एवं शाखा प्रमुख.

दिनांक 02.09.2023 को एर्णाकुलम में आयोजित एनआआई मीट का उद्घाटन करती हुई श्रीमती रेणु नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूरु.

दिनांक 08.09.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, कलबुरगी द्वारा आयोजित ग्राहक बैठक के दौरान क्षेत्र प्रमुख श्री सी.वी सुधीर, श्री मोहन दास उप महाप्रबंधक केन्द्रीय कार्यालय और उप क्षेत्र प्रमुख श्री एस जी राजकुमार.

दिनांक 19.08.2023 को लिगसुगुर शाखा के नये परिसर का उद्घाटन करते हुए क्षेत्र प्रमुख श्री सी.वी सुधीर.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसईटीआई, मछलीपट्टनम में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधा लगाते क्षेत्र प्रमुख श्री. के. वेंकट राव, उप क्षेत्र प्रमुख, श्री. एस. संतोष, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी श्री. के. वेंकट राजू, मुख्य प्रबंधक (परिचालन) श्री. जी. प्रसन्ना राजू व क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्य.

"यूनियन धारा" जनवरी-मार्च 2023 अंक की रुपरेखा एवं साज-सज्जा अत्यंत ही आकर्षक है. आपने इसमें बैंकिंग विषयों के अतिरिक्त अन्य समसामयिक विषयों को शामिल किया है जो पत्रिका के इस अंक में निहित रोचक लेखों से यह स्वत: ही स्पष्ट हो रहा है. "यूनियन धारा" पत्रिका के इस अंक से निश्चित ही सभी पाठकगण लाभांवित होंगे. इस पत्रिका के बेहतरीन एवं रोचक अंक के प्रकाशन हेतु आपको एवं आपके पूरे संपादक मंडल को हार्दिक बधाई.

ई रमेश
सहा महाप्रबंधक (राजभाषा) केनरा बैंक,
राजभाषा अनुभाग, मा. सं. वि.,
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

आपके प्रधान कार्यालय की तिमाही गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' के 'अप्रैल-जून, 2023' अंक की प्रति प्राप्त हुई. इस विशेषांक में समसामयिक विषय 'अमृत काल' को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत एवं समाहित किया गया है. विषय विविधता के साथ गहन ज्ञानवर्धन और पाठकों को जोड़ने की इस अंक में विशिष्ट क्षमता निहित है. कौशल विकास में बैंकों का योगदान, अमृत काल और बैंकिंग क्षेत्र, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बैंकिंग, विजन 40 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, अमृत काल में भारतीय भाषाएं, Digital Transformation for Eco-Innovation Deewj Importance of Green Revolution in sustainable development जैसे लेख पत्रिका को उत्कृष्ट बनाते हैं. विविध पाठकवर्ग को ध्यान में रखते हुए यात्रा, योग, कविता रस, व्यंजन, कार्य अनुभव, उपलब्धियां, अद्यतित बैंकिंग सूचनाएं आपकी पत्रिका में बखूबी प्रस्तुत की गई है. साथ ही समाचार संग्रह खंड के अंतर्गत उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सम्पूर्ण क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से सम्मिलित किया गया है. पत्रिका के सफल संपादन हेतु आपको और आपके संपादक मंडल को हार्दिक बधाई तथा आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं, आशा है कि आगे भी हमें आपकी पत्रिका के ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक अंक प्राप्त होते रहेंगे.

मनीषा शर्मा
सदस्य सचिव, दिल्ली बैंक नराकास
तथा सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.), पंजाब नैशनल बैंक

'यूनियन धारा' अप्रैल-जून, 2023 (अमृतकाल और बैंकिंग विशेषांक) प्राप्त हुई, सादर धन्यवाद. द्विभाषी पत्रिका होने के कारण निश्चित रूप से यह एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुँची होगी. अमृतकाल और बैंकिंग विशेषांक होने के कारण इसके लेख मुख्य रूप से अमृतकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता, नारी, भाषा आदि पर आधारित है जिसने विशेषांक प्रकाशन के उद्देश्यों को पूर्ण किया है. लेखों का चयन पूर्णत: न्यायोचित है. सेवानिवृत जीवन तथा व्यंजन और हेल्थ टिप्स जैसे आलेखों ने पत्रिका को विविधता प्रदान की है. समग्र रूप से पत्रिका मेरे मन में सकरात्मक प्रभाव छोड़ने में सफल हुई है.
पत्रिका के लिए मुद्रण सामग्री प्रदान करने वाले समस्त लेखकों को साधुवाद. आशा है कि यह पत्रिका भविष्य में भी उच्च मानदंडों के साथ निरंतर प्रकाशित होकर बैंकिंग ही नही अपितु अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान हो प्रवाहित करेगी.

गौरव पाण्डेय
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
चेरूतुरूति, तृश्शूर (नराकस तृश्शूर सदस्य)

हमें यूनियन बैंक की गृह पत्रिका "यूनियन धारा" के नवीनतम अंक अप्रैल-जून 2023 (अमृतकाल और बैंकिंग विशेषांक) की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद. पत्रिका का नवीनतम अंक अमृत काल और बैंकिंग विशेषांक पर आधारित है जो कि निश्चित रूप से हम सभी हेतु पठनीय एवं उपयोगी है. पत्रिका में आज के समय में प्रासंगिक आलेखों का समावेशन एवं बखूबी प्रस्तुतीकरण किया गया है. पत्रिका में बैंक की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी समावेश किया गया है जो प्रशंसनीय है. कृपया हमारी बधाई स्वीकार करें तथा पत्रिका प्रकाशन में जुड़ी टीम को हमारा सराहना भाव पहुंचाएं.

अजय एन चोक्सी
उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद अंचल

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की पत्रिका यूनियन धारा का यह अंक विशेष रूप से हमारे देश के अमृत काल को समर्पित है. यह जानकर मुझे एक सुखद अनुभूति हुई. कृषि बैंकिंग के विषय में लेख पढ़कर ऐसा महसूस हुआ जैसे इसपर बहुत ही गहन अध्ययन व विश्लेषण किया गया है. मांडू जैसे पर्यटक स्थल पर आधारित लेख भी बहुत ही अच्छा लगा और उसमें वहां के छायाचित्रों का बेहतरीन उपयोग किया गया है. मेरे सपनों का भारत व अन्य कविताएं बड़ी अच्छी लगीं. अंग्रेज़ी की कविताएं भी उच्च स्तरीय हैं. कुल मिलाकर यूनियन धारा का अमृत काल और बैंकिंग विशेषांक गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है. इस विशेष उपलब्धि पर आपको हार्दिक बधाई.

अभिषेक कुमार
राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया, चेन्नई अंचल

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे का निरीक्षण 12.09.2023

संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भतृहरि महताब के कर कमलों से सफल निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक इंडिया और श्रीमती एस जननी, क्षेत्र प्रमुख, ठाणे. साथ हैं डॉ अभिजीत फुक्कन, आर्थिक सलाहकार श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं.), श्री योगेंद्र सिंह, अंचल प्रमुख, मुंबई, श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मा. सं.), श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (रा. भा.), श्री सुधाकर खापेकर, मुख्य प्रबंधक (राभा), श्री सुधीर भोला कृष्ण प्रसाद, व. प्र. (राभा), श्री सर्वेश कुमार मिश्र, सहायक निदेशक (राजभाषा) वित्त मंत्रालय.

संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे का संदर्भ साहित्य "शाखा / कार्यालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन" का विमोचन किया गया.

संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य डॉ अमी याज्ञिक और श्रीमती कान्ता कर्दम ने यूनियन बैंक इंडिया की प्रदर्शनी स्टाल का वीक्षण किया गया.

हाटू पीक, नारकंडा, शिमला
रीता देवी
क्षे. का., शिमला

Union Dhara, R.N 27989/76

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, 239, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Editor - Gayathri Ravi Kiran.